



हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (एचआईपीए), शिमला

सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई, हिमाचल प्रदेश सरकार



कार्यसूची रिपोर्ट

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

तथा

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

लूहरी जल विद्युत परियोजना के लिए स्वीकृत होने वाली

भूमि - स्टेज 2

इसके अनुसार

“हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार  
(सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2015



अक्टूबर-2019



**Abnaki Infrastructure Applications and Integrated Development  
Private Limited**

JG-11, Second Floor, Khirki Extension, Malaviyanagar, New Delhi 110017

अध्याय	विवरण	
	विशेष सारांश	I
a.	परियोजना और सावर्जनिक उद्देश्य	I
a.1	परियोजना के उद्देश्य	I
a.2	सेवाओं का दायरा	II
b.	लोकेशन/स्थान	III
c.	भूमि अधिग्रण का आकार और विशेषताएं	IV
d.	विचार किये गये विकल्प	IV
e.	सामाजिक प्रभाव	V
e.1	सैम्पलिंग कार्यप्रणाली(मेथडालजी)	VI
e.2	भूमि पर प्रभाव	VII
f.	गंभीरता को कम करने के उपाय	X
f.1	सामुदायिक विकास कार्य	X
f.2	कमजोर और सामाजिक रूप से पिछड़े परिवार	X
f.3	पीएएफ के लिए मुफ्त बिजली	X
f.4	स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ)	X
g.	सामाजिक लागतों और लाभों का आकलन	XI
h.	समापन टिप्पणियां	XI
1.	परियोजना का विस्तृत विवरण	1
1.1	परिचय	1
1.1.1	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	1
1.1.2	परियोजना का उद्देश्य	2
1.1.3	सेवाओं का दायरा	3
1.1.4	परियोजना क्षेत्र	3
1.1.5	डिवलेपर्स की पृष्ठभूमि और प्रबंधन संरचना	4
1.2	परियोजना के लिए तर्क	4
1.3	परियोजना का विवरण	5
1.3.1	परियोजना का साइज़ और स्थान	5
1.3.2	उत्पादन लक्ष्य और लागत के साथ परियोजना की क्षमता और आउटपुट	6
1.4	विकल्पों की परीक्षा	6
1.5	परियोजना निर्माण के चरण	7
1.6	मुख्य डिजाइन की विशेषताएं और सुविधाओं के साइज़	8

1.7	सहायक संरचनाओं की आवश्यकता	13
1.8	शुरूवाती सामाजिक प्रभाव आकलन का विवरण	13
2	टीम की संरचना का दृष्टिकोण, कार्य पद्धति और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की अनुसूची	14
2.1	परिचय	14
2.2	योग्यता के साथ टीम के सदस्यों की सूची	14
2.3	सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए जानकारी एकत्र करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कार्य पद्धति और टूल के लिए विवरण और तर्क	15
2.3.1	सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) प्रक्रिया के लिए दृष्टिकोण और पद्धति	16
2.4	नमूना लेने के लिए पद्धति	23
2.4.1	नमूना कवरेज	24
2.5	सूचना/डेटा स्रोतों का अवलोकन	24
2.6	प्रमुख स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श की अनुसूची	25
2.6.1	पृष्ठभूमि	25
2.6.2	सार्वजनिक परामर्श का उद्देश्य	25
2.6.3	सार्वजनिक परामर्श का दायरा	26
2.6.4	कार्यपद्धति और प्रक्रिया	26
2.6.5	हितकारक	26
2.7	जन सुनवाई का विवरण	34
3	भूमि का आकलन	35
3.1	परिचय	35
3.2	भूमि सूची और डेटा संगृहीत का प्राथमिक स्रोत	36
3.3	कुल आवश्यक ज़मीन	37
3.4	परियोजना क्षेत्र के आसपास में किसी भी सार्वजनिक, अप्रयुक्त भूमि का वर्तमान उपयोग	37
3.5	भूमि (यदि कोई) पहले से ही खरीदी गई, दान की गई, पट्टे पर या अधिग्रहित की गई, और परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के प्रत्येक प्लॉट के लिए इच्छित उपयोग	38
3.6	परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान	38
3.7	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का प्रकृति, उपयोग और वर्गीकरण	39
3.7.1	सिंचाई क्षेत्र	39
3.7.2	फसल का पैटर्न	40
3.7.3	भूमि पर लगे वृक्षों का अधिग्रहण किया जाना	40

3.8	अधिकार का आकार और स्वामित्व का तरीक, भूमि वितरण और आवासीय घरों की संख्या	40
3.9	भूमि की कीमतें और हाल ही में भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन और पिछले 3 सालों में भूमि का उपयोग	40
4.	प्रभावित परिवारों और संपत्तियों का आकलन और गणना	42
4.1	सीधे तौर पर प्रभावितहोने वाली भूमि	42
4.1.1	क्या किरायेदारी या निवास वाली भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है	42
4.1.2	अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी जो अपने किसी भी वन अधिकार को खो चुके हैं	42
4.1.3	सामान्य संपत्ति संसाधनों पर निर्भर हैं जो उनकी आजीविका के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित होंगे	43
4.1.4	राज्य सरकार द्वारा अपनी किसी भी योजना के तहत भूमि सौंपी/ निर्दिष्ट की गई है और ऐसी भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत है	43
4.1.5	शहरी क्षेत्रों में अधिग्रहित की जाने वाली किसी भी भूमि पर तीन साल या उससे पहले से पहले निवास कर रहे हैं	43
4.1.6	अधिग्रहण से पहले तीन साल तक आजीविका के प्राथमिक स्रोत के रूप में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर निर्भर है	43
4.2	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भूमि के अधिग्रहण से सीधे प्रभावित नहीं हुआ	43
4.3	उत्पादक संपत्ति और महत्वपूर्ण भूमि की सूची	43
5	सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वास स्थल))	45
5.2	परियोजना क्षेत्र की जनसंख्या संबंधी प्रोफ़ाइल	45
5.2.1	लिंग के अनुसार जनसंख्या	45
5.2.2	सामाजिक श्रेणियां	45
5.2.3	धर्म के अनुसार जनसंख्या	46
5.2.4	ग्रामीण और शहरी जनसंख्या वितरण	47
5.5	भूमि का उपयोग और आजीविका	55
5.6	कृषि और गैर-कृषि उपयोग	56
5.6.2	बागवानी	57
5.6.3	पशुधन	57
6	सामाजिक प्रभाव	74
6.1	परिचय	74
6.2	प्रभावों की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण	74
6.2.1	एनालिटिकल टूल	75
6.2.2	परामर्श की विधियां	75

6.2.3	निरीक्षण और इंटरव्यू टूल	75
6.3	परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण। प्रत्यक्ष प्रभाव, अप्रत्यक्ष प्रभाव और संचयी प्रभाव	76
6.3.1	स्वास्थ्य पर प्रभाव	76
6.3.2	संस्कृति और सामाजिक एकता पर प्रभाव	77
6.3.3	भूमि पर प्रभाव	77
6.3.4	आजीविका और आय पर प्रभाव	77
6.3.5	भौतिक संसाधनों पर प्रभाव	79
6.3.6	निजी संपत्तियों पर प्रभाव	79
6.3.7	सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव	80
6.3.8	लिंग आधारित प्रभाव	80
7	अधिग्रहण पर लागत और लाभ और गणों का विश्लेषण	82
7.1	परिचय	82
7.2	अंतिम निष्कर्ष	82
7.2.1	सार्वजनिक उद्देश्य का आकलन	82
7.2.2	भूमि के कम स्थानंतरण और न्यूनतम आवश्यकता के लिए वैकल्पिक	83
7.2.3	सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता	83
7.2.4	गंभीरता को कम करने वाले सुझाव	84
7.3	मूल्यांकन मानदंड और काल-चक्र	86
7.3.1	आउटपुट	86
7.3.2	परिणाम	87
7.4	अंतिम सिफारिशें	88
	सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना	90
1	गंभीरता को कम करने के लिए दृष्टिकोण	90
2	प्रभाव से बचने, उसे कम करने और क्षतिपूर्ति करने के लिए उपाय	92
3	उपाय जो अधिनियम में बताए गये पुनर्वास और मुआवजे की शर्तों में शामिल हैं	93
4	अतिरिक्त उपाय जो आवश्यक निकाय ने कहा है यह सामाजिक प्रभाव आकलन प्रक्रिया और सार्वजनिक सुनवाई के निष्कर्षों के जवाब में कार्य करेगा	94

No.	टेबल	
1.1	परियोजना से प्रभावित होने वाला भूमि क्षेत्र और जिला वार प्रभावित परिवार	3
1.2	डैम ब्लॉक्स का विवरण	8
1.3	परियोजना की मुख्य विशेषताएं	10
2.1	प्रोजेक्ट स्टडी टीम	14
2.3	Collect बेसलाइन प्राथमिक मापदंड और उनका विवरण	20
2.4	प्राथमिक सर्वे के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल्स	21
2.5	डेटा स्रोत	24
2.6	परामर्श का सारांश	27
3.1	उप-मंडलों, तहसीलों	36
3.2	गांवों, तहसीलों और जिलों की संख्या	36
3.3	घटकों द्वारा एलएचईपी स्टेज -II के लिए आवश्यक भूमि	37
3.4	भूमि अधिग्रहण के कारण सीधे प्रभावित हुए प्राइवेट भूमि मालिकों की संख्या	38
3.5	अधिग्रहण की जाने वाली सरकारी भूमि	38
3.6	परियोजना के आवश्यक प्राइवेट भूमि का वर्गीकरण	39
3.7	प्राइवेट भूमि पर आने वाले पेड़ों की गणना सूची	41
4.1	निजी भूमि के मालिकों की संख्या जो भूमि अधिग्रहण के कारण सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं	42
4.2	फल देने वाले पेड़	44
5.1	जिलों के प्रशासनिक डिविजन्स	45
5.2	लिंग के अनुसार जनसंख्या	46
5.3	परियोजना प्रभावित गांवों में लिंग के अनुसार जनसंख्या	46
5.4	सामाजिक श्रेणी के अनुसार जनसंख्या	47
5.5	सामाजिक श्रेणी के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवार	47
5.6	धर्म के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत	48
5.7	धर्म के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवार	48
5.8	ग्रामीण और शहरी जनसंख्या वितरण	49
5.9	लिंग के अनुसार साक्षरता दर	49
5.10	हिमाचल प्रदेश में वयस्कों (उम्र 15-49 वर्ष) के बीच एचआईवी/एड्स की जानकारी	50
5.11	हिमाचल प्रदेश में जिलों के अनुसार संस्थागत प्रसव	52
5.12	हिमाचल प्रदेश और 3 जिलों में 5 साल के बच्चों के पोषण की स्थिति	53
5.13	हिमाचल प्रदेश और 3 जिलों में बच्चों और वयस्कों में एनीमिया	54
5.14	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत	54
5.15	कमजोरी के प्रकार	55
5.16	हिमाचल प्रदेश में नौ श्रेणियों के तहत वर्गीकरण के साथ कुल कैडस्ट्राल (भूकर संबंधी) सर्वे किया गया क्षेत्र	55
5.17	प्रभावित परिवारों के स्वामित्व वाले पशुधन की सूची	57

5.18	रोजगार में परियोजना से प्रभावित व्यक्ति (15 वर्ष से अधिक आयु)	58
5.19	पुरुषों और महिलाओं के बीच श्रम का घरेलू विभाजन	59
5.20	परियोजना क्षेत्र में स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ	62
5.21	लिंग द्वारा 15-64 वर्षों के भीतर लोगों की रोजगार स्थिति	64
5.22	परियोजना से प्रभावित होने वाले गांव की मोटर योग्य सड़क से दूरी और पहुंचने में लगा समय	64
5.23	जिलों में 3/2018 तक सिंचाई के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र	65
5.24	3 जिलों में आने वाले पर्यटक	66
5.25	परियोजना क्षेत्र में संगठन	68
5.26	परियोजना से प्रभावित परिवारों की आवास की संरचना	71
5.27	परियोजना प्रभावित गांवों में भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता	72
5.28	परियोजना से प्रभावित गांवों में सार्वजनिक सेवा की बुनियादी संरचना की उपलब्धता	72
6.1	स्वास्थ्य का स्तर	76
6.2	भूमि अधिग्रहण के कारण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले निजी भूमि मालिकों की संख्या	77
6.3	हिमाचल प्रदेश राज्य, 3 जिलो और परियोजना क्षेत्र में लिंग के अनुसार साक्षरता दर	81
S.1	प्रभाव बनाम गंभीरता को कम करना और कार्यान्वित के लिए जिम्मेदारी	90

## विशेष सारांश

### (a) परियोजना और सावर्जनिक उद्देश्य

सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजीवीएन), एक मिनी रत्न, जो श्रेणी- I और अनुसूची- 'A' सीपीएसई, बिजली मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं इसे भारत सरकार (जीओआई) और हिमाचल प्रदेश सरकार (जीओएचपी) के संयुक्त उपक्रम के रूप में 24 मई, 1988 शामिल किया गया था। एसजीवीएन वर्तमान में भारत में पड़ोसी देशों यानि कि नेपाल, भूटान के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में बिजली परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

लुहरी एचईपी स्टेज- II (172 मेगावाट) हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में फैले नंज गाँव के पास सतलुज नदी पर चलने वाली एक नदी परियोजना है। इस परियोजना से 90% भरोसेमंद सालों में 632 एमयू बिजली पैदा होने का अनुमान है। लुहरी एचईपी स्टेज- II (172 मेगावाट) सतलुज नदी की जल क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रस्तावित नदी प्रकार के विकास का एक भाग है। यह परियोजना नानजिंग गाँव के पास सतलुज नदी के सबसे गहरे आधार स्तर के ऊपर  $\pm 71$  मीटर ऊँचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध के निर्माण की परिकल्पना करती है और बाएं किनारे पर भूमिगत बिजली घर है। डैमल मंडी और शिमला जिला में नानजिंग गांव के पास लांगीट्यूड 770 20°58.46'E और लैटीट्यूड 31020°22.5'N पर स्थित है।

यह परियोजना स्थल हरियाणा के कालका में नवीनतम रेल हेड से लगभग 178 किमी दूर स्थित है और शिमला, नल्हेड़ा और चाबा होते हुए एनएच-5 और उसके बाद एसएच-13 और एमडीआर-22 होते हुए पहुंचा जा सकता है। निकटतम एयरपोर्ट जुबेर हट्टी (शिमला) है जो परियोजना स्थल से लगभग 93 किमी दूर है। निकटतम इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना स्थल से 205 किमी की दूरी पर चंडीगढ़ में स्थित है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्माण और संचालन के लिए एसजीवीएन को एलएचईपी स्टेज-2 आवंटित किया है। आवश्यक निकाय हिमाचल प्रदेश सरकार का एक पीएसयू है। एचपी की। आवश्यक निकाय के पीएसयू होने के नाते, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण आरओएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 2 के अंतर्गत आता है।

वर्तमान में एलएचईपी स्टेज-II को इस कार्यक्रम के तहत माना जाता है जिसे नदी पर चलने वाली (रन-ऑफ-रिवर) योजनाओं के रूप में डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में फैले नंज गाँव के पास सतलुज नदी पर किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना से 90% भरोसेमंद वर्ष में 632 एमपी बिजली पैदा होने का अनुमान है। एलएचईपी स्टेज- II (172 मेगावाट) सतलुज नदी की जल क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रस्तावित नदी पर चलने वाली विकास योजना है।

निर्माण के पहले के चरण के दौरान, निर्माण के दौरान और परियोजना शुरू होने के बाद, कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए रोजगार उत्पन्न होगा। एचपी सरकार के नियमों के अनुसार, औद्योगिक रोजगार का 70% हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित होना चाहिए। इस मामले में, परियोजना से प्रभावित गांवों के पीएफ को परियोजना स्तर पर पैदा होने वाले रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

#### a.1 परियोजना के उद्देश्य

इस सामाजिक प्रभाव आकलन स्टडी के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:

इस बात का आकलन कि क्या प्रस्तावित अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करता है;

प्रभावित परिवारों का अनुमान लगाना और उनमें से उन परिवारों की संख्या पता लगाना जिन्हें विस्थापित करने/होने की संभावना है;

भूमि, सार्वजनिक और निजी, घरों, बस्तियों और अन्य सामान्य संपत्तियों का स्तर जिनकी प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने की संभावना है;

क्या अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक पूर्ण सही-न्यूनतम सीमा है;

क्या वैकल्पिक जगह पर भूमि अधिग्रहण पर विचार किया गया है और वह संभव नहीं है;

परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन, और उन्हें हल करने की प्रकृति और लागत और परियोजना के फायदों की तुलना में परियोजना की कुलमिलाकर लागतों पर इन लागतों के प्रभाव

ये मुख्य उद्देश्य हैं जिन्हें आरटीएफसीटीएलएआरआरए, 2013 के प्रावधानों के खंड 4 के अनुसार अन्य आवश्यकताओं के साथ अपनाया गया है।

#### a.2 सेवाओं का दायरा

इस परियोजना अध्ययन के तहत सेवाओं के दायरे में हिमाचल प्रदेश के भूमि अधिग्रहण में सही मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियमावली, 2015 के प्रपत्र II के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन की तैयारी शामिल है।

इसके अलावा दायरे में हिमाचल प्रदेश के भूमि अधिग्रहण में सही मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियमावली, 2015 के प्रपत्र II के अनुसार सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना को तैयार करना भी शामिल है।

विस्तृत दायरे में शामिल है:

- टीम एकत्र करना;
- शिमला जिले की तहसील कुमारसैन, बिथल गाँव में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) के भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापन से जुड़े अधिकारियों के साथ मिलना;
- प्रभावों की सीमा और प्रभावों की श्रेणी को समझने के लिए जरूरत के अनुसार एसजेवीएनएल अधिकारियों से उपयुक्त सेकेंडरी डेटा, भूमि और पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी जानकारी एकत्र करना;
- एलएचईपी के स्टेज II के तहत परियोजना विकास के लिए अधिग्रहण की जाने वाली प्रभावित निजी भूमि के सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन सर्वे की शुरुआत के लिए संबंधित पंचायत अधिकारियों के संपर्कों को एकत्रित करना;
- 8 गाँवों को कवर करने वाले परिभाषित परियोजना क्षेत्र का पैमाइस सर्वेक्षण, जिसमें हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के 4 गाँव, कुल्लू जिले के 1 गाँव, मंडी जिले में 3 गाँव शामिल हैं;

- f) 8 गाँवों के पंचायत अधिकारियों और गाँव के अन्य सदस्यों के साथ अपने-अपने गाँव के स्थानों पर अनौपचारिक परामर्श बैठकें आयोजित करना और सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईएस) का अध्ययन करने के लिए कार्यप्रणाली(मथडालजी) पर चर्चा करना और इस परियोजना के तहत भूमि खोने वाले प्रभावित परिवारों से संपर्क करना;
- g) गांव वार और जिले वार एसआईएस को आयोजित करने के लिए फील्ड टीम को शामिल करना;
- h) एसआईएस स्टडी के हिस्से के रूप में प्रभावित परिवारों के साथ जांच करने के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रश्नावली डिजाइन करना;
- i) एसआईएस फ़ील्ड स्टडी शुरू करने से पहले किसी भी टिप्पणियों या सुझावों को शामिल करने के लिए आवश्यक रूप से एसजीवीएन और हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (एचआईपीए) की एसआईएस यूनिट से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रश्नावली की मंजूरी लेना।
- j) एसआईएस स्टडी के एक हिस्से के रूप में पूरा किये जाने वाली एसआईएस प्रश्नावली के लिए डेटा इंटी और विश्लेषण योजना की डिजाइनिंग;
- k) एसआईवीएन और एसआईएस यूनिट, एचआईपीए द्वारा समीक्षा के लिए एसआईएस और एसआईएमपी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करना
- l) उपर दिये गये नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार जनसुनवाई के भाग के रूप में भाग लेना
- m) एसजीवीएन, एचआईपीए और सार्वजनिक सुनवाई से प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए क्योंकि यह एसआईएमपी को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक है।

### (b) लोकेशन/स्थान

परियोजना द्वारा विचाराधीन परियोजना क्षेत्र में शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों के 8 गाँव शामिल हैं। प्रभावित क्षेत्र की संख्या और प्रभावित गाँवों की संख्या के साथ प्रभावित परिवारों की संख्या टेबल 1 में दी गई है।

टेबल 1. परियोजना से प्रभावित होने वाला भूमि क्षेत्र और जिला वार प्रभावित परिवार					
No.	गांव का नाम	तहसील	जिला	प्रभावित परिवारों की संख्या	प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर)
1.	महोली	कुमारसैन	शिमला	82	2.1126
2.	बरगल	कुमारसैन	शिमला	11	1.5751
3.	तलहा	कुमारसैन	शिमला	11	1.7075
4.	चमोद	कुमारसैन	शिमला	04	2.3269
5.	बेहाना	आनी	कुल्लू	66	1.2284
6.	कोट	कारसोग	मंडी	12	0.5974
7.	फेर्नु	कारसोग	मंडी	73	8.0198
8.	ननजी	कारसोग	मंडी	65	6.5772
<b>योग</b>				<b>324</b>	<b>24.1449</b>
स्रोत: एसजीवीएनएल परियोजना कार्यालय, बिथल, कुमारसैन तहसील, 2019					

### (c) भूमि अधिग्रहण का आकार और विशेषताएं

हिमाचल प्रदेश राज्य तीन मुख्य प्रभागों में विभाजित है, जो मंडी, कांगड़ा और शिमला हैं। विभाजन को आगे 12 जिलों में विभाजित किया गया है यानि कि बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल -स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना। जिलों को आगे 53 उप-विभाजन, 79 तहसीलों और 37 उप-तहसीलों में विभाजित किया गया है।

राजस्व प्रशासन के उद्देश्यों के लिए, प्रत्येक तहसील/उप-तहसील को कई कानूनगो सर्किलों में विभाजित किया गया है, जिनका बदले में प्रत्येक को क्रमशः 7 से 10 पटवारी सर्किलों में उप-विभाजन बनाया गया है। इस प्रकार, पटवारी राजस्व पदानुक्रम में सबसे छोटा राजस्व अधिकारी हैं, लेकिन निश्चित रूप से श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी राजस्व सम्पदा के संबंध में सभी राजस्व रिकॉर्ड के उचित रखरखाव और संरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं।

एलएचईपी स्टेज- II के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली कुल भूमि 174.3584 हेक्टेयर है जिसमें निजी भूमि 24.1449 हेक्टेयर (13.85%) है और कुल सरकारी भूमि 150.2135 हेक्टेयर (86.15%) है। कुल निजी भूमि में 168 प्लॉट हैं। इस प्रकार, परियोजना के तहत निजी भूमि का अधिग्रहण न्यूनतम है। परियोजना के लिए आवश्यक निजी भूमि 8 गांवों में स्थित है। ये गाँव शिमला जिले की कुमारसैन तहसील के महावाली, बरगल, तलाह और चमोड़, कुल्लू जिले की तहसील में डिंगीधर गाँव और मंडी जिले के करसोग तहसील के कोट, नंज और फिरनु गाँव हैं।

### (d) विचार किये गये विकल्प

निजी भूमि अधिग्रहणी के लिए नंज साइट पर परियोजना के चुनाव से पहले निम्नलिखित वैकल्पिक अध्ययन किये गये थे:

- विकल्प 1- नंज गांव के पास संकरे घाट पर स्टील ब्रिज के 250 किमी यू/एस पर दाएं किनारे पर डैम और सरफेस टो पावर हाउस
- विकल्प-2: नंज गांव के पास संकरे मार्ग पर स्टील ब्रिज के 700 किमी यू/एस पर बाएं किनारे पर डैम और अंडरग्राउंड टो पावर हाउस। (डैम एक्सिस के 410 एम डी/एस पर टीआरटी-1 और टीआरटी-2)
- विकल्प-3: नंज गांव के पास संकरे मार्ग पर स्टील ब्रिज के 700 किमी यू/एस पर बाएं किनारे पर डैम और अंडरग्राउंड टो पावर हाउस। (डैम एक्सिस के 1080 एम डी/एस पर टीआरटी-1)

विकल्प 1- नंज गांव के पास संकरे घाट पर स्टील ब्रिज के 250 किमी यू/एस पर दाएं किनारे पर डैम और सरफेस टो पावर हाउस

संकरे घाट पर स्टील ब्रिज के 250 किमी यू/एस पर दाएं किनारे पर डैम और सरफेस टो पावर हाउस का अध्ययन किया गया है। डैम और पावर हाउस की लाइमस्टोन और डोलोमाइट में होने की संभावना है। पतले मार्ग 250 एम डीएस से बैकवाटर प्रभाव से पावर हाउस की सतह में पानी भर सकता है, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सका।

विकल्प-2: नंज गांव के पास संकरे मार्ग पर स्टील ब्रिज के 700 किमी यू/एस पर बाएं किनारे पर डैम और अंडरग्राउंड टो पावर हाउस। (डैम एक्सिस के 410 एम डी/एस पर टीआरटी-1 और टीआरटी-2)

भूमिगत बिजली घर के साथ विकल्प -1 के डैम साइट 450एम यू/ एस के एक विकल्प का अध्ययन किया गया है। इस विकल्प के लिए डैम और पावर हाउस लाइमस्टोन और डोलोमाइट में ही होगा। पावर हाउस और ट्रांसफार्मर हॉल के लिए स्थान की उपलब्धता के बारे में विस्तृत अध्ययन के लिए इस साइट पर विचार किया गया है।

विकल्प-3: नंज गांव के पास संकरे मार्ग पर स्टील ब्रिज के 700 किमी यू/एस पर बाएं किनारे पर डैम और अंडरग्राउंड टो पावर हाउस। (डैम एक्सिस के 1080 एम डी/एस पर टीआरटी-1)

विकल्प में समान स्थान और कंपोनेंट के रखने के विकल्प विकल्प-2 के समान हैं बस ट्रेल रेस टनल (टीआरटी-1) की व्यवस्था अलग है। इस विकल्प के लिए वैकल्पिक -2 की तुलना में लगभग 1-2 मीटर का नेट हेड गेन होगा। इस विकल्प का अध्ययन एसजेवीएन विभागों के भीतर चल रहा है। अंतिम रूप देने के बाद, यदि संभव पाया जाता है, तो इसे अलग से जमा किया जाएगा किया जाएगा।

### (e) सामाजिक प्रभाव

सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (एसआईए), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और स्थान-परिवर्तन अधिनियम 2013 का "भूमि अधिग्रहण में ठीक मुआवजे का अधिकार और पारदर्शिता का एक महत्वपूर्ण घटक है। एसआईए सामाजिक आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, पर्यावरणीय पहलुओं के संदर्भ में प्रभावित समुदायों पर एक विकास परियोजना के परिणामों का आकलन करने के लिए एक उपकरण है, ताकि परियोजना की तैयारी के चरण के दौरान पहचाने गए सभी प्रतिकूल मुद्दों को दूर करने के लिए उचित राहत देने वाली योजना तैयार की जा सके। परियोजना के सामाजिक प्रभाव और सार्वजनिक उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए मुख्य अधिनियम (RTFCTLARRA 2013) का चैप्टर- II प्रदान किया गया है। अपनाई गयी प्रभाव मूल्यांकन पद्धति में इस परियोजना के विकास के कारण परिकल्पित संभावित सामाजिक प्रभावों की पहचान शामिल है। एसआईए ने इस परियोजना के लिए स्थानीय कानूनों और नियमों का भी पालन किया।

एसआईए स्टडी प्रभावित परिवारों की सीमा का अनुमान लगाने और विस्थपित किये जाने वाले संभावित परिवारों की संख्या का अनुमान लगाने में सक्षम बनाती हैं और पुनर्वास, परियोजना के विकास के लिए आवश्यक जमीन, लागत और प्रतिकूल या सकारात्मक रूप से प्रभावित लोगों पर परियोजना के कुलमिलाकर प्रभाव का अनुमान लगाया।

इस एसआईए स्टडी को करने के लिए गठित प्रमुख पर्सनल के पास इस तरह की स्टडी करने के लिए वांछित योग्यता, अनुभव और कौशल सेट हैं। यह सामाजिक विज्ञान में योग्यता और लॉ पृष्ठभूमि के साथ एक बहु-विषयक टीम है। डेटा संग्रह और विश्लेषण एक समर्पित एनालिटिकल टीम के द्वारा किया गया था। फ़ील्ड ऑपरेशन को फ़ील्ड मैनेजर के द्वारा सह संचालित किया गया था, जिसे हाउसहोल्ड/लाभार्थी सर्वे करने, बड़ी फ़ील्ड टीमों का प्रबंधन करने, लॉजिस्टिक्स को प्रबंधित करने, डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, डेटा का विश्लेषण और वांछित परिणामों को समय पर प्रस्तुत करने में व्यापक अनुभव है।

इस सामाजिक प्रभाव आकलन में निम्नलिखित कार्य शामिल थे:

- a) संभावित भूमि अधिग्रहण, संरचनात्मक प्रभावों सहित स्थायी और अस्थायी पुनर्वास प्रभावों का विस्तृत इंवेंटरी सर्वे (फोटोग्राफ सहित) को करना।
- b) स्क्रीनिंग और न्यून संभावित सामाजिक प्रभावों का आकलन करना।
- c) उन सभी की जनगणना करना जिन्हें टाइलहोल्डर्स और नॉनटाइल होल्डर्स सहित वर्तमान में प्रभावित (प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों सहित) माना गया है।
- d) संचालित की गयी पुनर्वास योजना एसआईए के माध्यम से पहचाने गये प्रतिकूल प्रभावों की गंभीरता को कम करती हैं और परियोजना के विकास के परिणामों को बेहतर बनाती हैं।

### e.1 सैम्पलिंग कार्यप्रणाली (मेथडालजी)

एसआईए को एलएचईपी स्टेज- II के परियोजना क्षेत्र में जुलाई और अगस्त 2019 के महीने के दौरान किया गया था। यह एक जनगणना सर्वे था और सभी प्रभावित परिवारों का सर्वे किया गया था। आधारभूत जानकारी को समझने के लिए एसआईए और सामाजिक-आर्थिक सर्वे किया गया था।

परियोजना का विकास प्रभावित परिवारों के लिए प्रभाव की परिकल्पना करता है जो अपनी भूमि और संरचनाओं को खो देंगे और वह परिवार जिनकी आजीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई थी। एसजेवीएन के प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों(पीएएफ) की कुल संख्या 324 है। शुरुआत में चमोद मोहाल में पीएएफ की संख्या 4 थी। हालांकि एसआईए सर्वे के दौरान ऐसा पाया गया कि एक घर में जमीन के 4 भागों में उप-विभाजित थी। इसलिए चमोद मोहाल में पीएएफ की संख्या बढ़कर 7 हो गयी। साथ ही दिंगीधर मोहाल में पीएएफ की संख्या 66 थी। हालांकि एसआईए के दौरान इसे पाया गया था कि एक पीएएफ की जमीन को 7 भागों में विभाजित किया गया है। इसलिए चमोद मोहाल में पीएएफ की संख्या बढ़कर 7 हो गयी। इसके अनुसार इन अतिरिक्त पीएएफ का इंटरव्यू किया गया और जानकारी एकत्र की गई। तो इन 9 अतिरिक्त पीएएफ को शामिल करते हुए, एलएचईपी स्टेज- II के तहत कुल मिलाकर पीएएफ की संख्या 324 की असली संख्या के मुकाबले 333 हो गई। फ़ील्ड विजिट के समय, एसआईए सर्वे के दौरान, गाँव में कुछ पीएएफ उपलब्ध नहीं थे। इन 333 पीएएफ में से 116 परिवारों को सर्वे के दौरान कवर नहीं किया जा सका क्योंकि अधिकांश परिवार अन्य स्थानों/जिलों में स्थानांतरित हो गये थे और कुछ ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। उपलब्ध 217 पीएएफ के लिए सामाजिक प्रभावों पर डेटा प्रदान किया गया है और उसके अनुसार रिपोर्ट में शामिल किया गया है। एसआईए के सर्वे के अनुसार सभी 333 पीएएफ टाइलधारक पाए गए, हालांकि कोई भी नॉन-टाइलहोल्डर नहीं था जो इस परियोजना के विकास के कारण प्रभावित हुआ है।

### e.2 भूमि पर प्रभाव

e.2.1 भूमि के बचे हुए भाग में खेती जारी रखने के लिए आर्थिक रूप से व्यावहारिकता: एसआईए सर्वे टीम ने अधिग्रहित भूमि के भाग की बची हुई भूमि की आर्थिक व्यवहार्यता और खेती की निरंतरता के संबंध में उनकी राय जानने के लिए जमीन खोने वालों से संपर्क किया। सभी परिवारों ने बताया कि उनकी भूमि का बचा भाग कम होने के कारण खेती के लिए आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं होगा। सामाजिक सर्वे के दौरान इंटरव्यू किए गए 217 परियोजना प्रभावित परिवारों में से सभी के द्वारा यही बात बताई गयी।

**e.2.2 प्लॉट के एक भाग का अधिग्रहण करने के बाद भूमि का मामूली/गंभीर प्रभाव:** प्रभावित भूमि का नुकसान बनाम स्वामित्व वाली कुल भूमि का 10% या ज्यादा होने के मामले में उत्पादकता की गतिविधियों के लिए उपलब्ध बची हुई जमीन को जीविका के लिए आर्थिक रूप से अलाभकारी माना जाता है (एडीबी ऑपरेशन मैनुअल बैंक पॉलिसी (बीपी)-ओएम सेक्शन F1/BP जिसे 1 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया था और 19 का पेज नंबर 3)। तो प्रभाव को गंभी प्रभाव माना जाएगा। और प्रभावित भूमि का नुकसान बनाम स्वामित्व वाली कुल जमीन का 10% या कम होने के मामले में उत्पादकता की गतिविधियों के लिए उपलब्ध बची हुई जमीन को जीविका के लिए आर्थिक रूप से व्यावहारिक माना जाता है। तो प्रभाव को मामूली प्रभाव मानना जाएगा। यह एशियन डेवलपमेंट बैंक सेफगार्ड पॉलिसी स्टेटमेंट 2009 गाइडलाइन के अनुसार है जिसे नुकसान की सीमा का अनुमान लगाने के लिए अपनाया गया है।

प्रभावित भूमि पर प्रभाव का आकलन करने के लिए एसआईए टीम ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और प्रत्येक प्लॉट पर नुकसान के प्रतिशत की गणना करके प्रभाव का आकलन किया। एलएचडीपी स्टेज-II के लिए निजी भूमि को 168 प्लॉट से अधिग्रहित किया जाना है। यह पता चला कि सभी 168 प्लॉट्स पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं।

### e.2.3 सिंचाई का कवरेज और फसल उगाने का तरीका

सर्वे से पता चला कि सर्वे के दौरान कवर किये गये परिवारों के पास जो निजी जमीने हैं उनमें सिंचाई की सुविधा नहीं है। इन जमीनों को वर्षा सिंचित के रूप में पहचाना जाता है और फसलों को साल में एक बार मानसून के मौसम में उगाया जाता है।

परियोजना क्षेत्र में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें अनाज-गेहूं और मक्का हैं और कुछ क्षेत्र में धान की खेती होती है। लोग सरसों जैसे तिलहन भी उगाते हैं। उगाई जाने वाली नगदी फसलें आलू, अदरक और मटर हैं। विभिन्न प्रकार की सब्जियों में सीजनी सब्जियां, कई फल मुख्य रूप से सेब, अनार और सूखे फल जैसे अखरोट पिस्ता आदि हैं जिनकी खेती की जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कुछ औषधीय और और सुगंधित पौधों की भी खेती की जाती है।

### e.2.4 अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर पेड़

**निजी भूमि:** एसआईए सर्वे के अनुसार निजी जमीनों पर 1174 पेड़ लगे हैं जिसे एलएचडीपी स्टेज-II परियोजना विकास के लिए अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें कुछ फल देने वाले पेड़ हैं जैसे , आम- 3 73, अमरूद- 10, अनार- 451, नींबू- 30, और बादाम- 50।

### e.2.5 आबादी का जनसांख्यिकीय विवरण

**लिंग के अनुसार आबादी:** एसआईए सर्वे 217 पीएफ के लिए किया गया था, जिसमें 918 व्यक्तियों की कुल आबादी शामिल है जिसमें 465 पुरुष और 453 महिलाएं हैं। यह पता चला कि परियोजना प्रभावित परिवारों में लिंगानुपात 974 है।

सामाजिक वर्ग के अनुसार आबादी- 217 पीएफ में से, 90 अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के हैं और 108 अन्य जातियों के हैं। सर्वे किए गए परिवारों में 19 एसटी परिवार हैं, ये गुर्जर समुदाय के हैं।

धर्म के अनुसार आबादी: 217 पीएफ में से, 198 हिंदू समुदाय से हैं और 19 परिवार मुस्लिम समुदाय से हैं। हिंदू और मुस्लिम के इन दो धार्मिक समूहों के अलावा पीएफ के बीच कोई अन्य धार्मिक समूह नहीं हैं।

साक्षरता दर: एसआईए के सर्वेक्षण से पता चला है कि प्रभावित परिवारों के परिवार के सदस्यों के बीच कुल साक्षरता दर 81.51% है। डेटा यह भी संकेत देता है कि पुरुष के बीच साक्षरता दर 89.74% है, जहां यह महिलाओं के बीच 73.33% है।

### e.2.6 कमजोर वर्ग:

कमजोर वर्ग वे समूह हैं जो किसी भी परिस्थितियों में कमजोर हो सकते हैं। भेदभाव का सामना करने वाले कमजोर समूहों में शामिल हैं- महिला, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), बच्चे, वृद्ध, विकलांग, गरीब प्रवासी, एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोग और यौन अल्पसंख्यक। कभी-कभी प्रत्येक समूह अपनी कई पहचानों के कारण कई बाधाओं का सामना करता है। उदाहरण के लिए, एक विकलांग एसटी व्यक्ति को एसटी होने और विकलांग होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

एसआईए सर्वे से पता चला कि 217 पीएफ में से, 70 एससी श्रेणी के हैं और 3 महिला प्रधान परिवार हैं। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों में से 2 विकलांग व्यक्ति हैं।

पीएफ की आर्थिक पृष्ठभूमि पर विचार करते समय यह पाया गया कि 58 परिवार आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के हैं, जिनमें से 33 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) से संबंधित हैं, 8 अंत्योदय अन्न योजना (एवाई) योजना का लाभ उठा रहे हैं और 27 प्राथमिकता राशन कार्ड धरेलू (पीआरसीएच) सुविधा के तहत लाभ उठा रहे हैं।

### e.2.7 पशुधन

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश लोगों के लिए कृषि आजीविका का प्रमुख स्रोत है। इसकी प्रकृति-निर्भरता और विभिन्न तकनीकी बाधाओं की मौजूदगी के कारण कृषि में सुधार लाना एक कठिन कार्य है। ये बाधाएं पहाड़ी और पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन इलाकों और दुर्गमता के कारण अधिक दिखाई देती हैं। फसलों, पशुपालन और बागवानी सहित विभिन्न कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए इनपुट सेवाओं के वितरण (डिलीवरी) के लिए पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी इलाकों की तुलना में कठिन प्रयासों की आवश्यकता होती है। पशुधन पालन इन कृषि प्रणालियों का एक अभिन्न अंग है।

यह पता चला था कि एलएचईपी स्टेज- II के इस परियोजना क्षेत्र में पशुधन को रखना बहुत आम बात है। 217 पीएफ में से, प्रत्येक पीएफ के पास पशुधन की कम से कम एक प्रजाति है, जो गाय है।

परियोजना क्षेत्र में सामुदायिक परामर्श और महिला समूहों के साथ एफजीडी से दो बहुत महत्वपूर्ण संदेश आते हैं: (1) इस क्षेत्र में पशुधन की उत्पादकता बहुत कम है और इसके बढ़ने की एक बड़ी गुंजाइश है, और (2) पशुधन क्षेत्र इस पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक बड़ा सहयोग है, जहाँ लैंडहोल्डिंग छोटी होती है, आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा विविधीकरण की ओर देख रहे कृषि पर निर्भर है। चूंकि लोगों की एक बड़ी संख्या पशुधन के साथ सीधे जुड़ी हुई है, इसलिए पशुधन को बढ़ावा देने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और मौजूदा सरकार की योजनाओं से उचित समर्थन प्रदान करके इसे बढ़ावा दिया जा सकता है जो इस परियोजना के विकास की अवधि के दौरान जुड़े हो सकते हैं।

### e.2.8 रोजगार और आय

एलएचईपी स्टेज-II में परियोजना क्षेत्र के एसआईए सर्वे से पता चला है कि परियोजना से प्रभावित 918 व्यक्तियों (पीएपी) की आयु 15 वर्ष से अधिक है, 477(52%) व्यक्ति कार्यरत हैं और 411(48%) काम नहीं करते हैं। 477 व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उसमें से 9 राज्य के बाहर काम कर रहे हैं, जबकि अन्य लोग राज्य और गांवों के आस-पास के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उन लोगों में से जो काम कर रहे हैं, 128 लोग(27%) औपचारिक क्षेत्र में शामिल है जैसे सरकारी और प्राइवेट नौकरी, जहां 349 अनौपचारिक क्षेत्र (73%) में शामिल हैं। 349 में से सभी जो अनौपचारिक क्षेत्रों में हैं वे खेती और संबंधित गतिविधियों से जुड़े हुए हैं या छोटे बिजनेस या व्यवसाय में शामिल है।

एसआईए के दौरान सर्वे परियोजना से प्रभावित परिवारों की औसत वार्षिक घरेलू आय के साथ-साथ के औसत वार्षिक घरेलू व्यय प्रदान करता है। घरेलू आय में सभी स्रोतों से एक ही परिवार में रहने वाले 15 वर्ष से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति की आय आय शामिल है। यह पता चला था कि औसत वार्षिक घरेलू आय रुपये 4,11,329/- है। इसकी 217 पीएएफ के लिए गणना की गयी है। जैसा कि पता चला है कि घरेलू खर्च आय से कम है, यह संपर्क किये गये सभी पीएएफ में देखा गया है। उन्होंने बताया कि उनके पास अपनी आय से बचत है और अपनी भूमि गिरवी रखकर कृषि उद्देश्य के लिए ऋण भी लेते हैं। यह इस क्षेत्र के लोगों के बीच एक सामान्य व्यवहार है।

### e.2.9 क्रेडिट (ऋण) तक पहुंच

एसआईए सर्वे ने इस बात की जांच की कि परियोजना क्षेत्रों के परिवारों की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की संस्थानों के क्रेडिट संस्थानों तक पहुंच प्राप्त हुई है। सर्वे ने सर्वे से पहले के फसल के साल के सभी बकाया ऋणों के साथ-साथ लिए गए सभी ऋणों (बकाया या चुकाए गए) पर विस्तृत डेटा एकत्र किया। प्रत्येक ऋण, मूल ऋण, ब्याज दर, ऋण के स्रोत, उधार लेने के उद्देश्य, और लोन लेने के लिए गिरवी रखी गयी संपत्ति के संबंध में जानकारी एकत्र की गयी थी।

यह पाया गया कि 217 परिवारों में से 46 परिवारों ने पिछले वर्ष के दौरान ऋण लिया है। 217 पीएएफ में से, 46 परिवारों ने औपचारिक क्षेत्रों से ऋण लिया है, जिसमें बैंक भी शामिल हैं। यह भी पता चला कि अनौपचारिक क्षेत्रों ने ब्याज की उच्च दरों का शुल्क लिया जो प्रति वर्ष 12-25% ब्याज के बीच है, जबकि औपचारिक क्षेत्र प्रति वर्ष 4 - 11% ब्याज के बीच शुल्क लेते हैं। परिवारों ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए बैंकों से ऋण लिया है, जिसमें कृषि गतिविधियां और घर का निर्माण शामिल है, ऋण के उद्देश्य के लिए अधिकतर परिवारों ने विभिन्न संपत्तियों जैसे भूमि को रहन की सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखा है।

### (f) गंभीरता को कम करने के उपाय

2013 के अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम में उचित मुआवजे का अधिकार और पारदर्शिता के प्रावधानों और हिमाचल प्रदेश के नियम 2015 के नियम 3 के उप नियम(4) के अनुसार,परियोजना के प्रभाव का समाधान करने के लिए किये गये जाने वाले सुधारक उपायों का गंभीरता को कम करने वाली योजना को सूचीबद्ध करना है। विस्तृत स्टडी के बाद, हितधारकों द्वारा परामर्श और चिंताओं को आगे रखा गया, रिपोर्ट में निम्नलिखित गंभीरता को कम करने के सुझाव दिये गये हैं।

### f.1 सामुदायिक विकास कार्य

एलएचईपी स्टेज-II परियोजना के प्रभावित गांवों के लिए सामुदायिक विकास कार्यों की सिफारिश की जाती है अनुलग्नक 12 में अनुसूची 3 को संलग्न किया गया है। इन सबके बीच आंतरिक और संपर्क मार्ग, सुरक्षित पेयजल स्रोत उपलब्ध कराना, जल निकासी और स्वच्छता सुविधाएं और पशुओं के लिए चराई की भूमि आदि शामिल होंगी।

### f.2 कमजोर और सामाजिक रूप से पिछड़े परिवार

महिला प्रधान घरों, शारीरिक/ मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध लोगों की समय-समय पर निगरानी की जाएगी और उन्हें आर्थिक उत्थान और जीवन की बेहतरी के लिए संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

यहां 19 एसटी प्रभावित परिवार और 90 एससी परिवार हैं, अधिनियम 2013 में विशेष प्रावधान दिए गए हैं जिन्हें इन परिवारों के लिए बजट अनुमान का हिस्सा माना जाता है।

### f.3 पीएफ के लिए मुफ्त बिजली

उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकार की नीति के अनुसार परियोजना शुरू करने के बाद 10 वर्ष तक प्रभावित परिवारों के लिए 100 यूनिट मुफ्त बिजली परियोजना द्वारा प्रदान की जानी है।

### f.4 स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ)

जलविद्युत परियोजनाओं के विकास दौरान, पर्यावरण, मौजूदा बुनियादी ढांचे, व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधनों, आदि पर प्रभाव पड़ता है। इन प्रतिकूल परिणामों की गंभीरता कम करने का प्रावधान को योजनाओं जैसे [पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी), कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान (कैट प्लान), क्षतिपूर्क वनीकरण के माध्यम से पर्यावरण के नुकसान भरपाई, कुल मौजूदा कीमत का भुगतान, पुनर्वास और पुनःस्थापन योजनाएं और प्रदूषण के कारण फसलों को नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति, आदि के लिए प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, स्थानीय विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए राज्य जल विद्युत नीति के तहत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) का एक विशेष प्रावधान किया गया है, ताकि परियोजना की लागत के हिस्से के रूप में परियोजना क्षेत्र में स्थानीय समुदायों के लिए दिखने वाला अतिरिक्त लाभ के रूप में सुनिश्चित किया जा सके।

एमपीपी एंड पावर विभाग, एचपी सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित एलएडीएफ दिशानिर्देशों के अनुसार (प्रतिलिपि अनुबंध के रूप में संलग्न है 13) 5मेगावाट से ऊपर की परियोजना की अंतिम लागत का 1.5% एलएडीएफ को योगदान दिया जाएगा। यहां यह ध्यान दिया जाता है कि एलएचईपी स्टेज- II की क्षमता 271 मेगावाट है।

जलविद्युत परियोजनाओं के चालू होने के बाद अतिरिक्त 1% (एक प्रतिशत) निः शुल्क बिजली एलएडीएफ के लिए आय उत्पत्ति और जनकल्याण योजनाओं, अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं आदि के निर्माण

के लिए जीवन भर परियोजना के आधार पर लगातार और निरंतर राजस्व का एक नियमित स्रोत प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

परियोजना के डिजाइन और लागत में उचित और पर्याप्त प्रावधान करके इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

फसल के नुकसान के लिए मुआवजा: आवश्यक निकाय न केवल प्रभावित भूस्वामियों को मुआवजा देने के लिए प्रतिबंधित होंगे, बल्कि निर्माण चरण के दौरान, अगर निर्माण गतिविधियों के कारण फसलों को किसी भी नुकसान का पता चलेगा, तो प्रभावित किसानों को हिमाचल सरकार की फसल नीति के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

### **(g) सामाजिक लागतों और लाभों का आकलन**

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) के कार्यान्वयन की लागत रुपये 52,82,45,578.00 /- है, यानी इस बजट में एसजेवीएन द्वारा की जाने वाली आंतरिक निगरानी लागत पर विचार करते हुए एसआईएमपी के कार्यान्वयन की लागत शामिल है।

### **(h) समापन टिप्पणियां**

हिमाचल प्रदेश के बताए गये भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन अधिनियम में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के फॉर्म 2 के अनुसार सामाजिक प्रभाव का आकलन प्रदान किया गया है। इन इनपुट्स(जानकारियों) ने सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) को बता गये नियमों के फॉर्म III के अनुसार तैयार करने में सक्षम बनाया है। यह सामाजिक प्रभाव के आकलन (एसआईए) प्रभावों की सीमा और प्रभावों की श्रेणी प्रदान करता है जो एसआईएमपी को पहचानने और डिजाइन करने में सक्षम बनाता है, नुकसान के विरुद्ध प्रभावों के आधार पर प्रदान किए जाने वाले एंटाइटेलमेंट का संकेत देता है जो एसआईए के अनुसार भूमि और जीविका है।

## अध्याय 1

## परियोजना का विस्तृत विवरण

### 1.1 परिचय

सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (एसआईए), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और स्थान-परिवर्तन अधिनियम 2013 का "भूमि अधिग्रहण में ठीक मुआवजे का अधिकार और पारदर्शिता का एक महत्वपूर्ण घटक है। एसआईए सामाजिक आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, पर्यावरणीय पहलुओं के संदर्भ में प्रभावित समुदायों पर एक विकास परियोजना के परिणामों का आकलन करने के लिए एक उपकरण है, ताकि परियोजना की तैयारी के चरण के दौरान पहचाने गए सभी प्रतिकूल मुद्दों को दूर करने के लिए उचित राहत देने वाली योजना तैयार की जा सके। परियोजना के सामाजिक प्रभाव और सार्वजनिक उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए मुख्य अधिनियम (RTFCTLARRA 2013) का चैप्टर-II प्रदान किया गया है। यह एसआईए प्रस्तावित लुहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के चरण-2 (172 मेगा वाट) के लिए तैयार की गयी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्माण और संचालन के लिए एसजेवीएन को एलएचईपी स्टेज-2 आवंटित किया है।

एसआईए स्टडी प्रभावित परिवारों की सीमा का अनुमान लगाने और स्टडी के दौरान पहचाने जाने वाले विस्थापित किये जाने वाले संभावित परिवारों की संख्या का अनुमान लगाने में सक्षम बनाती है। यह पुनर्वास, परियोजना के विकास के लिए आवश्यक जमीन, लागत और प्रतिकूल या सकारात्मक रूप से प्रभावित लोगों पर परियोजना के कुलमिलाकर प्रभाव अनुमान लगाएगा।

#### 1.1.1 परियोजना का संक्षिप्त विवरण

सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, एक मिनी रत्न, जो श्रेणी- I और अनुसूची- 'A' सीपीएसई, बिजली मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं इसे भारत सरकार (जीओआई) और हिमाचल प्रदेश सरकार (जीओएचपी) के संयुक्त उपक्रम के रूप में 24 मई, 1988 शामिल किया गया था। एसजेवीएन वर्तमान में भारत में पड़ोसी देखा यानिकि नेपाल और भूटान के अलावा भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में बिजली परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

लुहरी एचईपी स्टेज- II (172 मेगावाट) हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में फैले नंज गाँव के पास सतलुज नदी पर चलने वाली एक नदी परियोजना है। इस परियोजना से 90% भरोसेमंद सालों में 632 एमयू बिजली पैदा होने का अनुमान है। लुहरी एचईपी स्टेज- II (172 मेगावाट) सतलुज नदी की जल क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रस्तावित नदी प्रकार के विकास का एक भाग है। यह परियोजना नानजिंग गाँव के पास सतलुज नदी के सबसे गहरे आधार स्तर के ऊपर +71 मीटर ऊँचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध के निर्माण की परिकल्पना करती है और बाएं किनारे पर भूमिगत बिजली घर है। बांध मंडी और शिमला जिले में नानजिंग गाँव के पास लांगट्यूड 77° 20' 58.46" E और लैटीट्यूड 31° 02' 22.5" N पर स्थित है।

यह परियोजना स्थल हरियाणा के कालका में नवीनतम रेल हेड से लगभग 178 किमी दूर स्थित है और शिमला, नल्हेड़ा और चाबा होते हुए एनएच-5 और उसके बाद एसएच-13 और एमडीआर-22 होते हुए पहुंचा जा सकता है।

निकटतम एयरपोर्ट जुबेर हट्टी (शिमला) है जो परियोजना स्थल से लगभग 93 किमी दूर है। निकटतम इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना स्थल से 205 किमी की दूरी पर चंडीगढ़ में स्थित है।

### 1.1.2 परियोजना का उद्देश्य

इस सामाजिक प्रभाव आकलन स्टडी के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:

- इस बात का आकलन कि क्या प्रस्तावित अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करता है;
- प्रभावित परिवारों का अनुमान लगाना और उनमें से उन परिवारों की संख्या पता लगाना जिन्हें विस्थापित करने/होने की संभावना है;
- Extent of lands, public and private, houses, settlements and other common properties likely to be affected by the proposed acquisition; भूमि, सार्वजनिक और निजी, घरों, बस्तियों और अन्य सामान्य संपत्तियों का स्तर जिनकी प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने की संभावना है;
- क्या अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा परियोजना के लिए आवश्यक पूर्ण सही-न्यूनतम सीमा है;
- क्या वैकल्पिक जगह पर भूमि अधिग्रहण पर विचार किया गया है और वह संभव नहीं है;
- परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन, और उन्हें हल करने की प्रकृति और लागत और परियोजना के फायदों की तुलना में परियोजना की कुलमिलाकर लागतों पर इन लागतों के प्रभाव
- ये मुख्य उद्देश्य हैं जिन्हें RTFCTLARRA, 2013 के प्रावधानों के खंड 4 के अनुसार अन्य आवश्यकताओं के साथ अपनाया गया है।

### 1.1.3 सेवाओं का दायरा

इस परियोजना अध्ययन के तहत सेवाओं के दायरे में हिमाचल प्रदेश के भूमि अधिग्रहण में सही मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियमावली, 2015 के प्रपत्र II के अनुसार सामाजिक प्रभाव आकलन की तैयारी शामिल है।

इसके अलावा दायरे में हिमाचल प्रदेश के भूमि अधिग्रहण में सही मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियमावली, 2015 के प्रपत्र II के अनुसार सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना को तैयार करना भी शामिल है।

विस्तृत दायरे में शामिल हैं:

- टीम एकत्र करना;
- शिमला जिले की तहसील कुमारसैन, बिथल गाँव में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) के भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्स्थापन से जुड़े अधिकारियों के साथ मिलना;
- प्रभावों की सीमा और प्रभावों की श्रेणी को समझने के लिए जरूरत के अनुसार एसजेवीएनएल अधिकारियों से उपयुक्त सेकेंडरी डेटा, भूमि और पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी जानकारी एकत्र करना;
- एलएचईपी के स्टेज II के तहत परियोजना विकास के लिए अधिग्रहण की जाने वाली प्रभावित निजी भूमि के सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन सर्वे की शुरुआत के लिए संबंधित पंचायत अधिकारियों के संपर्क को एकत्रित करना;

8 गांवों को कवर करने वाले परिभाषित परियोजना क्षेत्र का पैमाइस सर्वेक्षण, जिसमें हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के 4 गाँव, कुल्लू जिले के 1 गाँव, मंडी जिले में 3 गाँव शामिल हैं;

- e) 8 गाँवों के पंचायत अधिकारियों और गाँव के अन्य सदस्यों के साथ अपने-अपने गाँव के स्थानों पर अनौपचारिक परामर्श बैठकें आयोजित करना और सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईएस) का अध्ययन करने के लिए कार्यप्रणाली(मैथडालजी) पर चर्चा करना और इस परियोजना के तहत भूमि खोने वाले प्रभावित परिवारों से संपर्क करना;
- f) गांव वार और जिले वार एसआईएस को आयोजित करने के लिए फील्ड टीम को शामिल करना;
- g) एसआईएस अध्ययन के हिस्से के रूप में प्रभावित परिवारों के साथ जांच करने के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रश्नावली डिजाइन करना;
- h) एसआईएस फील्ड स्टडी शुरू करने से पहले किसी भी टिप्पणियों या सुझावों को शामिल करने के लिए आवश्यक रूप से एसजीवीएन और हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (एचआईपीए) की एसआईएस यूनिट से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रश्नावली की मंजूरी लेना।
- i) एसआईएस स्टडी के एक हिस्से के रूप में पूरा किये जाने वाली एसआईएस प्रश्नावली के लिए डेटा इंटी और विश्लेषण योजना की डिजाइनिंग;
- j) एसआईवीएन और एसआईएस यूनिट, एचआईपीए द्वारा समीक्षा के लिए एसआईएस और एसआईएमपी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करना
- k) उपर दिये गये नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार जनसुनवाई के भाग के रूप में भाग लेना
- l) एसजीवीएन, एचआईपीए और सार्वजनिक सुनवाई से प्राप्त सुझावों को शामिल करते हुए क्योंकि यह एसआईएमपी को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक है।

उपरोक्त के अनुसार परियोजना की गतिविधियों को किया जाएगा और पूरा किया जाएगा

#### 1.1.4 परियोजना क्षेत्र

परियोजना द्वारा विचाराधीन परियोजना क्षेत्र में शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों के 8 गाँव शामिल हैं। प्रभावित क्षेत्र की संख्या और प्रभावित गांवों की संख्या के साथ प्रभावित परिवारों की संख्या टेबल 1.1 में दी गई है।

– टेबल 1.1. परियोजना से प्रभावित होने वाला भूमि क्षेत्र और जिला वार प्रभावित परिवा					
क्रम	गांव का नाम	तहसील	जिला	प्रभावित परिवारों की संख्या	प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर)
1.	महोली	कुमारसैन	शिमला	82	2.1126
2.	बरगल	कुमारसैन	शिमला	11	1.5751
3.	तलहा	कुमारसैन	शिमला	11	1.7075
4.	चमोद	कुमारसैन	शिमला	04	2.3269
5.	बेहाना	आनी	कुल्लू	66	1.2284
6.	काँट	करसोग	मंडी	12	0.5974
7.	फेर्नु	करसोग	मंडी	73	8.0198
8.	ननजी	करसोग	मंडी	65	6.5772

योग	324	24.1449
स्रोत: एसजेवीएनएल परियोजना ऑफिस, बिथल, कुमारसैन तहसील, 2019		

### 1.1.5 डिवलेपर्स की पृष्ठभूमि और प्रबंधन संरचना

सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजीवीएन), एक मिनी रत्न, जो श्रेणी- I और अनुसूची- 'A' सीपीएसई, बिजली मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं इसे भारत सरकार (जीओआई) और हिमाचल प्रदेश सरकार (जीओएचपी) के संयुक्त उपक्रम के रूप में 24 मई, 1988 शामिल किया गया था। एसजीवीएन अब एक लिस्टेड कंपनी है। एक परियोजना और एक राज्य के संचालन (यानि कि हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा 1500 मेगावाट नाथपा जाखरी हाइड्रो पावर स्टेशन) से शुरूवात करते हुए कंपनी को विंड और सोलर पावर सहित कुल 2015.2 मेगावाट की इंस्टॉल क्षमता की पांच परियोजनाएं दी गयी हैं। एसजेवीएन वर्तमान में भारत में पड़ोसी देशों यानि कि नेपाल और भूटान के अलावा भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में बिजली परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

लुहरी एचईपी स्टेज- II (172 मेगावाट) हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में फैले नंज गाँव के पास सतलुज नदी पर चलने वाली एक नदी परियोजना है। इस परियोजना से 90% भरोसेमंद सालों में 632 एमयू बिजली पैदा होने का अनुमान है। लुहरी एचईपी स्टेज- II (172 मेगावाट) सतलुज नदी की जल क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रस्तावित नदी प्रकार के विकास का एक भाग है। यह परियोजना नानजिंग गाँव के पास सतलुज नदी के सबसे गहरे आधार स्तर के ऊपर  $\pm 71$  मीटर ऊँचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध के निर्माण की परिकल्पना करती है और बाएं किनारे पर भूमिगत बिजली घर है।

### 1.2 परियोजना के लिए तर्क

इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए आरटीएफसीटीएआरआरए, 2013 सेक्शन 2(1) (b) के प्रावधानों के अनुसार, जिसमें इस परियोजना को जनता को बेहतर बिजली प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है और इसके अलावा इस परियोजना को एक नवीकरणीय बिजली उत्पादन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश अपनी पांच बड़ी नदियों में विशाल पनबिजली क्षमता के साथ समृद्ध है और खड़ी ढाल वाली उनकी सहायक नदियां पनबिजली क्षमता के अनुकूल उपयोग के लिए योजना बनाने वालों और इंजीनियरों को निरंतर चुनौती देती रहती हैं। राज्य, केंद्रीय, राज्य, ज्वाइंट और निजी क्षेत्र के डिवलेपर्स द्वारा कई पनबिजली परियोजनाएं चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में पनबिजली ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के लिए केवल एक ही रणनीति है, कि जितना संभव हो उतनी ऊर्जा का उत्पादन करना, न्यूनतम लागत के साथ और न्यूनतम पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभावों के साथ जितना तेज संभव हो उत्पादन करना है। जलविद्युत क्षमता का तेजी से उपयोग निश्चित रूप से राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा क्योंकि सभी नए प्रतिष्ठानों पर 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 1% स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) राज्य के संसाधनों को एक महत्वपूर्ण सीमा तक बढ़ायेगा। परियोजना की आवश्यकता अधिकतम बिजली की मांग में लगातार वृद्धि और उत्तरी क्षेत्र में बढ़ते ऊर्जा घाटे को पूरा करने की आवश्यकता से उत्पन्न होती है।

इस संबंध में क्योंकि परियोजना पनबिजली संयंत्र की स्थापना के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण की परिकल्पना करती है। यह भूमि अधिग्रहण आटीएफसीटीएलएआरआरए, 2013 और हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव का आकलन और सहमति) नियम 2015 {एचपीआरएफसीटीएलएआरआरए (एसआईएऔरसी) नियम 2015 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

### 1.3 परियोजना का विवरण

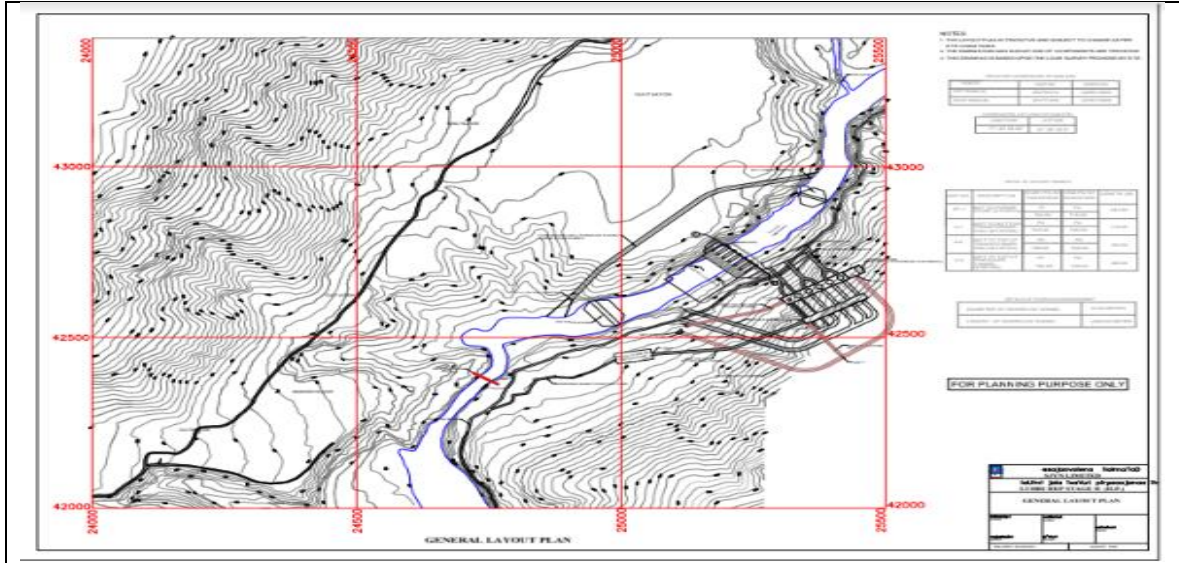
हिमाचल प्रदेश अपनी पांच बड़ी नदियों में विशाल पनबिजली क्षमता के साथ समृद्ध है और खड़ी ढाल वाली उनकी सहायक नदियां पनबिजली क्षमता के अनुकूल उपयोग के लिए योजना बनाने वालों और इंजीनियरों को निरंतर चुनौती देती रहती है। राज्य, केंद्रीय, राज्य, ज्वाइंट और निजी क्षेत्र के डिवलपर्स द्वारा कई पनबिजली परियोजनाएं चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में पनबिजली ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के लिए केवल एक ही रणनीति है, कि जितना संभव हो उतनी ऊर्जा का उत्पादन करना, न्यूनतम लागत के साथ और न्यूनतम पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभावों के साथ जितना तेज़ संभव हो उत्पादन करना है। जलविद्युत क्षमता का तेजी से उपयोग निश्चित रूप से राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य में सुधार करेगा क्योंकि सभी नए प्रतिष्ठानों पर 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 1% स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) राज्य के संसाधनों को एक महत्वपूर्ण सीमा तक बढ़ायेगा। परियोजना की आवश्यकता अधिकतम बिजली की मांग में लगातार वृद्धि और उत्तरी क्षेत्र में बढ़ते ऊर्जा घाटे को पूरा करने की आवश्यकता से उत्पन्न होती है।

इस संबंध में क्योंकि परियोजना पनबिजली संयंत्र की स्थापना के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण की परिकल्पना करती है। यह भूमि अधिग्रहण आटीएफसीटीएलएआरआरए, 2013 और हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव का आकलन और सहमति) नियम 2015 {एचपीआरएफसीटीएलएआरआरए (एसआईएऔरसी) नियम 2015 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

#### 1.3.1 परियोजना का साइज़ और स्थान

प्रस्तावित परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में सतलुज नदी पर स्थित है। बांध जिला मंडी और शिमला में नानजिंग गांव के पास लांगीट्यूड 770 20°58.46'E और लैटीट्यूड 31020°22.5'N पर स्थित है। परियोजना के अपस्ट्रीम पर 412 मेगावाट रामपुर एचपीएस है, जो बाहरी अपस्ट्रीम 1500 मेगावाट नाथपा-झाकरी परियोजना से छूटने वाले पानी का उपयोग करता है। लुहरी एचईपी स्टेज II के निचले हिस्से पर प्रस्तावित सुन्नी बांध परियोजना (23 किमी डी/एस से ऊपर) और 800 मेगावाट की कोल परियोजना परियोजना है। रामपुर एचपीएस और प्रस्तावित लुहरी एच.ई. परियोजना- II के बीच, लुहरी एचईपी स्टेज- I (लगभग 27 किमी अपस्ट्रीम) है।

यह परियोजना स्थल हरियाणा के कालका में नवीनतम रेल हेड से लगभग 178 किमी दूर स्थित है और शिमला, नल्हेड़ा और चाबा होते हुए एनएच-5 और उसके बाद एसएच-13 और एमडीआर-22 होते हुए पहुंचा जा सकता है। निकटतम एयरपोर्ट जुबेर हट्टी (शिमला) है जो परियोजना स्थल से लगभग 93 किमी दूर है। निकटतम इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना स्थल से 205 किमी की दूरी पर चंडीगढ़ में स्थित है।



चित्र 1: परियोजन का आउट

### 1.3.2 उत्पादन लक्ष्य और लागत के साथ परियोजना की क्षमता और आउटपुट

लुहरी एचईपी स्टेज- II (172 मेगावाट) हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में फैले नंज गाँव के पास सतलुज नदी पर चलने वाली नदी परियोजना है। इस परियोजना से 90% भरोसेमंद वर्ष में 632 मेगायूनिट बिजली उत्पन्न होने का अनुमान है। 16.03.18 को भारत सरकार से 72.478 करोड़ रुपये की पूर्व-निर्माण गतिविधियों के लिए निवेश की मंजूरी मिली है।

इस परियोजना के विकास से परिकल्पना किये गये डिजाइन ऊर्जा उत्पादन आउटपुट को नीचे दी गई टेबल में दिया गया है, यह उत्पादन लक्ष्य भी है।

डिजाइन ऊर्जा	631.84 GWh (संभावित)
वार्षिक लोड फैक्टर (मुख्य यूनिट)	40.35%
वार्षिक लोड फैक्टर (पर्यावरणीय यूनिट)	50.70%

### 1.4 विकल्पों की परीक्षा

निजी भूमि अधिग्रहणी के लिए नंज साइट पर परियोजना के चुनाव से पहले निम्नलिखित वैकल्पिक अध्ययन किये गये थे:

- विकल्प 1- नंज गाँव के पास संकरे मार्ग पर स्टील ब्रिज के 250 किमी यू/एस पर दाएं किनारे पर डैम और सरफेस टो पावर हाउस
- विकल्प-2: नंज गाँव के पास संकरे मार्ग पर स्टील ब्रिज के 700 किमी यू/एस पर बाएं किनारे पर डैम और अंडरग्राउंड टो पावर हाउस। (डैम एक्सिस के 410 एम डी/एस पर टीआरटी-1 और टीआरटी-2)
- विकल्प-3: नंज गाँव के पास संकरे मार्ग पर स्टील ब्रिज के 700 किमी यू/एस पर बाएं किनारे पर डैम और अंडरग्राउंड टो पावर हाउस। (डैम एक्सिस के 1080 एम डी/एस पर टीआरटी-1)

विकल्प 1- नंज गांव के पास संकरे घाट पर स्टील ब्रिज के 250 किमी यू/एस पर दाएं किनारे पर डैम और सरफेस टो पावर हाउस

संकरे घाट पर स्टील ब्रिज के 250 किमी यू/एस पर दाएं किनारे पर डैम और सरफेस टो पावर हाउस का अध्ययन किया गया है। डैम और पावर हाउस की लाइमस्टोन और डोलोमाइट में होने की संभावना है। पतले मार्ग 250 एम डीएस से बैकवाटर प्रभाव से पावर हाउस की सतह में पानी भर सकता है, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सका।

विकल्प-2: नंज गांव के पास संकरे मार्ग पर स्टील ब्रिज के 700 किमी यू/एस पर बाएं किनारे पर डैम और अंडरग्राउंड टो पावर हाउस। (डैम एक्सिस के 410 एम डी/एस पर टीआरटी-1 और टीआरटी-2)

भूमिगत बिजली घर के साथ विकल्प -1 के डैम साइट 450एम यू/ एस के एक विकल्प का अध्ययन किया गया है। इस विकल्प के लिए डैम और पावर हाउस लाइमस्टोन और डोलोमाइट में ही होगा। पावर हाउस और ट्रांसफार्मर हॉल के लिए स्थान की उपलब्धता के बारे में विस्तृत अध्ययन के लिए इस साइट पर विचार किया गया है।

विकल्प-3: नंज गांव के पास संकरे मार्ग पर स्टील ब्रिज के 700 किमी यू/एस पर बाएं किनारे पर डैम और अंडरग्राउंड टो पावर हाउस। (डैम एक्सिस के 1080 एम डी/एस पर टीआरटी-1)

विकल्प में समान स्थान और कंपोनेंट के रखने के विकल्प विकल्प-2 के समान है बस ट्रेल रेस टनल (टीआरटी-1) की व्यवस्था अलग है। इस विकल्प के लिए वैकल्पिक -2 की तुलना में लगभग 1-2 मीटर का नेट हेड गेन होगा। इस विकल्प का अध्ययन एसजेवीएन विभागों के भीतर चल रहा है। अंतिम रूप देने के बाद, यदि संभव पाया जाता है, तो इसे अलग से जमा किया जाएगा।

## 1.5 परियोजना निर्माण के चरण

लुहरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में फैली सतलुज नदी पर स्थित है। शुरुआत में एलएचईपी एकल चरण परियोजना के रूप में विचार किया गया था और हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ 27.10.08 को कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। मार्च, 2015 में हिमाचल सरकार ने एसजेवीएन को सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण एकल चरण के बजाय एलएचईपी को मल्टी-स्टेज(कई चरण वाली) परियोजना के रूप में क्रियान्वित करने की संभावना का पता लगाने की सलाह दी। इसके अनुसार, रामपुर और कोल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बीच सतलुज नदी की पनबिजली क्षमता का उपयोग करने के तीन चरणों (यानी कि लुहरी एचईपी स्टेज-I- 210 मेगावाट, लुहरी एचईपी स्टेज-II-172 मेगावाट और सुन्नी डैम एचईपी - 382मेगावाट) की परिकल्पना की गई थी। हिमाचल सरकार ने 29.08.17 को एसजेवीएन को " स्टैंड अलोन आधार" पर तीन परियोजनाएं आवंटित की।

**लुहरी एचईपी स्टेज-1** 210 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ सतलुज नदी पर स्थिति नदी पर चलने वाली (आरओआर) योजना है जो निरथा गांव के पास स्थिति है और हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में फैली हुई है। इस परियोजना में 90% भरोसेमंद वर्ष में 758 मेगायूनिट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। भारत सरकार के द्वारा 8.02.18 को पूर्व निर्माण गतिविधियों के लिए 86.53 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी गयी है।

लुहरी एचईपी स्टेज-1 (172 मेगावाट) नंज गांव के पास सतलुज नदी पर नदी पर चलने वाली परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू और मंडी जिलों में फैली हुई है। इस परियोजना में 90% भरोसेमंद वर्ष में 632 मेगायूनिट

विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। भारत सरकार के द्वारा 16.03.18 को पूर्व निर्माण गतिविधियों के लिए 72.478 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी गयी है।

## 1.6 मुख्य डिजाइन की विशेषताएं और सुविधाओं के साइज

परियोजना के तहत प्रस्तावित मुख्य डिजाइन सुविधाओं और अन्य सुविधाओं में शामिल हैं:

### i. रिवर डायवर्जन वर्कस

नदी की घाटी के दाईं ओर डायवर्जन टनल का निर्माण प्रस्तावित है। 765 मी<sup>3</sup>/सेकेंड तक के डायवर्जन फ्लड के गुजरने के लिए 10.5 मी व्यास का घोड़े की नाल के आकार डायवर्जन डिजाइन किया गया है। अपस्ट्रीम कॉफर डैम की ऊंचाई ±17.50 मीटर और डाउनस्ट्रीम कॉफर डैम की ऊंचाई ± 6.0 मीटर होगी।

### ii. डैम और स्पिलवे

सबसे गहरी नींव स्तर +688मीटर से एक +71m ऊंचा, कंक्रीट ग्रेविटी डैम प्रास्ताविक किया गया है इसमें 9.75m (W) X 16.50m (H) की साइज के 6 आधारभूत गेटेड स्पिलवेज शामिल हैं। स्पिलवे को 14862 क्यूमेक के संभावित अधिकतम फ्लड के अनुरूप डिजाइन फ्लड के गुजरने करने के लिए डिजाइन किया गया है। पूर्ण जलाशय स्तर 755.50 मीटर और अधिकतम ड्रा डाउन स्तर ईआई 750.00मी रखा गया है। डैम लगभग 13.55एमसीएम का कुल तालाब और 5.44 एमसीएम का लाइव स्टोरेज प्रदान करेगा। शीर्ष पर बांध की लंबाई +147.13 मीटर होगी। प्रस्तावित बांध को 11 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है जैसा कि टेबल 1.2 में दिया गया है।

टेबल 1.2. डैम ब्लॉक्स का विवरण

क्रम	विवरण	कुल लंबाई (मीटर)	ब्लॉक्स की संख्या	ब्लॉक संख्या	टिप्पणी
1	बाएं किनारे पर एनओएफ खंड	36.00	3	9, 10 & 11	कुल ब्लॉक्स = 11
2	ओवरफ्लो ब्लॉक्स	94.50	6	3 से 8	
3	दाएं किनारे पर एनओएफ खंड	16.63	2	1 से 2	

### iii. प्रवेश की संरचना

जलाशय से भूमिगत बिजली घर तक 661.10 मीटर 3/ सेकेंड (मुख्य यूनिट+सहायक यूनिट) का डिजाइन डिस्चार्ज प्रदान करने के लिए दाहिने किनारे पर प्रवेश संरचना प्रस्तावित है। प्रवेश संरचना की सेंटर लाइन ±736.23m पर प्रस्तावित है। प्रेशर शाफ्टों में खींचे जानेवाले डूबे हुए मलबे को रोकने के लिए ट्रैश स्क्रीन्स प्रदान की जाएगी। ट्रैश रैक की सफाई की सुविधा भी प्रस्तावित की गई है। ट्रैश स्क्रीन के माध्यम से वेग 1.5मीटर/सेकेंड तक सीमित होगा जैसा कि IS: 9761-1995- हाइड्रोलिक डिजाइन के लिए जलविद्युत इंटेक-मानदंड में बताया गया है।

इंटेक-1 और 2(245.99 मी<sup>3</sup>/सेकेंड प्रत्येक) से डिस्चार्ज का उपयोग मुख्य के लिए और इंटेक-3(169. मी<sup>3</sup>/सेकेंड) के लिए डिस्चार्ज को पर्यावरणीय यूनिट्स के लिए उपयोग किया जाएगा।

स्टॉप लॉग गेट्स के साथ इंटेक गेट्स निरीक्षण और रखरखाव में सक्षम करने के लिए प्रदान किए गये हैं, जबकि जलाशय बंद है और अत्यधिक बाढ़ के दौरान प्रेशर शाफ्ट प्रवेश क्षेत्र के भीतर भारी तलछट वाले पानी को जमने से रोकता है। इंटेक स्ट्रक्चर से लेकर टीबीटी आउटफ्लो तक का एल-सेक्शन प्लेट-ई में दिया गया है।

**iv. प्रेशर शाफ्ट और पेनस्टॉक**

संचालन और रखरखाव में लचीलेपन के लिए, 3 प्रेशर शाफ्ट प्रस्तावित की गयी हैं जिन्हें आगे 661.10मी<sup>3</sup>/सेकंड के कुल डिस्चार्ज में छह पास में विभाजित किया जाएगा।

**v. पावर हाउस और ट्रांसफार्मर हॉल**

सतही पावर हाउस की जगह की अनुपलब्धता के कारण 172 मेगावाट (4 x 32 मेगावाट-मेन यूनिट्स और 1 x 32 MW + 1 x 12 मेगावाट पर्यावरणीय यूनिट्स) की स्थापित क्षमता के साथ बाएं किनारे (शिमला जिले में) पर 176.5m (L) x 24.65m (W) x 53.0m (H) साइज़ का भूमिगत बिजली घर प्रदान किया जाएगा। ±80मीटर के टॉप कवर के साथ पहाड़ के अंदर ±130 मीटर की एक पावर हाउस गुफा प्रस्तावित है। ट्रांसफॉर्मर हाल और मशीन हाल के बीच में न्यूनतम 50.0 मीटर की चट्टान की उपलब्ध है। प्रस्तावित ट्रांसफॉर्मर गुफा 139.5(लंबाई) x 19.0(चौड़ाई) x 29.0(ऊंचाई) की है।

**vi. टेल रेस टनल और स्ट्रक्चर**

टर्बाइन्स से मौजूद पानी को ड्राफ्ट ट्यूबों के माध्यम से 9.7 मीटर और 8.7 मीटर व्यास के घोड़े के नाल के आकार की 2 टेल रेस टनल में छोड़ा जाएगा। टेल रेस टनल्स की लंबाई संबंधित रूप से +453.0मीटर और +399मीटर की होगी। टीआरटी से सतलुज नदी तक पानी छोड़ने के लिए EI+716.70 मीटर के क्रस्ट लेबल के साथ टीआरटी के बाद टीआरटी आउटफाल गेटेड संरचना प्रस्तावित की गयी है।

**vii. एक्सेस टनल्स**

मशीन हॉल और ट्रांसफार्मर हॉल और पेनस्टॉक तक एक्सेस सुरंगों को वाहनों के आकार और उनमें ले जाने वाले आवश्यक उपकरणों के आधार पर निर्धारित किया गया है, 15 मी 1 की अधिकतम ढलान और पैंतरेबाज़ी की आसानी के लिए उन्हें जितना संभव हो उतना सीधा कर सकते हैं। निर्माण के लिए एक्सेस सुरंगें अगल-बगल में केवल दो डंप ट्रक को पास करने की आकार की है।

**viii. मेन एक्सेस टनल (एमएटी)**

मेन एक्सेस टनल 1 इन 15 की अधिकतम ढलान के साथ लगभग ±672 मीटर लंबी होगी। यह अनुमान लगाया गया है कि पार्किंग क्षेत्र बनाने के लिए सुरंग और उसके मशीन हॉल लोडिंग और इरेक्शन बे के बीच जंक्शन पर एक बड़ा खंड बनाया जाएगा।

**ix. सेकेंडरी एक्सेस टनल और केबल टनल**

सेकेंडरी एक्सेस टनल और केबल टनल ट्रांसफॉर्मर, स्विचगियर और ड्राफ्ट ट्यूब गेट्स की डिलीवरी के लिए पहुंच प्रदान करता है। इस टनल में ट्रांसफार्मर हाल के ठीक बाहर पार्किंग बे भी शामिल किया जा सकता है। यह सुरंग सुरक्षा कारणों से सुरंग के उल्टे हिस्से में नलिकाओं में दबी केबल के साथ केबल सुरंग के रूप में भी काम करेगी।

x. इंटरस्टेट/इंटरनेशनल पहलु

परियोजना सतलुज बेसिन में स्थित है, जो सिंधु बेसिन का एक हिस्सा है, और 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के उपयुक्त प्रावधान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चूंकि सतलुज सिंधु बेसिन की एक पूर्व में बहने वाली नदी है, इसलिए भारत को अपने जल बंटवारे पर विशेष अधिकार है।

xi. लागत का आकलन और वित्तीय पहलु

इस परियोजना पर जनवरी 2018 मूल्य स्तर पर आईडीसी और वित्तपोषण शुल्क सहित लगभग 1741.65 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। परियोजना की डिजाइन ऊर्जा 631.84 GWh पर आंकी गई

xii. निर्माण की अवधि

एलएचईपी चरण II परियोजना को 5 वर्षों में पूरा करना प्रस्तावित है।

xiii. लुहरी एचईपी-II की मुख्य विशेषताएं

परियोजना की मुख्य विशेषताएं टेबल 1.3 में दी गई हैं

टेबल 1.3. परियोजना की मुख्य विशेषताएं	
<b>1.0 स्थान</b>	
परियोजना का प्रकार	अधिकतम के लिए पाउंडेज के लिए आरओआर
नदी	सतलुज
राज्य	हिमाचल प्रदेश
जिला	शिमला, मंडी और कुल्हू
तहसील	कुमारसेन, करसोग और अन्नी
करीबी गांव (डैम साइट)	नानी (मंडी जिला)
रेल हेड	कालका (हरियाणा) 178 किमी.
डैम एक्सेस का लैटीट्यूड	30°20'22.5" N
डैम एक्सेस का लांगीट्यूड	77°20'58.46" E
<b>2.0 जल विज्ञान</b>	
डैम साइट पर कैचमेंट एरिया	52231 किमी. <sup>2</sup>
90% भरोसेमंद वर्ष	2001-2002
नदी के डायवर्जन की व्यवस्था के लिए फ्लड डिजाइन	756.00मीटर <sup>3</sup> /सेकेंड (सीवीसी के द्वारा अनुमोदित)
परियोजना के लिए डिजाइन फ्लड(पीएमएफ)	14862.00मीटर <sup>3</sup> /सेकेंड (सीवीसी के द्वारा अनुमोदित)
<b>3.0 जलाशय</b>	
जलाशय का पूर्ण स्तर (एफआरएल)	ईएल755.50मीटर
अधिकतम ड्रा डाउन लेवल (एमडीडीएल)	±EL 755.0मीटर
एफआरएल का कुल स्टोरेज	±13.55 X 10 <sup>6</sup> मीटर <sup>3</sup>

एफआरएल पर लाइव स्टोरेज	$\pm 5.44 \times 10^6$ मीटर <sup>3</sup>
डेड स्टोरेज	$\pm 8.11 \times 10^6$ मीटर <sup>3</sup>
डि सिल्टिंग बेसिन	जलाशय डि सिल्टिंग बेसिन के रूप में काम कर
<b>4.0 रिवर डाइवर्जन</b>	
रिवर डायवर्जन डिस्चार्ज (25 साल में 1)	765.00मीटर <sup>3</sup> /सेकंड (सीवीसी के द्वारा अनुमोदित)
डाइवर्जन स्क्रीम	डाइवर्जन टनल (डीटी) और कॉफर डैम्स के माध्यम से
डाइवर्जन टनल का स्थान	दांया किनारा
टनल्स की संख्या	एक(01)
डीटी का व्यास और शेप	10.5 मीटर घोड़े के नाल के आकार का
टनल की लंबाई	$\pm 793.0$ मीटर
<b>5.0 डैम</b>	
डैम का प्रकार	कंक्रीट ग्रेविटी
डैम का शीर्ष	इएल 759.00मीटर
डैम एक्सिस पर औसत रिवर बेड लेवल	इएल $\pm 718.00$ मीटर
रिवर बेड के ऊपर डैम की ऊंचाई	41.00 मीटर
शीर्ष पर डैम की लंबाई	147.13 मीटर
डैम की शीर्ष की चौड़ाई	8.00 मीटर
<b>6.0 स्पिलवे</b>	
टाइप	स्लुइस प्रकार के तहत
बे की संख्या	छह
गेट का पप्रकार और संख्या	रेडियल. छह(06)
<b>7.0 पावर इनटेक</b>	
इनटेक की संख्या	तीन (03)
डिजाइन डिस्चार्ज	$(491.98 + 169.12) = 661.10$ क्यूमेक्स
इनटेक 1 और 2 प्रत्येक की डिस्चार्ज क्षमता (मुख्य यूनिट के लिए)	245.99 क्यूमेक्स प्रत्येक
इनटेक 3 की डिस्चार्ज क्षमता(सहायक यूनिट के लिए)	169.12 क्यूमेक्स
<b>8.0 प्रेशर शॉफ्ट</b>	
प्रेशर शॉफ्ट की संख्या	तीन(03) जिसे आगे 6 में विभाजित किया गया है
प्रेशर शॉफ्ट 1 और 2 के लिए डिजाइन डिस्चार्ज (मेन यूनिट के लिए)	245.99 मीटर <sup>3</sup> /सेकंड
प्रेशर शॉफ्ट 3 के लिए डिजाइन डिस्चार्ज (मेन यूनिट के लिए)	169.12 मीटर <sup>3</sup> /सेकंड

<b>9.0 पावर हाउस</b>	
टाइप	भूमिगत
स्थान	बांया किनारा
सामान्य ट्रेल वाटर लेबल	±ईएल 722.30मीटर
न्यूनतम ट्रेल वाटर लेबल	±ईएल 717.00मीटर
ग्रास हेड	31.37मीटर
डिजाइन हेड	29.37मीटर
टर्बाइन टाइप	कप्लान
यूनिट्स की संख्या	छह (06) डिजाइन
डिस्चार्ज	661.19 मीटर <sup>3</sup> /सेकेंड स्थापित
मुख्य यूनिट्स की क्षमता	4 X 32.6 मेगावाट स्थापित
मुख्य यूनिट्स की क्षमता	1 X 32+1 X 12 मेगावाट
कुल स्थापित क्षमता	±172 मेगावाट*
<b>10.0 ट्रेल रेस टनल</b>	
संख्या	दो (02)
टनल का साइज	±9.7मीटर और ±8.7मीटर व्यास का घोड़े की नाल के आकार का
<b>11.0 बिजली का उत्पादन</b>	
डिजाइन ऊर्जा	631.84 जीडब्ल्यूएच(संभावित)
एनुअल लोड फैक्टर (मुख्य यूनिट)	40.35%
एनुअल लोड फैक्टर (पर्यावरणीय यूनिट)	50.70%

### 1.7 सहायक संरचनाओं की आवश्यकता

रिवर डाइवर्जन, डैम, पावर इनटेक, पावर हाउस, टेल रेस टनल, कनेक्टिविटी के लिए सड़क और कुलमिलाकर परियोजना विकास के भाग के रूप में अन्य भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न सहायक संरचनाओं का विवरण टेबल 4, परियोजना की मुख्य विशेषताओं में उपलब्ध कराया गया है।

### 1.8 शुरूवाती सामाजिक प्रभाव आकलन का विवरण

एसजेवीन ने एलएचईपी II परियोजना के लिए पहले सामाजिक प्रभाव का कोई मूल्यांकन नहीं किया है। हालांकि हालांकि, उन्होंने परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की सीमा और परियोजना विकास और प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित होने वाले मालिकों की सूची का विवरण एकत्र किया है।

डीपीआर को तैयार करने के लिए 11.06.2018 को पहली कंसल्टेशन मीटिंग की गयी। डीपीआर तैयार किया जा रहा है।



## अध्याय 2

# टीम की संरचना का दृष्टिकोण, कार्य पद्धति और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की अनुसूची

### 2.1 परिचय

सोशलइम्पैक्टअसेसमेंट (एसआईए), भूमिअधिग्रहण, पुनर्वासऔरस्थान-परिवर्तनअधिनियम2013 का "भूमि अधिग्रहण में ठीकमुआवजे का अधिकारऔरपारदर्शिताकाएकमहत्वपूर्णघटकहै।एसआईए सामाजिक आर्थिक, सामाजिक-

सांस्कृतिक,पर्यावरणीयपहलुओंकेसंदर्भमेंप्रभावितसमुदायोंपरएकविकासपरियोजनाकेपरिणामोंकाआकलनकरनेकेलिएएक उपकरणहै, ताकिपरियोजनाकीतैयारीकेचरणकेदौरानपहचानेगएसभीप्रतिकूलमुद्दोंकोदूरकरनेकेलिएउचितराहत देने वालीयोजनातैयारकीजासके।परियोजनाकेसामाजिकप्रभावऔरसार्वजनिकउद्देश्यकोनिर्धारितकरनेकेलिएमुख्यअधिनियम (RTFCTLARRA 2013) काचैप्टर- II प्रदानकियागयाहै।

अपनाई गयी प्रभाव मूल्यांकन पद्धति में इस परियोजना के विकास के कारण परिकल्पित संभावित सामाजिक प्रभावों की पहचान शामिल है। एसआईएने इस परियोजना के लिए स्थानीय कानूनों और नियमों का भी पालन किया।

यह खंड स्टडी के लिए शामिल टीम और उनके क्रेडेंशियल, सामाजिक मूल्यांकन के संचालन के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली, सूचनाओं को एकत्र करने के लिए अपनाए गए टूल, , प्रमुख हितधारकों (संस्थागत और समुदाय) के साथ परामर्श की अनुसूची के साथ सार्वजनिक परामर्शों के लिए कार्यप्रणाली का विवरण देता है।

### 2.2 योग्यता के साथ टीम के सदस्यों की सूची

इस एसआईएस्टडी को करने के लिए गठित प्रमुख पर्सनल के पास इस तरह की स्टडी करने के लिए वांछित योग्यता, अनुभव और कौशल सेट हैं।यह सामाजिक विज्ञान में योग्यता और लॉ पृष्ठभूमि के साथ एक बहु-विषयक टीम है।टीम को समान की प्रकार की स्टडीज करने का अनुभव है जैसे सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना, पुनर्वास और पुनर्स्थापन, भूमि अधिग्रहण, बेसलाइन सामाजिक आर्थिक सर्वे, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जैसी। बड़े पैमाने पर, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वे में टीम के सदस्यों का अनुभव वर्तमान स्टडी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस था।

डेटा संग्रह एक समर्पित टीम के द्वारा किया गया था और विश्लेषण एक समर्पित एनालिटिकल टीम के द्वारा किया गया था। फ़ील्ड ऑपरेशन को फ़ील्ड मैनेजर के द्वारा सह संचालित किया गया था, जिसे हाउसहोल्ड/लाभार्थी सर्वे करने, बड़ी फ़ील्ड टीमों का प्रबंधन करने, लॉजिस्टिक्स को प्रबंधित करने, डेटा कीगुणवत्ता सुनिश्चित करने, डेटा काविश्लेषण और वांछित परिणामों को समय पर प्रस्तुत करने में व्यापक अनुभव है।

टेबल 2.1 स्टडी के लिए शामिल टीम के सदस्यों और उनके पद और अनुभव के सालों को दिखाती है

टेबल 2.1 प्रोजेक्ट स्टडी टीम		
क्रमांक	प्रस्तावित पद	नाम
1.	टीम लीडर / प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर	श्री निहारेंदु जगतदेव

टेबल 2.1 प्रोजेक्ट स्टडी टीम		
क्रमांक	प्रस्तावित पद	नाम
2.	प्रोजेक्ट एडवाइजर	श्री मधुसूदन हनुमप्पा
3.	फील्ड मैनेजर, भूमि अधिग्रहण स्पेशलिस्ट और कम्यूनिटी मोबीलाइजेशन एक्सपर्ट	श्री राजीव कुमार सिंह
4.	जेंडर और डेवलपमेंट एक्सपर्ट	सुश्री मंजुश्री तालुकदार
5.	फील्ड सुपरवाइजर, सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्रामर	सुश्री सी जगती
6.	फील्ड सुपरवाइजर	सुश्री बबीता उपाध्याय
7.	इन्वेस्टीगेटर – 1	बिहारी लाल
8.	इन्वेस्टीगेटर – 2	शीतल
9.	इन्वेस्टीगेटर – 3	अफजल राजपूत
10.	इन्वेस्टीगेटर – 4	मोहम्मद अरशद
11.	इन्वेस्टीगेटर – 5	मनीष कुमार

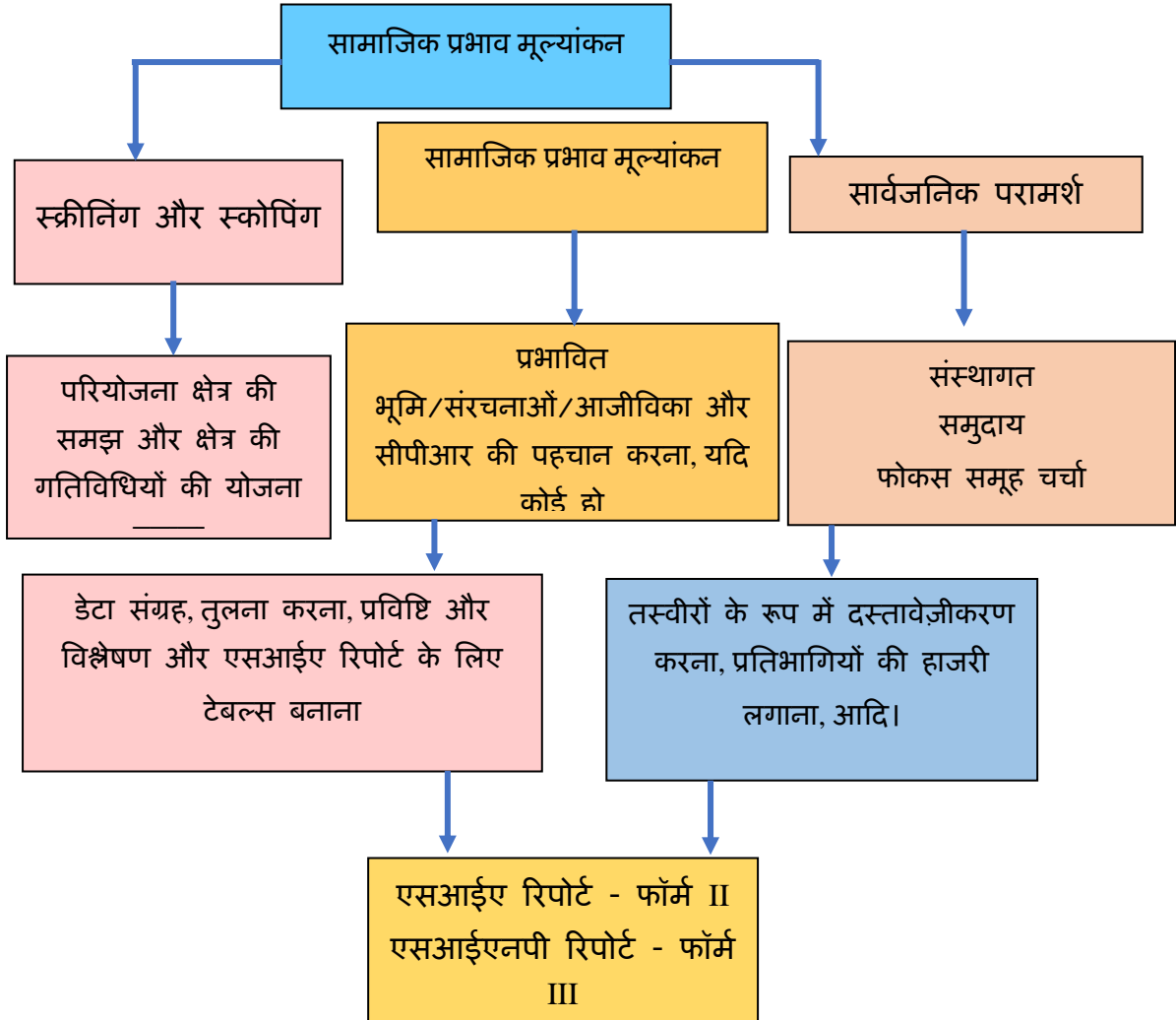
### 2.3 सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए जानकारी एकत्र करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कार्य पद्धति और टूल के लिए विवरण और तर्क

अपनाई गयी प्रभाव मूल्यांकन पद्धति में इस परियोजना के विकास के कारण परिकल्पित संभावित सामाजिक प्रभावों की पहचान शामिल है। एसआईएने इस परियोजना के लिए स्थानीय कानूनों और नियमों का भी पालन किया।

एसआईएप्रक्रिया परियोजना के सामाजिक प्रभावों की पहचान करने, और प्रभावों को कम करने, प्रबंधन और निगरानी के उपायों का वर्णन करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जो इन परिकल्पित प्रभावों का समाधान करने के लिए लागू किया जाएगा। अंततः, यह उचित संगठनों को विकास प्रस्तावों के बारे में सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है, और संभावित प्रभावित हितधारकों को प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देता है।

एक विस्तृत प्रभाव मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, एसआईएप्रक्रिया को प्रगतिशील और पुनरावृत्ति वाले चरणों की एक श्रृंखला पर बनाया गया है। हितधारकों, परियोजना और मूल्यांकन टीम ने एसआईएप्रक्रिया के दौरान इन चरणों को इनपुट प्रदान किए।

चित्र 2 : सामाजिक प्रभाव आकलन प्रक्रिया



परियोजना के अध्ययन की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें संबोधित करना और गंभीरता को कम करने के लिए सामाजिक मुद्दों की जांच करना शामिल है, जिसमें सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) शामिल है।

### 2.3.1 सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) प्रक्रिया के लिए दृष्टिकोण और पद्धति

परियोजनाएं, टाइटलहोल्डर और नॉन-टाइटलहोल्डर, दोनों की संपत्तियों पर प्रतिकूल प्रभावों की परिकल्पना करती हैं। इन प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिए एक सामाजिक प्रभाव आकलन किया गया था जो इन प्रभावों के कारण प्रभावित लोगों की श्रेणी, प्रतिकूल प्रभावों की सीमा की पहचान करने में सक्षम था और संबंधित हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित मुआवजा और सहायता प्रदान करने वाली पुनर्वास कार्य योजना तैयार करती हैं।

सलाहकार ने निम्नलिखित उप-कार्यों को किए हैं:

- परियोजनाओं से संबंधित सभी दस्तावेजों की समीक्षा की गई -पहले से तैयार डीपीआर, यदि कोई हो, तो अंतिम प्रभाव वाले क्षेत्र चित्र, जो प्रत्यक्ष प्रभाव का क्षेत्र दिखाते हैं, सरकारी और निजी भूमि की सूची परियोजना के विकास के लिए अस्थायी रूप से और स्थायी रूप से आवश्यक है, आदि
- परियोजना के उद्देश्यों, दायरे और परिचालन विशेषताओं से संबंधित सुरक्षा उपाय और गैर-सुरक्षा उपाय सामाजिक मुद्दे, और परियोजना के सत्यापन योग्य सामाजिक विकास परिणामों को निर्दिष्ट करें।
- स्थानीय रोजगार के अवसर, बाल श्रम, एचआईवी / एड्स और मानव तस्करी, सामर्थ्य, लिंग और अन्य सामाजिक जोखिमों को आंकना जो परियोजना के परिणामस्वरूप और सामाजिक प्रभावों को कम करने के उपायों के लिए शामिल किया जाता है, यदि कोई हो
- 'एचआईवी / एड्स रोकथाम कार्य योजना' तैयार करें जो विशेष समुदायिक समूहों के सामान्य जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करेगा, और जो परियोजना की सुविधा में और उसके आसपास काम करेंगे।
- लिंग, मजदूर, एचआईवी, तस्करी, और उपरोक्त विश्लेषण में पहचाने गए अन्य सामाजिक पैरामीटर को संबोधित करने के लिए फॉलो-ऑन निवेशों (किसी भी तकनीकी सहायता की आवश्यकता सहित) में समावेश किए जाने के लिए प्रस्तावित डिजाइन की विशेषताएं और उपाय।
- सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं (लिंग, जातीय और स्वदेशी अल्पसंख्यकों; सामाजिक आर्थिक आलोचनीयता, आदि) के संदर्भ में प्रमुख स्टैकहोल्डर समूहों के साथ स्टैकहोल्डर परामर्श जो परियोजना के उद्देश्यों और दायरे से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे, डिजाइन विकल्प, संभावित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, प्रतिकूल प्रभावों गंभीरता को कम करने के लिए संभावित उपाय और अन्य जानकारियां जिसका स्टैकहोल्डर्स के लिए उपयोग किया जाएगा। सलाहकार ऐसे स्टैकहोल्डर परामर्शों के रिकॉर्ड रखेगा।
- हितधारक के हिस्से के रूप में समुदाय (घरों/उद्यमों/सार्वजनिक संस्थानों) सहित टारगेट ग्रुप एनालिसिस का विश्लेषण करता है जो पावर प्लांट में उत्पन्न ऊर्जा की पहुंच है और/या जो परियोजना से प्रभावित है, का संचालन भी किया गया था। अध्ययन से अंतिम उपयोगकर्ताओं और स्टैकहोल्डर्स की पहचान होगी जो परियोजना विकास से सकारात्मक या प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी जिसमें घर, उद्योग, सार्वजनिक संस्थाएँ आदि शामिल हैं, और परियोजना के जोखिमों और संभावित प्रभाव (ऊर्जा पहुंच/आपूर्ति, सामाजिक प्रभाव, आय पर प्रभाव, श्रम बाजार की स्थिति/रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी, ग्रामीण, जनसंख्या आकार के विकास आदि) का वर्णन करते हैं। अध्ययन ने आजीविका और सामाजिक ताने-बाने से संबंधित जोखिमों और प्रभावों तक भी पहुंच की। सलाहकार ने विश्लेषण किया है कि परियोजना क्षेत्रीय और/या राष्ट्रीय योजनाओं और रणनीतियों की उपलब्धि में कैसे योगदान देगी (जैसे कि गरीबी को कम करने के लिए/जनसंख्या की समस्या को सुधारना)।
- 
- हितधारकों की भागीदारी के साथ, जोखिम वाले समूहों की कमी के पीछे की कारणों की पहचान और विश्लेषण, उनके जोखिमों का पता लगाना शामिल हैं। परियोजना को डिजाइन और कार्यान्वित करते समय प्रमुख स्टैकहोल्डर्स के लिए भागीदारी विकास रणनीतियां लागू करें।

- सभी परियोजनाओं के परियोजना स्थान और उसके आसपास के लिंग विकास के लिए परियोजना विशिष्ट 'लिंग कार्य योजना' तैयार करना। परियोजना डिजाइन के तत्वों (नीति या कार्यान्वित) की पहचान करें जिसमें महिलाएं भाग ले सकती हैं और इस तरह परियोजना से लाभान्वित हो सकती हैं।
- 
- अनुमोदित और प्रकाशित के रूप में भूमि अधिग्रहण (यदि आवश्यक हो) से संबंधित हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण कानून और आरटीएफसीटीएलएआरआरए, 2013 की समीक्षा करना। कोई अन्य राज्य स्तरीय संबंधित नियम भी लागू हो सकते हैं।
- एक स्टैकहोल्डर एंगेजमेंट प्लान (एसईपी) तैयार करना
- बेसलाइन सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट्स और अन्य संबंधित दस्तावेजों के लिए प्रारूपों की समीक्षा।
- इस सर्वेक्षण की परियोजना और आउटपुट के लिए सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करके परियोजना के विकास के परिणामों में वृद्धि करने और प्रतिकूल प्रभावों से गंभीरता को कम करने से पुनर्वास कार्य योजना को तैयार करने का आधार बनेगा।
- पूरे कॉरिडोर के विस्तार के साथ गाँवों के प्रत्येक भू-राजस्व मानचित्रों को एकत्रित करना, डिजाइन कॉरिडोर के साथ ही आंकीकरण करना, प्रभावित सर्वेक्षण संख्याओं को सूचीबद्ध करना, संपत्ति खोने वाले परिवारों में से प्रत्येक के स्वामित्व के रिकॉर्ड को इकट्ठा करना, भूमि अधिग्रहण योजना को तैयार करना, आदि।
- सामाजिक मूल्यांकन और भूमि अधिग्रहण योजना से प्राप्त इनपुट सहित पुनर्वास कार्य योजना तैयार करना।
- निर्माण के दौरान प्रतिकूल प्रभावों से बचने और कम करने के लिए गंभीरता को कम करने वाले उपायों को विकसित किया जाएगा, एसजेवीएन के साथ समन्वय से पहले प्रकटीकरण और प्रस्ताव का संचालन और समाप्त किया जाएगा।
- परियोजनाओं के विभिन्न चरणों के दौरान सभी स्टैकहोल्डर्स को शामिल करने वाले सहभागी दृष्टिकोण का उपयोग करके गंभीरता कम करने वाले उपायों को विकसित करना।

इस सामाजिक प्रभाव आकलन में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

- संभव भूमि अधिग्रहण, संरचनात्मक प्रभाव सहित, स्थायी और अस्थायी पुनर्वास प्रभावों की सर्वेक्षण सूची (तस्वीरों या वीडियोग्राफी सहित) को विस्तृत रूप से किया जाना।
- 
- अन्य संभावित सामाजिक प्रभावों की जांच और मूल्यांकन करना।
- टाइलहोल्डर्स और नॉन-टाइलहोल्डर्स को शामिल करते हुए वर्तमान में प्रभावित (प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों सहित) उन सभी की जनगणना सर्वे करना।
-

- एसआईए के माध्यम से पहचाने गए प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पुनर्स्थापन योजना आयोजित करना और परियोजना के विकास परिणामों को बेहतर बनाना।

सामाजिक प्रभाव की गंभीरता को कम करने की योजना में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

परियोजना के प्रभावों की सर्वे सूची और प्रभावित जनसंख्या का जनगणना सर्वे।

लागू की गई उपयुक्त सरकार की नीतियों के अनुपालन की समीक्षा;

पुनर्वास के बाद के समर्थन, साथ ही भूमि अधिग्रहण और आवश्यक आजीविका पुनःस्थापन के हस्तक्षेपों सहित, पहचान किए गए सामाजिक प्रभावों को संबोधित करने के लिए रणनीति और कार्य योजना तैयार करना;

उपरोक्त रणनीति और कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए प्रभावित आबादी सहित स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करना

सामाजिक प्रभाव गंभीरता को कम करना और अन्य सामाजिक हस्तक्षेपों की लागत का आकलन करना, और अनुमानित बजट प्रदान करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों और दायरे के अनुसार, परियोजना अध्ययन ने इस परियोजना के अंतर्गत मुख्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली को अपनाया गया है।

सामाजिक प्रभाव आकलन सर्वे के माध्यम से प्रभावित लोगों (परिवारों/लोगों) के उनकी जीवन की गुणवत्ता और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल पर उचित जानकारी एकत्र करने के लिए मूल्यांकन किया है। बेसलाइन सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली का विवरण टेबल 2.2 में दिया गया है।

सर्वे- माध्यमिक डेटा एकत्रित करना (डेस्क समीक्षा)

मापदंड	विवरण	डेटा के स्रोत
सामान्य पहचान	स्थान - राज्य, जिला, शहर/गाँव आदिद्वारा।	पहले से क्लाइंट एजेंसी से उपलब्ध प्रकाशित नक्शे और जानकारी, प्रकाशित जानकारी।
जनसांख्यिकी की विशेषताएं	कुल जनसंख्या पुरुष / महिला वितरण; साक्षरता का स्तर; और उपलब्ध कोई भी अन्य जानकारी	भारत की जनगणना, 2011 इन मापदंडों पर हाल की जानकारी के लिए कोई अन्य प्रकाशित पेपर्स या उपलब्ध डेटा
सामाजिक-आर्थिक विशेषताएं	उम्र, जाति, परिवार और लिंग; वैवाहिक स्थिति; आय;	अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय

	खुदकीसंपत्ति; शिक्षायोग्यतापैटर्न; व्यवसायपैटर्न; स्वास्थ्य; कमजोरदलितों (मुस्लिम/हिंदू) धार्मिकअल्पसंख्यकोंकाविवरण, एससीऔरएसटीसबसेपिछड़ेहैंआ दि; तथा कोईअन्यसंबंधितजानकारी	इनमापदंडोंपरहालकीजानकारीकेलिए कोईअन्यप्रकाशितपेर्सयाउपलब्धडे टा
<b>कौशल</b>	परियोजनाक्षेत्रकेभीतरकौशलकी पहचानकरना	प्रकाशितस्टडीज़,आदि
<b>संरचनाओं का कीमत</b>	संरचनाओंकामूल्योंकन निर्माणसामग्रीऔरश्रममजदूरीका मूल्य,आदि	प्रकाशितबाजारदरें दरोंकीबुनियादीसूची
<b>भूमि की कीमत</b>	राजस्वकीसर्कलदरें प्रभावितसंपत्तियोंकेआस- पासकेराजस्वकीसर्कलदरोंकीसर्क लदरें	राजस्वविभाग ग्रामपंचायतें अन्यरिपोर्टकासार्वजनिकबजटमूल्यों कन, जिसमेंविकासपरियोजनाओंनेपरियो जनासंरेखणकेआस- पासकेस्थानोंमेंभूमिकाअधिग्रहणकि याहै।
<b>नीतियां/अ धिनियमों</b>	हिमाचलप्रदेशसरकार भारतसरकार	हिमाचलप्रदेशसरकारकाभूमिकानून आवश्यकतानुसारकोईभीअन्यसुरक्षा नीतियां

बेसलाइन सर्वे

<b>टेबल 2.3. बेसलाइनप्राथमिक मापदंड और उनका विवरण</b>	
<b>मापदंड</b>	<b>विवरण</b>
सामान्य पहचान	स्थान- राज्य, जिला, शहर/गांव द्वारा आदि; संपर्क का विवरण पहचान पत्र की प्रतिलिपि या नम्बर; और घर/परिवार का पता लगाने के लिए कोई अन्य सीमा चिह्न।
जनसांख्यिकी विशेषताएं	कुल जनसंख्या; पुरुष/महिला वितरण; तथा

	18 वर्षों से कम और अधिक लोगों की संख्या
सामाजिक-आर्थिक विशेषताएं	उम्र, जाति, परिवार और लिंग; वैवाहिक स्थिति आय; खुद की संपत्ति; शिक्षा योग्यता पैटर्न; व्यवसाय पैटर्न; स्वास्थ्य परिवार के भीतर भूमि/संपत्ति (सभी प्रभावित संपत्ति सहित) के स्वामित्व विवरण; कमजोर प्रभावित परिवारों का विवरण; तथा कोई अन्य संबंधित जानकारी।
कौशल	परिवार के सदस्यों के कौशल सेट यदि कोई हो
Categories of Impact प्रभाव की श्रेणियाँ	संपत्ति का प्रकार- संरचनाएं और भूमि
प्रभाव का स्तर	प्रभावित परिवार/घर की खुद की कुल संपत्ति की तुलना में नुकसान/प्रभाव का स्तर

बेसलाइन सर्वे एक गतिविधि है, जो किसी भी विकास परियोजना के लिए प्राथमिक है। प्रत्येक परिवार के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल पर जमीनी स्तर की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, जो भी लागू हो सकता है, एक आधारभूत सर्वे किया जाता है। यह जानकारी, इसलिए एकत्रित की गई, परियोजना स्थिति के तैयारी के चरण के संबंध में विचार के अंतर्गत घरेलू/परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की तुलना के लिए बेंचमार्क प्रदान करता है। यह परियोजना के अंतर्गत घर/परिवारों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण और पुर्नस्थापन कार्य योजना (एलएआरएपी) को डिजाइन करने के लिए आगे की जानकारी प्रदान करता है।

सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए जानकारी एकत्र करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स

रिसर्च टूल्स और उपकरणों का विकास

सर्वे करने के लिए डिजाइन किए गए टूल्स दो श्रेणियों के हैं, उनमें संरचनाएं प्रश्नावली और असंरचित जांच सूची शामिल हैं। इसका उपयोग संवादात्मक और चर्चा स्तर सूचना दोनों को इकत्र करने के लिए किया जाता है जैसा कि टेबल 2.4 में दिया गया है।

टेबल 2.4. प्राथमिक सर्वे के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल्स	
मापदंड	विवरण
संरचित प्रश्नावली	घरेलू / पारिवारिक स्तर पर।
जाँच सूची	कमजोर समूहों; महिला समूहों; तथा

टेबल 2.4. प्राथमिक सर्वे के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल्स	
मापदंड	विवरण
	आवश्यकतानुसार किसी अन्य समूहों

एसआईए और एसआईएमपी के दायरे के अनुसार, सर्वे में कवर किए गये मुद्दों को एलएचईपी के अधिकारियों और एचआईपीए की एसआईए यूनिट के साथ परामर्श से अंतिम रूप दिया गया था। स्टडी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक संरचित सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रश्नावली का उपयोग निम्नलिखित व्यापक जांच क्षेत्रों को शामिल करने के लिए किया गया था:

परियोजना स्थान की सामान्य पहचान

संपत्ति का नुकसान और संपत्ति का प्रकार

संपत्ति के स्वामित्व विवरण

संपत्ति पर उपयोगिताएँ

भूमि और संरचना की माप

संरचना का प्रकार

भूमि का उपयोग, मृदा प्रकार और सिंचाई संकाय

उगाई जाने वाली फसलें, उत्पादन और मूल्य

परिवार का विवरण (धर्म, जाति, परिवार का प्रकार, आर्थिक स्थिति)

परिवार के सदस्यों का विवरण (संख्या, लिंग, उम्र, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता/शिक्षा, स्वास्थ्य स्थिति, रोजगार की स्थिति, व्यवसाय का प्रकार, आय, प्रवासी स्थिति, मौजूदा कौशल, आजीविका वरीयता)

सामाजिक और सांस्कृतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और नागरिक समाज संगठन

स्वास्थ्य, बिजली, ईंधन, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता तक पहुंच

परिवहन का साधन (उपलब्धता और उपयोग)

लैंगिक पहलू

खुद की भूमि और संरचनाओं का विवरण (प्रभावित संपत्तियों के अलावा)

घरेलू संपत्ति के कब्जे पर विवरण

घरेलू आय और खर्चों का विवरण

खाद्य सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा

ऋण और ऋणग्रस्तता तक पहुंच

सरकारी योजनाओं से प्राप्त किया गया लाभ

प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना पर ज्ञान और जागरूकता

पुनर्स्थापन की प्राथमिकताएं (यदि हाउस, दुकान, भूमि प्रभावित है) और पुनर्वास की आवश्यकता है

रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, स्टडी के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट/लिटरेचर के विषय और समीक्षा पर इसी तरह के सर्वे में हमारे पिछले के अनुभव के आधार पर डिजाइन किया गया था।

## दूल्स का पूर्व परीक्षण

वास्तविक क्षेत्र की परिस्थितियों में प्रश्नावली की अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए, कुल्लू जिले के कुमारसैन तहसील के एक गांव में फील्ड प्रबंधकों के साथ संगठन के वरिष्ठ पेशेवरों द्वारा क्षेत्र में प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण किया गया था।

प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण निम्नलिखित जांच को करने के लिए किया गया था।

भाषा की स्पष्टता के संदर्भ में प्रश्नों को समझने की क्षमता, आसानी का वह स्तर, जिसके साथ प्रतिवादी प्रश्नावली में इस्तेमाल की गई शब्दावली से पहचान कर सकता है।

- प्रश्नावली में तार्किक प्रवाह और सवालों का अनुक्रमण
- प्रश्नावली में स्किप करने का क्रम
- प्री-कोडेड प्रतिक्रियाओं, नई प्रतिक्रियाओं आदि की थकावट।

रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को पूर्व-परीक्षण के फीडबैक/निष्कर्षों के आधार पर संशोधित किया गया था। तब रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को एलएचईपी स्टेज-II के संबंधित अधिकारियों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया। इस स्टडी के लिए उपयोग की गई घरेलू प्रश्नावली को **अनुबंध 2** के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

## 2.4 नमूना लेने के लिए पद्धति

एसआईए को अगस्त और सितंबर 2019 के महीने के दौरान एलएचईपी स्टेज- II के परियोजना क्षेत्र में किया गया था। यह एक जनगणना सर्वे था और सभी प्रभावित परिवारों का सर्वे किया गया था। बेसलाइन जानकारी को स्पष्ट करने के लिए एसआईए और सामाजिक-आर्थिक का सर्वे किया गया था।

परियोजना का विकास प्रभावित परिवारों पर प्रभाव की परिकल्पना करता है जो अपनी भूमि और संरचनाओं को खो देंगे और जिन परिवारों की आजीविका सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुई थी। एसजेवीएन से प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की कुल संख्या 324 थी। प्रारंभ में चमोद मोहाल में पीएएफ की संख्या 4 थी। हालाँकि, एसआईएके सर्वे के दौरान यह पाया गया कि एक घर की भूमि को 4 भागों में उप-विभाजित किया गया था। इसलिए चमोद मोहाल में पीएएफ की संख्या बढ़कर 7 हो गई। इसके अलावा, डिंगिधर मोहाल में पीएएफ की संख्या 66 थी। हालाँकि, एसआईएके सर्वे के दौरान, यह पाया गया कि पीएएफ की एक भूमि 7 भागों में उप-विभाजित है। इसलिए चमोद मोहाल में पीएएफ की संख्या बढ़कर 72 हो गई। तदनुसार, इन अतिरिक्त पीएएफ का साक्षात्कार किया गया था और जानकारी एकत्रित की गई थी। तो, इन 9 अतिरिक्त पीएएफ सहित, कुल मिलाकर एलएचईपी स्टेज- II के अंतर्गत पीएएफ की 324 संख्या वास्तविक संख्या के मुकाबले बढ़कर 333 हो गई। क्षेत्र की यात्रा के समय, एसआईएके सर्वे के दौरान, कुछ पीएएफ गाँव में उपलब्ध नहीं थे। इन 333 पीएएफ में 116 परिवारों को सर्वे के दौरान कवर नहीं किया जा सका, चूंकि अधिकांश परिवारों को अन्य स्थानों/जिलों में स्थानांतरित कर दिया गया है और कुछ ने साक्षात्कार देने से इनकार कर दिया। उपलब्ध 217 पीएएफ के लिए सामाजिक प्रभावों पर डेटा प्रदान किया गया है और तदनुसार रिपोर्ट में शामिल किया गया है। एसआईए के सर्वे के

अनुसार, सभी 333 पीएएफ को टाइटल्होल्डर पाया गया, हालांकि यहां कोई भी नॉन-टाइटल्होल्डर नहीं हैं जो इस परियोजना के विकास के कारण प्रभावित हैं।

### 2.4.1 नमूना कवरेज

जैसा कि पहले बताया गया, एलएचईपी स्टेज- II के अंतर्गत प्रभावित होने वाले सभी परिवारों से सर्वे के लिए संपर्क किया गया था। एसजेवीएन द्वारा साझा की गई सूची के अनुसार कुल प्रभावित परिवारों का विवरण 324 है। इसमें से हमने कुल 208 परिवारों को कवर किया है और शेष 116 परिवार सर्वे के समय उपलब्ध नहीं थे, या चले गये हैं, और कुछ ने सामाजिक सर्वे प्रश्नावली के अनुसार जानकारी प्रदान करने से इनकार कर दिया है जिसका हमने सामाजिक सर्वे करने के लिए उपयोग किया है। हालांकि, सूची में कवर्ड 208 परिवारों के अलावा, हम 9 परिवारों की पहचान करने में भी सक्षम हुए हैं, जो कि प्रभावित थे और उन्हें वर्तमान में मौजूदा भूमि पार्सल से भूमि विभाजन प्राप्त किया है।

### 2.5 सूचना/डेटा स्रोतों का अवलोकन

एसआईए स्टीके के लिए उपयोग की जाने वाली जानकारी और डेटा स्रोतों का विवरण टेबल 2.5 में दिया गया है।

टेबल 2.5 डेटा स्रोत		
क्र.सं.	डेटा	स्रोत
<b>I.</b>	<b>माध्यमिक डेटा</b>	
1.	सामाजिक- आर्थिक प्रोफाइल	भारत की जनगणना, 2011
		राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 (2015-16)
		स्वास्थ्य विभाग: शिमला, कुल्लू और मंडी
		आईसीडीएस: शिमला, कुल्लू और मंडी
		सार्वजनिक वितरण प्रणाली: शिमला, कुल्लू और मंडी
2.	भू राजस्व डेटा	राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
<b>II.</b>	<b>प्राथमिक स्रोत - बेसलाइन सर्वे</b>	
1.	सामाजिक- आर्थिक प्रोफाइल	परिवार - घर का मुखिया या सदस्य जो बेसलाइनसर्वे के समय परिवार के बारे में अधिकतम जानकारी प्रदान कर सकता है
<b>III.</b>	<b>प्राथमिक स्रोत - सार्वजनिक परामर्श</b>	
1.	संस्थागत	एजेंसी की चर्चाओं को लागू करना
		स्थानीय एनजीओ
		पीडब्ल्यूडी
		सिंचाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग
		शिक्षा विभाग
		उद्योग विभाग
		मत्स्य विभाग
2.	समुदाय	महिला समूह के साथ एफजीडी

		अल्पसंख्यक समूह (सामाजिक और धार्मिक) के साथ एफजीडी
		समुदाय और गांव के नेताओं के साथ परामर्श

## 2.6 प्रमुख स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श की अनुसूची

### 2.6.1 पृष्ठभूमि

स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट एक रचनात्मक और उत्तरदायी संबंध स्थापित करने की नींव है जो परियोजना के सामाजिक प्रभाव के सफल प्रबंधन के लिए बहुत आवश्यक है। यह एक नियामक प्रक्रिया है जिससे प्रभावित करने वाले मामलों पर लोगों का इनपुट प्राप्त होता है। इस परामर्श और परियोजना के तैयार चरण से विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के एंगेजमेंट को सुचारू रूप से कार्यान्वित करना और लंबी अवधि में एसजेवीएन के लिए परियोजना के संचालन चरणों को भी सक्षम बनाएगा।

सामाजिक मूल्यांकन और पर्यावरण अध्ययन पर काम कर रही प्रोजेक्ट स्टडी टीम द्वारा सितंबर 2019 के दूसरे सप्ताह में एक स्टेकहोल्डर परामर्श और सह-भागिता प्रक्रिया शुरू की गई, साइट की जगहों पर और एलएचईपी स्टेज- II साइट के आसपास रहने वाले गांवों के सामुदायिक सदस्यों के साथ परामर्श बैठकों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया। परामर्श बैठकों की श्रृंखला परियोजना के दायरे और कार्यप्रणाली पर स्टेकहोल्डर्स की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने और एकत्र करना के लिए कार्य करती है।

### 2.6.2 सार्वजनिक परामर्श का उद्देश्य

मुख्य उद्देश्य हैं:

हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए समुदाय और अन्य स्टेकहोल्डर्स के बारे में बताना और प्रचार करना और बिजली परियोजना के साथ-साथ विकसित की जा रही विभिन्न भौतिक सुविधाएं; संचालन के माध्यम से तैयारी के सभी चरणों में परियोजना के स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट, दक्षता, पारदर्शिता और सार्वजनिक सहभागिता में सुधार करना; तथा एसआईएस्टडी रिपोर्ट के हिस्से के रूप में शामिल होने के लिए सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स से इनपुट और सिफारिशें प्राप्त करना।

### सार्वजनिक परामर्श का दायरा

सार्वजनिक परामर्श के दायरे में एलएचईपी स्टेज- II परियोजना स्थल के सामाजिक प्रभावों की पहचान करना शामिल था। कवर किए गए मुद्दे परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए सतत विकास, आजीविका, शिकायत और न्याय थे।

परामर्श ने समुदाय पर परियोजना के विभिन्न सामाजिक प्रभावों और प्रतिकूल प्रभावों की गंभीरता को कम करने को कवर किया। इस दायरे में परियोजना के सकारात्मक और प्रतिकूल विकास प्रभावों पर हितधारकों की धारणा को समझना शामिल था।

इस अभ्यास ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या एलएचईपी स्टेज- II परियोजना की परियोजना गतिविधियों से मूल निवासियों के कोई समूह प्रभावित होगा।

इस प्रक्रिया में परियोजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मूल्यांकन, दस्तावेजीकरण और हितकारकों की जरूरतों का प्रबंधन करने की आवश्यकता शामिल थी। सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को एकत्र करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि उनकी राय को ध्यान में रखा गया, जिसने इस परियोजना के लिए स्टैकहोल्डर एंगेजमेंट रिपोर्ट तैयार करने में भी मदद की।

## कार्यपद्धति और प्रक्रिया

सितंबर 2019 के दौरान परियोजना की स्टडी टीम केद्वारा परियोजना स्थल का दौरा किया गया था। टीम ने परियोजना से संबंधित हितधारकों के साथ बैठक की और परियोजना स्थल पर सार्वजनिक परामर्श किया। बैठक के उद्देश्य, तिथि, समय और स्थल के बारे में समुदाय को पहले से सूचना दी गई थी।

परामर्श प्रक्रिया के तहत समुदाय के साथ बैठकें गांव स्तर पर आयोजित की गयी थीं। समुदाय के लोगों के साथ प्रभावित गांवों की यात्रा की गई थी।

परामर्श प्रक्रिया का उचित दस्तावेजीकरण किया गया था, मतलब बैठकों की फोटोग्राफी। बैठक में उनकी भागीदारी के लिए सभी प्रतिभागियों से हस्ताक्षर लिए गए थे। समुदाय के साथ चर्चा और संचार का माध्यम हिंदी में था जो स्थानीय बोलचाल की भाषा है। यह सुनिश्चित करने के लिए सहभागी प्रक्रिया अपनाई गई थी कि सभी सदस्य भाग लें और अपने विचार व्यक्त करें और वस्तुगत प्रतिक्रिया प्रदान करें।

परियोजना स्टडी टीम में सामाजिक विशेषज्ञ, लिंग विशेषज्ञ और फील्ड मैनेजर शामिल थे। टीम के सदस्य की सूची अनुलग्नक 3 के रूप में संलग्न है।

## हितकारक

सार्वजनिक परामर्श या सामुदायिक भागीदारी किसी भी परियोजना का एक अभिन्न अंग और प्रक्रिया है जिसमें पुनर्वास या पुनर्स्थापन के मुद्दे शामिल होते हैं। यह विकास के मूल्यवान स्थानीय सुझावों और धारणाओं को शामिल करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में, हितधारकों को मुद्दों को पता लगाने करने का अवसर मिलता है, जो डिजाइन और वैकल्पिक अंतिम रूप दिए जाने में उचित परिवर्तन करने के बाद हल हो जाते हैं। हितधारक विकास योजनाओं से परिचित हो जाते हैं और उसी समय इन पहलों, निर्णयों और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए प्रभावित और साझा करते हैं। सामुदायिक परामर्श भी परियोजना के विरोध से बचने में मदद करते हैं, जो अन्यथा होने की संभावना होती है।

परामर्श की दो श्रेणियां हैं जिन्हें परियोजना से प्रभावित विभिन्न गांवों में आयोजित स्टैकहोल्डर एंगेजमेंट के दौरान किया गया था। उनमें शामिल हैं:

संवादी इंटरव्यूज	<ul style="list-style-type: none"> <li>- स्थानीय ग्राम स्तर पर प्रभावित हितधारक</li> <li>- समुदाय प्रमुख, ग्राम पंचायत सदस्यके रूप में व्यक्ति</li> </ul>
------------------	---

कमजोर समूहों के साथ ग्रुप डिस्कशन	<ul style="list-style-type: none"> <li>- महिला समूह</li> <li>- धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समूह</li> <li>- सामाजिक रूप से अल्पसंख्यक समूह</li> </ul>
-----------------------------------	--

परियोजना क्षेत्र में सार्वजनिक परामर्श संरेखण के साथ विभिन्न गांवों में आयोजित किया गया था। इस परियोजना में सार्वजनिक परामर्श करने के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाई गई थी:

प्रभावित लोगों के साथ व्यक्तिगत इंटरव्यू; और

प्रभावित लोगों की राय और पसंद को साझा करना।

आयोजित परामर्श का सारांश टेबल 2.6 में प्रदान किया गया है। सार्वजनिक परामर्श के दौरान भाग लेने वाले प्रतिभागियों की उपस्थिति इस रिपोर्ट में अनुबंध 4 के रूप में संलग्न है। परामर्श का चित्र अनुबंध 5 में दिया गया है

टेबल 2.6 परामर्श का सारांश				
मुद्दे/धारणा	मुख्य बिंदु	लोगों की टिप्पणियां/चिंताएं	परामर्श के दौरान सुझाव	परियोजना योजना में एकीकरण
परियोजना का विकास	भूमि पर प्रभाव जहां परियोजना भौतिक अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा।	लोगों ने बताया कि उनकी संपत्ति पर प्रभाव, खासतौर इन मामले में यह भूमि है और उनमें से कुछ उत्पादक कृषि भूमि जिसे जब तक संभव हो कम करना चाहिए हालांकि, यदि आवश्यक हो, तो इसे उचित और समय पर मुआवजे के भुगतान के साथ स्वीकार किया जा सकता है।	जहां तक संभव हो जमीन सरकारी क्षेत्र से अधिग्रहित की गयी है। केवल न्यूनतम निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है	मुआवजे का भुगतान आरटीएफसीटीएलएआरआरए, 2013 की धारा 46 के आधार पर किया जाएगा जो समय पर भुगतान के लिए प्रदान करेगा

निर्माण के दौरान आय का नुकसान	निर्माण गतिविधियों के कारण कृषि फसलों और पेड़ों पर प्रभाव और जमीन पर प्रतिबंधित गतिशीलता और पहुँच	निर्माण की इस अवधि का मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि इस अवधि के दौरान आय के नुकसान के कुछ प्रतिशत को कुछ हद तक कवर किया जा सके।	इस प्रभाव को आरटीएफसीटीएलएआरआरए, 2013 की दूसरी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार कवर किया जाएगा
मुआवजा पैकेज	मात्रा और मुआवजे की गणना का आधार	लोग जानना चाहते थे कि कैसे और क्या आधार अपनाया जाएगा और उम्मीद करेंगे कि उनके नुकसान के लिए उचित मुआवजे की गणना की जा सकती है।	यह आरटीएफसीटीएलएआरआरए, 2013 अधिनियम पर आधारित है, इसलिए उसके अनुसार मुआवजे पर नुकसान की गणना में कोई विसंगति नहीं होगी।
मुआवजे का समय पर मिलने का प्रावधान	मुआवजे के लिए निर्धारित समय	लोगों को जानने के लिए दिलचस्पी थी, और परियोजना अधिकारियों को मुआवजे के भुगतान की उचित तयसीमा देनी चाहिए और उसके अनुसार उसका पालन करना चाहिए	इसे आरटीएफसीटीएलएआरआरए, 2013 के प्रावधानों द्वारा निर्देशित किया गया है। इस प्रकार, तदनुसार इस अधिनियम में परिभाषित मुआवजा के भुगतान के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।
स्थान परिवर्तन	यदि संभव हो तो परियोजना के विकास के	लोग अपनी भूमि प्रदान करने के लिए सहमत हो	परिणाम संरेखण को अंतिम रूप देने से पहले विकल्पों की जांच की गई है।

	स्थान पर स्थानांतरित करना	गए हैं, लेकिन परामर्श के दौरान बताया है कि यदि संभव हो तो, परियोजना स्थान को कुछ मीटर की दूरी पर स्थानांतरित करें ताकि उनकी उत्पादक भूमि का कुछ हिस्सा या कुछ फल देने वाले पेड़ों को बचाया जा सके।	
महिलाओं की भागीदारी	लिंग विशेष और महिला फील्ड सुपरवाइजर के द्वारा महिला समूहों के साथ अलग से बातचीत की गई	सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन चरण के दौरान एफजीडी को करने के लिए महिला उम्मीदवारों का होना प्रस्तावित है।	चर्चा के दौरान महिलाओं से परामर्श किया गया हैकार्यान्वयन के दौरान रोजगार प्रदान करने और कौशल सेट और योग्यता के आधार पर रोजगार के बारे में उनकी राय ली गयी

## समुदाय से मुख्य निष्कर्ष और प्रतिक्रिया

निष्कर्षों के सारांश में शामिल हैं:  
सकारात्मक चिंताएं और निष्कर्ष

परियोजना की शुरुआत के बारे में चिंता:

समुदाय के सदस्यों ने परियोजना शुरू होने का सही महीना और वर्ष जानने की जरूरत व्यक्त की। ग्रामीणों ने सुझाव दिया है कि अधिकारियों को परियोजना की शुरुआत और पूरा होने के समय के बारे में पहले से सूचित करना चाहिए।

परियोजना गतिविधियों के लिए स्थानीय श्रम शक्ति को शामिल करना:

स्थानीय समुदाय के साथ चर्चा के दौरान यह पता चला कि गांवों के ग्रामीणों के प्रमुख व्यवसाय प्रभावित होने वाले हैं या आसपास के गांव कृषि और श्रम कार्य हैं। बहुत कम परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि है, लेकिन प्रतिकूल प्रभाव जैसे असमान इलाकों और सिंचाई की कमी के कारण उत्पादकता बहुत कम है। मक्का इस क्षेत्र में साल में एक बार उत्पादित होने वाला एकमात्र अनाज है।

अधिकतर घरों की जीविका मजदूरी के काम पर निर्भर है। अधिकतर लोग सड़क निर्माण और सड़क की मरम्मत के लिए मजदूरी का काम पाने के लिए स्थानीय निजी ठेकेदारों पर निर्भर हैं। इसके अलावा गाँव स्तर में कृषि मजदूरी या निर्माण कार्य जैसे अन्य मजदूरी के काम की उपलब्धता बहुत कम है। क्षेत्र के लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत बहुत कम मजदूरी का काम मिलता है। ।

समुदाय के लोगों के अनुसार अकुशल मजदूरी के लिए मजदूरी की दर रु. 350 / - प्रति दिन है जहां कुशल श्रम के लिए यह 500/- रु। है। पुरुषों और महिलाओं के बीच मजदूरी दर में कोई भिन्नता नहीं है। पुरुषों और महिलाओं को समान रेट मिलता है जबकि ठेकेदार आमतौर पर पुरुष मजदूरों की तुलना में महिला मजदूरों को कम मजदूरी देते हैं।

समुदाय के लोगों को चिंता है कि आम तौर पर इस प्रकार की परियोजना के लिए ठेकेदार बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों से मजदूर लाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि चूंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे श्रम शक्ति उपलब्ध हैं, इसलिए जब परियोजना शुरू होगी तो स्थानीय श्रम शक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

स्थानीय योग्य युवाओं और कुशल व्यक्तियों के लिए रोजगार:

समुदाय के लोगों ने बताया कि इस इलाके के कई युवाओं ने विभिन्न स्ट्रीम्स में आईटीआई पूरा किया है और उनमें से कुछ अभी भी बेरोजगार हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि तकनीकी नौकरियों की किसी भी आवश्यकता के लिए इस क्षेत्र के बेरोजगार आईटीआई उत्तीर्ण और कुशल लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जल विद्युत परियोजना का सकारात्मक विकास प्रभाव

चर्चा के दौरान जलविद्युत परियोजना के सकारात्मक विकास प्रभाव पर समुदाय की धारणा को जानने का प्रयास किया गया। सभी प्रतिभागियों ने परियोजना का स्वागत किया और उन्होंने बताया कि परियोजना का उनके समुदाय में कई तरह से सकारात्मक विकास प्रभाव पड़ेगा। उनके अनुसार निम्नलिखित सकारात्मक विकास प्रभाव हैं:

स्थानीय लोगों को मुख्य रूप से मजदूरी के काम में रोजगार मिलेगा। इससे उनकी आजीविका को बढ़ाने और बाहर पलायन को कम करने में मदद मिलेगी।

परियोजना के तहत संपर्क सड़कों के निर्माण के कारण परिवहन और संचार बढ़ेगा। यह उसके यात्रा के समय को बचाने में मदद मिलेगी और व्यवसाय की सुविधाएं बढ़ेगी।

आसपास के सभी गांवों को सस्ती दर पर उचित बिजली मिलेगी।

b प्रतिकूल चिंताएं और निरीक्षण

टीम ने विकास के प्रतिकूल प्रभाव पर समुदाय की धारणा को भी जानना चाहा, यदि कोई हो तो। समुदाय के लोगों ने कहा कि वे किसी भी प्रतिकूल प्रभाव की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें आशंका है कि निम्नलिखित प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकते हैं:

कुछ लोग अपनी कृषि भूमि खो सकते हैं और यह उनकी फसल के नुकसान के रूप में प्रभावित कर सकता है और अंततः उनकी आजीविका को प्रभावित कर सकता है। समुदाय के लोगों ने सुझाव दिया है कि सड़क के निर्माण के दौरान परियोजना अधिकारी को उचित ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी का क्षरण न हो और गाँवों की निजी कृषि भूमि में मालबा (कूड़ा-कचरा) को न फेंका जाए।

इन पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक जलधाराएँ गाँवों के मुख्य पेयजल स्रोत हैं। समुदाय के लोगों ने सुझाव दिया है कि परियोजना के तहत सड़कों और सुरंगों का निर्माण करते समय परियोजना प्राधिकरण को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए कि यह मौजूदा धाराओं को प्रभावित नाकरे।

शिमला के कुमारसैन तहसील के नानज गाँव में लगभग 13 परिवार रहते हैं। सभी परिवार अल्पसंख्यक समूह (मुस्लिम) हैं। चर्चा के दौरान यह पता चला कि वे इस बारे में नहीं जानते हैं कि परियोजना के विकास के कारण गाँव में कितने परिवारों अपनी भूमि खोएंगे। कई परिवारों ने दृढ़ता से व्यक्त किया कि उन्हें जल विद्युत परियोजनाके लिए अपनी जमीन देना पसंद नहीं है। हालांकि, कुछ परिवारों ने यह व्यक्त किया कि उन्हें अपनी भूमि के नुकसान के लिए जो भी मुआवजा मिलेगा, तो वह उसके बदले में किसी दूसरी जगह पर समान क्षेत्रफल या कम से कम भूमि खरीद लेंगे, लेकिन अपने पैतृक गांव के पास ही।

#### c अन्य प्रभाव

##### भूमि मूल्य का प्रभाव

टीम परियोजना शुरू होने के बाद भूमि के मूल्य के प्रभाव के बारे में समुदाय से विचार जानना चाहा। समुदाय के लोगों ने कहा कि उसके क्षेत्र में परियोजना शुरू होने के बाद निश्चित रूप से भूमि का मूल्य बढ़ेगा और भूमि का मूल्य आवासीय और कृषि भूमि दोनों के लिए बढ़ेगा। उनके अनुसार मूल्य की भूमि न केवल परियोजना स्थलों के आसपास बल्कि आसपास के गाँवों में भी बढ़ेगी।

##### प्रोजेक्ट डिजाइन

समुदाय ने यह व्यक्त किया गया था कि उन्हें जल विद्युत □□□□□□□□के लिए चयनित स्थानों पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन परियोजना के अधिकारी और सरकार को इस बात का उचित ध्यान रखना चाहिए कि निजी आवासीय क्षेत्र का अधिग्रहण ना किया जाए और कोई परिवार विस्थापित न हो। जहां तक संभव हो परियोजना अधिकारी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा कृषि भूमि का अधिग्रहण न किया जाए।

##### मूल निवासियों का समूह

परामर्श प्रक्रिया और समुदायों के साथ बैठक के दौरान यह पाया गया कि परियोजना क्षेत्र में कोई भी मूल निवासी समूह नहीं है। लेकिन बाद के चरण में यदि यह पाया जाता है कि परियोजना क्षेत्र में कोई मूल निवासी समूह है और वे परियोजना से प्रभावित हुए हैं, तो सुरक्षा उपायों के अनुसार इस मुद्दों को हल किया किया जाएगा।

d सामुदायिक विकास के कार्य

सार्वजनिक परामर्श के दौरान समुदाय के सदस्यों से कई सुझाव और मांगें आई हैं कि परियोजना प्राधिकरण को परियोजना प्रभावित गांवों में कुछ सामुदायिक विकास कार्यों को करने के लिए कुछ महत्व देना चाहिए।

परामर्श के भाग के रूप में समुदाय से प्राप्त सुझाव।

सामुदायिक विकास कार्य के लिए प्राप्त सुझाव निम्नलिखित हैं

a. पेयजल के लिए सुरक्षित स्रोत का प्रावधान

परामर्श के दौरान, अधिकांश गांवों में एक प्रमुख मुद्दा उठाया गया था कि पीने और खाना पकाने के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले पानी के सुरक्षित स्रोत की आवश्यकता है। चूंकि कोई सुरक्षित स्रोत नहीं है, इसलिए लोग अपने पीने के पानी और घरेलू उपयोग के लिए खुली धारा और नाले जैसे असुरक्षित स्रोतों से पानी का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं। एसआईए सर्वे के दौरान, स्टडी टीम ने पाया है कि परियोजना प्रभावित गांवों में 100% परिवार असुरक्षित स्रोतों से असुरक्षित पानी का उपयोग करते हैं। गर्मियों के दौरान पानी की कमी होती है जिससे लोगों को घरेलू उपयोग, खाना पकाने और पीने के उद्देश्यों के लिए पास के शहर से पानी खरीदना पड़ता है। लोगों ने अनुरोध किया है कि परियोजना प्राधिकरण वाटर पंप और सामान्य नल को स्थापित करने के प्रावधान के साथ ओवरहेड टैंक का निर्माण करे, तो ग्रामीणों को वहां से सुरक्षित पानी लेने के लिए फायदेमंद होगा। चूंकि सतलुज नदी का पानी साफ नहीं है, इसलिए पीने के लिए सहायक नदियों/नालों के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है।

b. गांव में स्ट्रीटलाइट का प्रावधान

यह कई गांवों में एक आम मांग थी कि उन्हें अपने गांवों के भीतर स्ट्रीट लाइट पोस्ट की जरूरत है। गाँव के अंदर की संकरी सड़कों में रात के समय चलना बहुत मुश्किल और खतरनाक है। लोगों ने अनुरोध किया है कि परियोजना प्राधिकरण को महुली (शिमला जिला) और बेहना, दिंगीधर मोहाल (कुल्लू जिला) के परियोजना वाले गांवों में 3 से 4 स्ट्रीट लाइट पोस्ट प्रदान करनी चाहिए।

c. मंदिर धर्मशाला का पुनर्निर्माण (विश्राम गृह)

कुल्लू जिले के बेहना दिंगीधर मोहाल में, एक प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ भगवान बेहना महादेव की पूजा की जाती है। परियोजना स्थल के आस-पास के गाँव के लोग ही नहीं बल्कि 25 किलोमीटर से अधिक दूर के लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। गाँव के लोगों के अनुसार यह मंदिर 100 साल से अधिक पुराना है। हर साल यहां एक बड़ा मेला (स्थानीय त्योहार) आयोजित किया जाता है, जिसमें सैकड़ों से अधिक श्रद्धालु भाग लेते हैं। मंदिर के परिसर के अंदर एक धर्मशाला था। शादी और अन्य समारोहों के दौरान लोग इस धर्मशाला का उपयोग करते हैं। ज्यादातर महिला श्रद्धालु जो दूर-दराज से आती हैं, वहां विश्राम करती हैं। अब धर्मशाला ध्वस्त स्थिति में है और यह वर्तमान में उपयोग में नहीं है। गाँव के लोगों ने परियोजना प्राधिकरण से इस धर्मशाला के पुनर्निर्माण का अनुरोध किया।



चित्र: 3 धर्मशाला के स्नैपशॉट्स, बेहना गांव

ग्रामीणों और मंदिर समिति के सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए मंदिर के महत्व के साथ अनुरोध पत्र अनुलग्नक 6 के रूप में संलग्न है

**d. युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण**

सार्वजनिक परामर्श के दौरान पाया गया कि बहुत से युवा जो शिक्षित हैं, यहाँ तक कि स्नातक पूरा कर चुके हैं, वे बेरोजगार हैं। कौशल की कमी शायद एक सबसे बड़ी समस्या है जिसका सामना युवा कर रहे हैं जिससे कई स्नातक किये हुए युवा बेरोजगार हैं। ग्रामीणों के अनुसार डिग्री के साथ कॉलेजों से पास हुए कई स्नातक हैं और उचित कौशल की कमी के कारण उन्हें बेरोजगार कहा जाता है। लोगों की मांग है कि परियोजना अधिकारी को उनके गांव के शिक्षित छात्रों के लिए आईटीआई या अन्य कौशल-आधारित प्रशिक्षण का वित्तपोषण और व्यवस्था करनी चाहिए।

**2.7 जन सुनवाई का विवरण**

सार्वजनिक सुनवाई का विवरण गतिविधि के पूरा होने पर प्रदान किया जाएगा। इस स्तर पर हम फॉर्म II के अनुसार सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट और फॉर्म III के अनुसार सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्लान को ड्राफ्ट रिपोर्ट के रूप में प्रदान कर रहे हैं ताकि फीडबैक प्राप्त हो सके। फीडबैक के अनुरूप जनसुनवाई के दौरान प्राप्त जानकारी और सुझाव को उसके अनुसार शामिल किया जाएगा।

## Chapter 3

## भूमि का आकलन

### 3.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश मंडी, कांगड़ा और शिमला जैसे तीन मुख्य डिवीजन में विभाजित है। डिवीजन को 12 जिलों में उप-विभाजित किया गया है यानी बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौलस्पीति-, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना। जिलों को 53 उप-मंडलों, 79 तहसीलों और 37 उप-तहसीलों में उप-विभाजित किया गया है।



Fig 4: Himachal Pradesh map with district level division

चित्र 4: जिला स्तर के विभाजन के साथ हिमाचल प्रदेश का नक्शा

प्रत्येक जिले का नेतृत्व एक उप-आयुक्त करता है, जो इस क्षमता में अपनी विकास भूमिका के अलावा, एक जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के दोहरे कार्यों का भी पालन करता है। कलेक्टर के रूप में, एक उप-आयुक्त अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन राजस्व संपत्ति के संबंध में भू राजस्व के नियमित और समय पर संग्रह के लिए जिम्मेदार है, साथ ही मूल्यवान राजस्व अभिलेखों के अद्यतन और उचित संरक्षण का भी जिम्मेदार है। उनके पास जिला राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त एक अधिकारी है। जिसका काम जिला राजस्व अभिलेखों को उचित रूप से सुव्यवस्थित करना और भूमि प्रशासन से जुड़े दिन-प्रतिदिन के कार्यों में भाग लेना है। एलएचईपी स्टेज-II की परियोजना स्थल जिलों के 3

अंतर्गत आता है यानी शिमला, कुल्लू और मंडी। इन जिलों 3के उप-मंडलों, तहसीलों और उप तहसीलों की संख्या- निम्नलिखित टेबल 3.1 में प्रदर्शित होती है।

जिले	उप-मंडलों की संख्या	तहसीलों की संख्या	उपतहसीलों- की संख्या
शिमला	7	12	5
कुल्लू	4	4	2
मंडी	7	10	7

राजस्व प्रशासन के उद्देश्यों के लिए, प्रत्येक तहसील/उप-तहसील को कानूनगो सर्किलों की संख्या में उप-विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक परिणामस्वरूप, 7 से 10 पटवारी सर्किलों की संख्या में औसतन उप-विभाजित है। इस प्रकार, पटवारी राजस्व पदानुक्रम में सबसे कम राजस्व का ऑफिस हैं, लेकिन निश्चित रूप से श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण हैं लेकिन निश्चित रूप से श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी राजस्व सम्पदा के संबंध में सभी राजस्व अभिलेखों के उचित रखरखाव और संरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं।

एसजेवीएन ने राजस्व विभाग से पहले ही जमीन के अभिलेख और नक्शे एकत्र कर लिए हैं और स्टडी टीम को वही प्रदान किया गया है। परियोजना के प्रभाव के तहत प्रभाव का संपूर्ण क्षेत्र (अधिग्रहण के लिए भूमि क्षेत्र सीमित नहीं)।

### 3.2 भूमि सूची और डेटा संगृहीत का प्राथमिक स्रोत

एलएचईपी स्टेज-II के परियोजना स्थल जिलों के अंतर्गत आता 3 है यानि शिमला, कुल्लू और मंडी। परियोजना के प्रभाव अंतर्गत पर प्रभाव पड़ेगा (मोहल्लों) गाँवों 8। गाँवों में 8 प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रकार की जमीन की आवश्यकता है। निम्नलिखित टेबल और जिलों के नाम का वर्णन गाँवों के नाम और संबंधित तहसीलों 12 करता है जो एलएचईपी स्टेज -II परियोजना के प्रभाव में होगा। यह टेबल 3.2 में दिया गया है। भूमि सूची का विवरण एसजेवीएन से प्राप्त किया गया है, जिसमें उन्होंने प्रभावित भूमि क्षेत्र गाँवों के ग्राम राजस्व नक्शे प्रदान किए हैं। ये नक्शे और भूमि खंड प्रभावित खसरा संख्या वार अनुलग्नक 7 और अनुलग्नक 8 में दिए गए हैं।

जिले	गाँवों का नाम	तहसीलों का नाम	भूमि आवश्यकता टिप्पणियां
शिमला	महावली	कुमारसैन	प्राइवेट और सरकारी दोनों जमीन
	बरगल	कुमारसैन	प्राइवेट और सरकारी दोनों जमीन
	तलाह	कुमारसैन	प्राइवेट और सरकारी दोनों जमीन
	चमोद	कुमारसैन	प्राइवेट और सरकारी दोनों जमीन
कुल्लू	डिंगिधर	अन्नी	प्राइवेट और सरकारी दोनों जमीन
मंडी	कोट	करसोग	प्राइवेट और सरकारी दोनों जमीन
	नंज	करसोग	प्राइवेट और सरकारी दोनों जमीन

	फिरनू	करसोग	प्राइवेट और सरकारी दोनों जमीन
--	-------	-------	-------------------------------

### 3.3 कुल आवश्यक ज़मीन

एचएचईपी स्टेज-II के लिए कुल आवश्यक ज़मीन 174.3584 हेक्टेयर है जिसमें से कुल प्राइवेट ज़मीन 24.1449 हेक्टेयर (13.85%) है और कुल सरकारी ज़मीन 150.2135 हेक्टेयर (86.15%) है। टेबल 3.3 आवश्यक घटक वार भूमि को इंगित 15 करता है।

टेबल 3.3 घटकों द्वारा एलएचईपी स्टेज -II के लिए आवश्यक भूमि				
क्र.सं	घटक का नाम	आवश्यक ज़मीन		
		वन भूमि	प्राइवेट भूमि	कुल भूमि
		क्षेत्र (हे० मॅ)	क्षेत्र (हे० मॅ)	क्षेत्र (हे० मॅ)
1	नदी क्षेत्र सहित जलाशय	105.8036	13.9955	119.7991
2	पावर हाउस कॉम्प्लेक्स और स्विच यार्ड आदि।	14.6629	2.3269	16.9898
3	बांध	1.8650	0.0635	1.9285
4	डंपिंग साइट्स	9.8531	1.7075	11.5606
5	क्वारी साइट	6.5282	0.0000	6.5282
6	कालोनी साइट	0.0000	5.5717	5.5717
7	परियोजना के लिए सड़कें और नौकरी की सुविधाएं आदि	8.6065	0.4798	9.0863
8	Underground/Notional area for PH complex & DT पीएच कॉम्प्लेक्स और डीटी के लिए भूमिगत/ राष्ट्रीय क्षेत्र	2.8942	0.0000	2.8942
<b>Total कुल</b>		<b>150.2135</b>	<b>24.1449</b>	<b>174.3584</b>
स्रोत: एसजीवीएन, बिथल				

### 3.4 परियोजना क्षेत्र के आसपास में किसी भी सार्वजनिक, अप्रयुक्त भूमि का वर्तमान उपयोग

एसजेवीएन के अधिकारियों के साथ चर्चा और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा (डीपीआर) से यह पता चलता है कि परियोजना क्षेत्र के आसपास में किसी भी सार्वजनिक, अप्रयुक्त भूमि के उपयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह आरटीएफसीटीएलएआरआरए, के संदर्भ में परियोजना क्षेत्र के आसपास में किसी भी 8 की धारा 2013अप्रयुक्त भूमि के उपयोग को दर्शाता है।

### 3.5 भूमि यदि कोई( पहले से ही खरीदी गई, दान की गई, पट्टे पर या अधिग्रहित की गई, और परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के प्रत्येक प्लॉट के लिए इच्छित उपयोग

एसजेवीएन के अधिकारियों के साथ चर्चा और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा (डीपीआर) से यह पता चलता है कि परियोजना कार्यान्वित की इस स्टेज 2 के लिए एसजेवीएन द्वारा कोई भी भूमि पहले से खरीदी, पट्टे पर या अधिग्रहित नहीं की गई है।

### 3.6 परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि की मात्रा और स्थान

परियोजना का स्थान शिमला जिले की कुमारसैन तहसील, कुल्लू जिले की अन्नी तहसील और मंडी जिले की करसोग तहसील के गांवों के अधिकार क्षेत्र में आता है। भूमि की मात्रा का स्थान वार अधिग्रहण टेबल में दिया गया है। टेबल 3.4 दर्शाती है कि भूमि अधिग्रहण के कारण 324 भूमि मालिक, 168 प्लॉट और प्राइवेट भूमि का 24.1449 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

जिला	तहसील का नाम	गांव का नाम	भूमि मालिकों की संख्या	प्लॉट की संख्या (कित्ता)	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
शिमला	कुमारसैन	महावली	82	17	2.1126
		बरगल	11	09	1.5751
		तलाह	11	07	1.7075
		चमोद	04	08	2.3269
कुल्लू	अन्नी	डिंगिधर	66	13	1.2284
मंडी	करसोग	कोट	12	28	0.5974
		फिरनू	65	48	8.0198
		नंज	73	38	6.5772
<b>कुल</b>			<b>324</b>	<b>168</b>	<b>24.1449</b>

इसके अतिरिक्त अधिग्रहित की जाने वाली सरकारी भूमि की क्षेत्रहेक्टेयर है 150.2135 । इसका विवरण टेबल में दिया गया है।

संख्या	राजस्व ग्राम	वन भूमि (हे)
1	तेशन	12.9915
2	महावली	13.7514
3	बरगल	22.9376
4	चमोद	14.6629
	पीएच कॉम्प्लेक्स के लिए भूमिगत/राष्ट्रीय क्षेत्र	2.2342

5	तलाह	3.0302
6	डिंगिधर	3.7801
7	कोट	13.3521
8	नंज	25.1439
	डीटी के लिए भूमिगत/राष्ट्रीय क्षेत्र	0.66
9	फिरनू	37.6696
<b>कुल</b>		<b>150.2135</b>

### 3.7 अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का प्रकृति, उपयोग और वर्गीकरण

अधिग्रहित की जाने वाली प्राइवेट भूमि एकल फसली वर्षा वाली कृषि भूमि है। उगाई जाने वाली फसलों में दाल (उड़द और मूंग दाल) और फलियां (राजमा), धान, मक्का, गेहूं, मौसमी सब्जियां (गोभी, फूलगोभी, शिमला मिर्च, खीरा, भिंडी, मिर्च, आदि) शामिल हैं। अधिग्रहण के अंतर्गत भूमि खोने वाले लोगों द्वारा सभी एकल फसलें उत्पादित की जाती हैं। सभी फसलें मानसून पर निर्भर हैं। 24.1449 हेक्टेयर में से भूमि का लगभग 60% बंजर/पथरीली भूमि है (स्थानीय रूप से खाद भूमि के रूप में दर्शाया गया है)। इसलिए अधिग्रहण के लिए निर्धारित की गई भूमि व्यापक रूप अनुपजाऊ भूमि है।

अध्यन के दौरान पीएएच की भूमि रिकॉर्ड और उनके वर्गीकरण निर्धारित किया गया और टेबल 3.6 में दिया गया है।

सं.	भूमि का वर्गीकरण (भूमि के रिकॉर्ड के अनुसार)	प्लॉट की संख्या
1	बंजर कदीम	6
2	बंजर कवले कस्थ	15
3	बाखल दोयम	15
4	बाखल सोयम	5
5	बाखल अक्वल	4
6	बाखल दोयम फलदार	1
7	बाखल अक्वल फलदार	1
8	बाथल चहरान	4
9	बगीचा बरनी दोयम	1
10	बंजर जदीद	1
11	बाथल सोयम	6
12	बरनी अक्वल	19
13	बरनी दोयम	41
14	धानी दोयम	23
15	दानी अक्वल	1
16	क्यार दोयम	2

टेबल 3.6 परियोजना के आवश्यक प्राइवेट भूमि का वर्गीकरण		
सं.	भूमि का वर्गीकरण (भूमि के रिकॉर्ड के अनुसार)	प्लॉट की संख्या
17	घरत	1
18	घसनी	1
19	गैर मुमकिन खलवाड़ा	2
20	गैर मुमकिन खनदार	1
21	गैर मुमकिन खम्बी	1
22	गैर मुमकिन आबदी	3
23	गैर मुमकिन मकान	5
24	गैर मुमकिन देवस्थान	1
25	गैर मुमकिन खाद	4
26	गैर मुमकिन सड़क	1
27	गैर मुमकिन पत्थर	2
28	घरानी अक्वल	1
<b>कुल</b>		<b>168</b>
स्रोत : एसजेवीएन, बिथल		

### 3.7.1 सिंचाई क्षेत्र

एसआईए सर्वे के दौरान यह पता चला कि परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित की जा रही प्राइवेट भूमि में सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन ज़मीनों पर बारिश होती है और मानसून के दौरान साल में एक बार ही फसलें उगाई जाती हैं।

### 3.7.2 फसल का पैटर्न

उगाई जाने वाली फसलों में दालें (उड़द और मूंग दाल) और फलियां (राजमा), धान, मक्का, गेहूं, मौसमी सब्जियां (गोभी, फूलगोभी, शिमला मिर्च, खीरा, भिंडी, मिर्च, आदि) शामिल हैं। अधिग्रहण के अंतर्गत भूमि खोने वाले लागों द्वारा सभी एकल फसलें उत्पादित की जाती हैं। सभी फसलें मानसून पर निर्भर हैं। 24.1449 हेक्टेयर में से भूमि का लगभग 60% बंजर/पथरीली भूमि है (स्थानीय रूप से खाद भूमि के रूप में दर्शाया गया है)। इसलिए अधिग्रहण के लिए निर्धारित की गई भूमि व्यापक रूप से अनुपजाऊ भूमि है।

### 3.7.3 भूमि पर लगे वृक्षों का अधिग्रहण किया जाना

एसआईए के सर्वे ने खुलासा किया है कि एलएचईपी स्टेज-II परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली प्राइवेट भूमि पर 988 की संख्या में फल देने वाले पेड़ खड़े हैं। प्राइवेट भूमि 8 गांवों में आ रही है। वनस्पति नाम से पेड़ की प्रजातियां और संबंधित संख्या टेबल 3.7 में प्रस्तुत की गई है।

टेबल 3.7 प्राइवेट भूमि पर आने वाले पेड़ों की गणना सूची			
सं.	पेड़ की प्रजातियों के नाम	वनस्पति नाम	पेड़ों की संख्या
1	आम के पेड़	मेंगीफेरा इंडिका	397
2	अनार के पेड़	पुनिका गैनॉटम	451
3	नींबू के पेड़	साइट्रस × लिमोन	80
4	बादाम के पेड़	प्रूनस डलसिस	50
5	अमरूद के पेड़	सिडियम गुजावा	10
<b>कुल</b>			<b>988</b>
स्रोत : एसआईए सर्वे, एलएचईपी स्टजे-II 2019			

### 3.8 अधिकार का आकार और स्वामित्व का तरीका, भूमि वितरण और आवासीय घरों की संख्या

सामाजिक सर्वे से उजागर हुआ है कि सामान्य भूमि स्वामित्व का पैटर्न छोटे भूमि धारक है। 2.5 एकड़ से अधिक की औसत भूमि स्वामित्व संख्या में 18 हैं और अन्य 306 भूमि के प्राइवेट मालिक 2.5 एकड़ से कम भूमि के आकार वाले सभी छोटे भूमि स्वामी हैं।

सामाजिक सर्वे से उजागर हुआ है कि यहां कोई भी आवासीय संपत्तियां नहीं हैं, जिससे एलएचईपी स्टजे 2 परियोजना के अंतर्गत सरकारी या प्राइवेट भूमि दोनों पर परियोजना विकास या प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित हो।

### 3.9 भूमि की कीमतें और हाल ही में भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन और पिछले 3 सालों में भूमि का उपयोग

एसआईए सर्वे के दौरान सर्वे टीम ने प्रत्येक भूमि मालिक से संपर्क किया है और परियोजना के लिए अधिग्रहण किए जाने वाले प्लॉट्स में किसी प्रकार के हाल में स्वामित्व परिवर्तन पर समझने की कोशिश की है। इन चर्चाओं से ज्ञात हुआ है कि हाल ही (लगभग 3 सालों) में स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है और नंज में 6 भूमि मालिकों ने अपनी भूमि बेच दी है और अन्य सभी ने अपनी भूमि स्वामित्व को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया है।

भूमि मालिकों के खेती के पैटर्न में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है और जैसा कि धारा 3.8.2 में उल्लेख किया गया है कि वे वर्षा पर आधारित कृषि से फसलों को उगाना जारी रख रहे हैं।

## अध्याय 4 प्रभावित परिवारों और संपत्तियों का आकलन और गणना

इस अध्याय में एलएचईपी स्टेज- II के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि और संपत्ति का विवरण दिया गया है। सर्वे के दौरान डेटा में प्रभावित निजी भूमि, किसी भी एसटी और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकारों को खोने और किसी भी परिवार के बारे में विवरण शामिल है जो सामान्य संपत्ति संसाधन (सीपीआर) पर निर्भर हैं, और सीपीआर के अधिग्रहण के कारण उनकी आजीविका प्रभावित होती है। रिपोर्ट के इस अध्याय में प्रभावों की विभिन्न श्रेणियों पर चर्चा की गई है। यह भी शामिल है

### 4.1 सीधे तौर पर प्रभावित होने वाली भूमि

एलएचईपी स्टेज- II के लिए आवश्यक कुल निजी भूमि 24.1449 हेक्टेयर है और कुल भूमि में 168 प्लॉट हैं। एसआईए के सर्वे के अनुसार ये 168 प्लॉट 324 निजी मालिकों के हैं। विवरण टेबल 4.1 में दिया गया है।

टेबल 4.1 निजी भूमि के मालिकों की संख्या जो भूमि अधिग्रहण के कारण सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं					
जिला	तहसील का नाम	गांव का नाम	जमीन के मालिकों की संख्या	प्लॉट्स की संख्या (किट्टा)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
शिमला	कुमारसैन	महवली	82	17	2.1126
		बरगल	11	09	1.5751
		तलाह	11	07	1.7075
		चमोद	04	08	2.3269
कुल्लू	अन्नी	दिंगीधर	66	13	1.2284
मंडी	कारसोग	कोट	12	28	0.5974
		नंज	65	48	8.0198
		फिरनू	73	38	6.5772
<b>योग</b>			<b>324</b>	<b>168</b>	<b>24.1449</b>
स्रोत- एसजेवीएन, बिठल					

#### 4.1.1 क्या किरायेदारी या निवास वाली भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है

एलएचईपी स्टेज 2 परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर कोई किरायेदार नहीं है या कोई अन्य व्यक्ति नहीं रह रहा है।

#### 4.1.2 अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी जो अपने किसी भी वन अधिकार को खो चुके हैं

अनुसूचित जनजाति और कोई अन्य पारंपरिक वनवासी नहीं हैं जो एलएचईपी स्टेज 2 परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के कारण किसी भी वन अधिकार को खोयेगे।

#### 4.1.3 सामान्य संपत्ति संसाधनों पर निर्भर हैं जो उनकी आजीविका के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित होंगे

कोई भी सामान्य संपत्ति संसाधन नहीं हैं जो उनकी जीविका के लिए एलएचपी स्टेज 2 परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के कारण प्रभावित होंगे।

#### 4.1.4 राज्य सरकार द्वारा अपनी किसी भी योजना के तहत भूमि सौंपी/ निर्दिष्ट की गई है और ऐसी भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत है

राज्य सरकार द्वारा उनकी किसी भी योजना के तहत कोई भूमि नहीं सौंपी/ निर्दिष्ट की गई है जो एलएचईपी स्टेज 2 परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के कारण प्रभावित होगी।

#### 4.1.5 शहरी क्षेत्रों में अधिग्रहित की जाने वाली किसी भी भूमि पर तीन साल या उससे पहले से पहले निवास कर रहे हैं

शहरी क्षेत्रों में किसी भी भूमि पर रहने वाले परिवार के व्यक्ति/व्यक्ति प्रभावित नहीं हैं जो भूमि के अधिग्रहण से पहले तीन साल या उससे अधिक समय से रह रहे हैं।

#### 4.1.6 अधिग्रहण से पहले तीन साल तक आजीविका के प्राथमिक स्रोत के रूप में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर निर्भर है

कोई भी प्रभावित परिवार या उसका सदस्य नहीं है जो अधिग्रहण से पहले तीन साल तक आजीविका के प्राथमिक स्रोत के रूप में अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्भर है।

#### 4.2 अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भूमि के अधिग्रहण से सीधे प्रभावित नहीं हुआ

ऐसे कोई भी परिवार या व्यक्ति नहीं हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हों क्योंकि प्रस्तावित परियोजना विकास के लिए सभी पीएएफ अपनी कृषि वर्षा आधारित भूमि का 100% खो रहे हैं।

#### 4.3 उत्पादक संपत्ति और महत्वपूर्ण भूमि की सूची

उत्पादक परिसंपत्तियों में वर्षा आधारित कृषि भूमि के अलावा फल देने वाले पेड़ शामिल हैं। फल देने वाले पेड़ों के प्रभावित होने का विवरण टेबल 4.2 में दिया गया है।

टेबल 4.2 फल देने वाले पेड़								
जिला	मोहाल	आम	अमरुद	अनार	नींबू	पालम	बादाम	योग
शिमला	महावली	0	0	0	0	0	0	0
	बरगल	22	0	39	0	0	0	61
	तलाह	66	0	0	50	0	50	166
	चमोद	15	10	0	10	0	0	35
कुल्छू	दिंगीधर	132	0	12	20	0	0	164
मंडी	कोट	0	0	0	0	0	0	0
	फिरनू	12	0	400	0	0	0	412
	नंज	150	0	0	0	186	0	336
<b>योग</b>		<b>397</b>	<b>10</b>	<b>451</b>	<b>80</b>	<b>186</b>	<b>50</b>	<b>1174</b>
स्रोत- एसआईए सर्वे, 2019								

**अध्याय 5**
**सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वास स्थल)**
**5.1 परिचय**

प्रभावित क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक रूपरेखा किसी भी विकास परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक विशेष क्षेत्र का समाज और अर्थव्यवस्था है जो प्रस्तावित परियोजना को प्रभावित करता है जो उस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल का अध्ययन करने को आवश्यक बनाता है जिसमें एक परियोजना का विकास प्रस्तावित है। यह इस तथ्य के नजरिए से महत्वपूर्ण है कि विकास लोगों के अनुकूल और पर्यावरणीय रूप से स्थाई होना चाहिए। इसे देखते हुए परियोजना के डिजाइन चरण के दौरान तैयारी गतिविधि के हिस्से के रूप में बेसलाइन बनाने करने के लिए एक विस्तृत सामाजिक-आर्थिक अध्ययन किया गया है। यह प्रभावों की श्रेणी और सीमा को स्थापित करने और अपरिहार्य प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए एक उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए आधार प्रदान करता है।

वर्तमान स्टडी एलएचईपी स्टेज- II के लिए आयोजित की गयी है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में 3 जिलों के अंतर्गत आता है। जिले शिमला, कुल्लू और मंडी हैं। सामाजिक-आर्थिक अध्ययन डेटा के दो सेटों पर आधारित है, जिसमें उपलब्ध प्रकाशित डेटा, प्राथमिक संवादी इंटरव्यू और सभी हितधारकों के साथ सार्वजनिक परामर्श से शामिल हैं।

उपरोक्त को देखते हुए शुरू की चर्चा में सेकेंडरी डेटा सेट में हिमाचल प्रदेश की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल पर और फिरा शिमला जिला, कुल्लू जिला और मंडी जिले पर चर्चा की गयी है।

हिमाचल प्रदेश में 12 जिले शामिल हैं जो कि चंबा, कांगडा, लाहौल और स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर हैं। प्रशासनिक उद्देश्य के लिए, प्रत्येक जिले को प्रशासनिक डिविजनों, उप-डिविजन्स, विकासात्मक ब्लॉक्स, तहसीलों, उप-तहसीलों और गांवों (आबादी वाले और बिना आबादी वाले) में विभाजित किया गया है। टेबल 5.1 जिलों के उपरोक्त विवरण प्रस्तुत करती है।

टेबल 5.1 जिलों के प्रशासनिक डिविजन्स							
जिला	उप-डिविजन्स	तहसील	उप-तहसील	सीडी ब्लॉक्स	गांव		
					योग	आबादी वाले	बिना आबादी वाले
शिमला	7	12	5	11	3231	2705	526
कुल्लू	4	4	2	5	326	314	12
मंडी	7	10	7	10	3338	2850	488

स्रोत: एसआईए सर्वे, 2019

**5.2 परियोजना क्षेत्र की जनसंख्या संबंधी प्रोफाइल**
**5.2.1 लिंग के अनुसार जनसंख्या**

2011 की जनगणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या 6,864,602 है, जिनमें से पुरुष और महिला क्रमानुसार 3,481,873 और 3,382,729 हैं। टेबल 5.2 हिमाचल प्रदेश और 3 जिलों की जनसंख्या को दर्शाती है।

लिंग अनुपात, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित, एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक जो निश्चित समय पर एक समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रबल समानता की सीमा को मापता है। हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात 972 है, शिमला जिले में यह 915 है, कुल्लू जिले में यह 942 है, और मंडी जिले में यह 1007 है।

स्थान	कुल	पुरुष	महिला	लिंगानुपात
हिमाचल प्रदेश	6864602	3481873	3382729	972
शिमला जिला	184362	425039	388971	915
कुल्लू जिला	437903	225452	212451	942
मंडी जिला	999777	498065	501712	1007

स्रोत: जनगणना 2011

एसआईए सर्वेक्षण के अनुसार, जो 217 परियोजना प्रभावित परिवारों के बीच आयोजित किया गया था, 217 परियोजना प्रभावित परिवारों की कुल जनसंख्या 918 है जिनमें से पुरुष 465 हैं और महिला 453 हैं। टेबल 5.3 8 गाँवों में परियोजना प्रभावित परिवारों की जनसंख्या को दर्शाती है। यह पता चला कि परियोजना प्रभावित परिवारों के बीच लिंग अनुपात 974 है जो हिमाचल प्रदेश के लिंग अनुपात से थोड़ा बेहतर है।

जिला	गांव का नाम	परिवारों की संख्या	कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला	लिंगानुपात
शिमला	महावली	61	228	106	122	1151
	बरगल	10	38	20	18	900
	तलाह	10	28	13	15	1154
	चमोद	6	24	13	11	846
कुल्लू	डिगिंधर	44	203	110	93	845
मंडी	कोट	9	61	32	29	906
	फिरनू	39	184	92	92	1000
	नंज	38	152	79	73	924
<b>योग</b>		<b>217</b>	<b>918</b>	<b>465</b>	<b>453</b>	<b>974</b>

एसआईए सर्वे : एलएचईपी स्टेज-II, 2019

### 5.2.2 सामाजिक श्रेणियां

टेबल 5.4 से हिमाचल प्रदेश और 3 जिलों में सामाजिक श्रेणी द्वारा जनसंख्या के वितरण का पता चलता है। हिमाचल प्रदेश में एक चौथाई से अधिक आबादी एससी और 5.7% एसटी हैं।

टेबल 5.4: सामाजिक श्रेणी के अनुसार जनसंख्या			
स्थान	अनुसूचित जाति (%)	अनुसूचित जन जाति (%)	अन्य (%)
हिमाचल प्रदेश	25.19	5.71	69.10
शिमला जिला	26.5	1.1	72.4
कुल्लू जिला	28.0	3.84	68.16
मंडी जिला	29.38	1.27	69.35
स्रोत: जनगणना 2011			

**टेबल 5.5** एलएचईपी स्टेज- II परियोजना क्षेत्र में परियोजना प्रभावित गांवों की सामाजिक श्रेणी द्वारा सर्वे किए गए परिवारों के वितरण को दर्शाती है। 217 सर्वे किए गए परिवारों में 90 अनुसूचित जाति वर्ग (41%) से हैं और 108 अन्य श्रेणी (59%) से हैं। सर्वे किए गए परिवारों में 19 एसटी परिवार हैं, जो गुर्जर समुदाय के हैं।

टेबल 5.5: सामाजिक श्रेणी के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवार					
जिला	गांव का नाम	परिवारों की संख्या	एससी	एसटी	अन्य
शिमला	महावली	61	59	0	2
	बरगल	10	1	0	9
	तलाह	10	9	0	1
	चमोद	6	0	0	6
कुल्लू	डिगिंधर	44	8	0	36
मंडी	कोट	9	3	0	6
	फिरनू	39	1	9	29
	नंज	38	9	10	19
<b>कुल</b>		<b>217</b>	<b>90</b>	<b>19</b>	<b>108</b>
एसआईए सर्वे : एलएचईपी स्टेज-II, 2019					

### 5.2.3 धर्म के अनुसार जनसंख्या

जनगणना 2011 हिमाचल प्रदेश और 3 परियोजना जिलों की धर्म जनसांख्यिकी की अच्छी जानकारी प्रदान करता है। हिमाचल प्रदेश में हिंदू बहुसंख्यक हैं और इसके बाद 3 जिलों में मुसलमान हैं। हिमाचल प्रदेश में हिंदू 95%, शिमला जिले में 97.23%, कुल्लू जिले में 94.92% और मंडी जिले में 98.16% हैं। चुराह तहसील में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत बहुत अधिक है जो राज्य और जिले का औसत से 16% अधिक है। यह टेबल 5.6 में दर्शाया गया है।

स्थान	हिंदू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	अन्य
हिमाचल प्रदेश	95.17	2.18	0.18	1.16	1.15	0.03	0.13
शिमला जिला	97.23	1.45	0.25	0.50	0.40	0.02	0.15
कुल्लू जिला	94.92	0.68	0.36	0.32	3.51	0.02	0.19
मंडी जिला	98.16	0.95	0.09	0.41	0.26	0.00	0.13

स्रोत : जनगणना 2011

एसआईए के सर्वे से यह पता चला कि परियोजना प्रभावित परिवार हिंदू और मुस्लिम धर्म से हैं। सर्वे में शामिल 217 परिवारों में 198 हिंदू समुदाय से हैं और केवल 19 परिवार मुस्लिम समुदाय से हैं। ये मुस्लिम पीएएफ मंडी जिले के फिरनू और नानजिंग गांवों के हैं। हिंदू और मुस्लिम को छोड़कर अन्य किसी भी धर्म से कोई परिवार नहीं है। टेबल 5.7 में विवरण दिया गया है।

जिले	गांव का नाम	परिवारों की संख्या	हिंदू	मुस्लिम	अन्य
शिमला	महावली	61	61	0	0
	बरगल	10	10	0	0
	तलाह	10	10	0	0
	चमोद	6	6	0	0
कुल्लू	डिगिंधर	44	44	0	0
मंडी	कोट	9	9	0	0
	फिरनू	39	30	9	0
	नंज	38	28	10	0
<b>कुल</b>			<b>198</b>	<b>19</b>	<b>0</b>

एसआईए सर्वे : एलएचईपी स्टेज-II, 2019

#### 5.2.4 ग्रामीण और शहरी जनसंख्या वितरण

2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लगभग 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, 93% से अधिक जनसंख्या मंडी में, 90.55% कुल्लू और 75.26% शिमला जिले में (टेबल 5.8)। यह ध्यान दिया जाता है कि एलएचईपी स्टेज- II का परियोजना क्षेत्र केवल ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आता है।

स्थान	कुल आबादी	ग्रामीण जनसंख्या (%)	शहरी जनसंख्या (%)
हिमाचल प्रदेश	6864602	89.97	10.03

शिमला जिला	814010	75.26	24.74
कुल्लू जिला	437903	90.55	9.45
मंडी जिला	999777	93.73	6.27
स्रोत: जनगणना 2011			

### 5.2.5 साक्षरता स्तर

साक्षरता किसी भी राष्ट्र या राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए प्रमुख सूचकों में से एक है। 2011 की जनगणना के उद्देश्य से, सात साल या उससे अधिक आयु का व्यक्ति, जो किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है, को साक्षर माना जाता है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, पुरुष साक्षरता 80.9% और महिला साक्षरता 64.6% के साथ साक्षरता दर 74.04% है।

टेबल 5.9 लिंग के आधार पर साक्षरता दर और हिमाचल प्रदेश और 3 परियोजना जिलों में साक्षरता में लैंगिक अंतर के बारे में बताती है।

साक्षरता के मामले में हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है और यह 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में 11 वें स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर 82.80% है और पुरुष साक्षरता 89.53% और महिला साक्षरता 75.93% है।

जिलावार साक्षरता दर के संबंध में, जिला मंडी में लगभग 72% साक्षरता है जो हिमाचल प्रदेश के अन्य 12 जिलों की तुलना में सबसे कम साक्षरता दर है। महिला साक्षरता के बारे में बताते हुए, 15.90 प्रतिशत के साथ मंडी जिले में लैंगिक अंतर राज्य के 13.60 प्रतिशत के स्तर से अधिक खराब है।

स्थान	कुल	पुरुष	महिला	लैंगिक अंतर
हिमाचल प्रदेश	82.80	89.53	75.93	13.60
शिमला जिला	83.64	89.59	77.13	12.46
कुल्लू जिला	79.40	87.39	70.91	16.48
मंडी जिला	81.53	89.56	73.66	15.90
स्रोत: जनगणना 2011				

### 5.2.6 स्वास्थ्य की स्थिति

स्वास्थ्य कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है और आर्थिक रूप से उत्पादक जीवन जीने के लिए अच्छे स्वास्थ्य जरूरी होता है। व्यक्तियों और समुदायों का स्वास्थ्य विभिन्न सामाजिक आर्थिक, जनसांख्यिकीय और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। रिपोर्ट के इस भाग में हिमाचल प्रदेश, परियोजना के 3 जिलों और परियोजना प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य की स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य की स्थिति को समझने के लिए एचआईवी/एड्स, संस्थागत प्रसव और शिशु मृत्यु दर जैसे सूचकों का विश्लेषण किया गया है। माध्यमिक स्रोतों के साथ-साथ घरेलू एसआईए सर्वे द्वारा जानकारी एकत्र की गई थी। प्रासंगिक माध्यमिक डेटा विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र किया गया है।

उस स्तर की जांच करने का भी प्रयास किया गया है, जहां तक परियोजना क्षेत्र में पर्यावरणीय कारक जैसे कि स्वच्छता, सुरक्षित पीने के पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच ने स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित किया है, इसे रिपोर्ट को अगले सेक्सस में चित्रित किया गया है।

#### 5.2.6.1 एचआईवी/एड्स

राज्य में एचआईवी / एड्स के मामले बढ़ रहे हैं। वर्तमान में, एनएसीओ के एचआईवी प्रहरी निगरानी तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार, एचआईवी/एड्स (पीएलडब्ल्यूएच) के साथ रहने वाले लोगों की आधिकारिक संख्या हिमाचल में लगभग 5700 है।

**टेबल 5.10** हिमाचल प्रदेश की आबादी के बीच शहरी/ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 15-49 वर्ष की आयु में एचआईवी/एड्स की जानकारी को दर्शाता है।

टेबल 5.10: हिमाचल प्रदेश में वयस्कों (उम्र 15-49 वर्ष) के बीच एचआईवी/एड्स की जानकारी			
सूचक	शहरी (% में)	ग्रामीण (% में)	कुल (% में)
महिलाएं जिन्हें एचआईवी/एड्स का विस्तृत जानकारी है	47.6	28.5	30.9
पुरुष जिन्हें एचआईवी/एड्स की विस्तृत जानकारी है	44.7	44.5	44.5
महिलाएं जिन्हें पता है कि कंडोम के निरंतर इस्तेमाल से एचआईवी/एड्स होने की संभावना कम हो सकती है	81.8	66.8	68.6
पुरुष जिन्हें पता है कि कंडोम के निरंतर इस्तेमाल से एचआईवी/एड्स होने की संभावना कम हो सकती है	88.7	89.1	89.1
स्रोत: एनएफएचएस- 4 (2015-16)			

परियोजना प्रभावित परिवारों में एचआईवी/एड्स के बारे में जानकारी और जागरूकता: एसआईए सर्वे के दौरान, एचआईवी/एड्स के बारे में पीएएफ की जानकारी को जानने का प्रयास किया गया था। यह पाया गया कि 217 सर्वे किए गए पीएएफ में से केवल 139 पीएएफ ने एचआईवी/एड्स के बारे में सुना था। यह दर्शाता है कि लोगों को एचआईवी / एड्स के बारे में बहुत कम जानकारी है।

एचआईवी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण, एचआईवी/एड्स के बारे में लोगों की जागरूकता पर निर्भर करता है। यह पाया गया कि एचआईवी/एड्स के बारे में जानने वाले पीएएफ में एचआईवी के संचरण के बारे में अच्छी जानकारी है क्योंकि सभी 217 पीएएफ में जागरूकता है कि असुरक्षित यौन क्रिया के कारण एचआईवी संक्रमित होता है। लेकिन पीएएफ को एचआईवी के अन्य संचरण विधियों के बारे में कोई जागरूकता नहीं है, यानी, इंजेक्शन लगाने वाले उपकरण का साझा करने और गर्भावस्था/प्रसव और स्तनपान के दौरान माँ से बच्चे में होता है। यह प्रस्तावित है कि परियोजना कार्यान्वित चरण के दौरान स्थानीय लोगों के लिए एक जागरूकता शिविर आयोजित किया जाना चाहिए और प्रवासी मजदूरों के लिए भी इस तरह के शिविर होने चाहिए जो परियोजना स्थल के

आसपास के क्षेत्रों में रह रहे हों और स्थानीय लोगों के साथ घुलमिल सकें और जिससे एचआईवी/एड्स के सर्पक में आने की संभावना और अधिक हो। ठेकेदार को साइट पर सभी मजदूरों के लिए मासिक आधार पर मुफ्त और नियमित चिकित्सा जांच प्रदान करने के लिए भी अनिवार्य होना चाहिए और मजदूर शिविरों में कंडोम तक मुफ्त पहुंच प्रदान करना चाहिए। इसे एक स्थानीय एनजीओ के साथ जोड़ा जा सकता है जो जागरूकता कार्यक्रम में मदद कर सकती है।

*एचआईवी/एड्स रोकथाम के लिए एचपी सरकार द्वारा शुरू की गई पहल:* राज्य सरकार ने 22 जनवरी, 2018 को हिमाचल प्रदेश में एचआईवी पॉजिटिव से पीड़ित बच्चों के लिए पोषण योजना शुरू की। राष्ट्रीय युवा दिवस को चिह्नित करते हुए एचपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी द्वारा आयोजित एक जागरूकता अभियान के दौरान एचपी के मुख्यमंत्री द्वारा इसे शुरू करने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य 18 वर्ष की आयु तक के युवाओं को पोषण संबंधी सप्लीमेंट देना और एचआईवी पॉजिटिव की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य उन्हें एक सामान्य और स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम बनाना है।

सरकार ने हर गर्भवती मां के लिए एचआईवी परीक्षण से गुजरना अनिवार्य कर दिया है। यदि मां एचआईवी पॉजिटिव है तो यह बच्चे में वायरस को पहुंचने से रोकेगा।

नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट शो के संगठन सहित स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान तेज किया गया है जो आम जनता से संवाद करने के प्रभावी तरीके हैं। शिक्षा विभाग एचआईवी पॉजिटिव के साथ रहने वाले सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ निकट समन्वय में काम कर रहा है।

#### 5.2.6.2 संस्थागत प्रसव

प्रसूति और प्रसवपूर्व स्वास्थ्य दोनों के लिए उचित प्रसव की देखभाल महत्वपूर्ण है और जन्म के समय कुशलपूर्ण उपस्थिति को बढ़ाकर सुरक्षित मातृत्व और बच्चे का जीवित रहना मुख्य लक्ष्य है।

प्रसव के समय कौशलपूर्ण की उपस्थिति मातृ मृत्यु दर को कम करने की दिशा में प्रगति की निगरानी में एक महत्वपूर्ण सूचक है। पेशेवरों पर ध्यान के अलावा, यह महत्वपूर्ण है कि माताएं अपने बच्चों को एक उचित सेटिंग में प्रसव करें, जहां जीवन रक्षक उपकरण और स्वास्थ्यकर स्थिति भी जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हो जो माँ और/या बच्चे की मृत्यु या बीमारी का कारण बन सकती हैं।

एनएफएचएस -4 के अनुसार, चंबा जिले में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में सबसे कम है। चंबा में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 57% है जबकि हमीरपुर जिले में यह उच्चतम (91%) है और राज्य का औसत 76% है। (टेबल 5.11)

3 परियोजना जिलों में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत शिमला (77%), कुल्लू (71%) और मंडी (64%) है। ऐसा ध्यान दिया गया है कि चंबा के बाद जो संस्थागत प्रसव का सबसे कम प्रतिशत है, दूसरे और तीसरे सबसे कम जिलों में मंडी और कुल्लू हैं।

सारणी 5.11: हिमाचल प्रदेश में जिलों के अनुसार संस्थागत प्रसव		
No. क्र.सं.	Districts जिलें	Percentage प्रतिशत
1	हमीरपुर	91
2	कांगड़ा	88
3	बिलासपुर	83
4	ऊना	81
5	किन्नौर	80
6	सिरमौर	78
7	शिमला	77
8	सोलन	75
9	लाहुल और स्पीति	73
10	कुल्लू	71
11	मंडी	64
12	चामोद	57
<b>हिमाचल प्रदेश राज्य</b>		<b>76</b>
स्रोत : एनएफएचएस 4 (2015-16)		

रिसर्च टीम मंडी और कुल्लू जिलों में संस्थागत प्रसव के कम प्रतिशत में योगदान करने वाले कारकों को पता लगाने का भी प्रयास किया है। अनुसंधान टीम ने स्वास्थ्य और आईसीडीएस विभागों के साथ संस्थागत परामर्श की श्रृंखला की थी और परियोजना क्षेत्रों में महिला समूह के साथ एफजीडी का आयोजन किया। यह पता चला कि संस्थागत प्रसव को प्रभावित करने वाले कारकों में सुविधा से दूरी, परिवहन की कमी और कठिन इलाके हैं। परियोजना क्षेत्र की महिलाओं के अनुसार लंबी दूरी और पहाड़ी इलाके स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंचने में बाधाएं हैं।

#### 5.2.6.1 शिशु मृत्यु दर

शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) प्रति 1,000 जीवित बच्चों में एक साल से कम के मरने वाले बच्चों की संख्या है। एनएफएचएस -4 में हिमाचल प्रदेश में शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्में बच्चों में एक साल की आयु से पहले के 34 बच्चों की मृत्यु का अनुमान किया जाता है। शिशु मृत्यु दर अन्य पिछड़े वर्गों की तुलना में अनुसूचित जातियों (50 प्रति 1,000 जीवित जन्में बच्चों) और अनुसूचित जनजातियों (44 प्रति 1,000 जीवित जन्में बच्चों) में बहुत अधिक है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों (30 प्रति 1,000 जीवित जन्में बच्चों) से नहीं हैं।

उन माताओं की तुलना में जो 10 वर्ष या उससे अधिक वर्षों तक स्कूल गईं (26 प्रति 1,000 जीवित जन्म बच्चों) हैं और वो माताएं जो 10 वर्ष से कम समय तक स्कूल गईं (56 प्रति 1,000 जीवित जन्म बच्चों), का शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है।

#### 5.2.6.4 बच्चों की पोषण स्थिति

आहार से आश्वस्त व्यक्ति, शरीर में पोषक तत्वों के स्तर और सामान्य उपापचयी अखंडता पोषण की स्थिति स्वास्थ्य की जरूरत हैं। सामान्य पोषण की स्थिति को भोजन की खपत और पोषक तत्वों के सामान्य उपयोग द्वारा प्रबंधित किया जाता है। किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी स्थिति आम तौर पर दो कारकों पर निर्भर करती है, बाहरी कारक जैसे सुरक्षित खाना, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक कारकों और आंतरिक कारकों, जिसमें व्यक्ति की आयु, लिंग, पोषण, व्यवहार, शारीरिक गतिविधि और बीमारियां शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश में एनएचएस-4 के अनुसार, पाँच साल से कम आयु के 26% बच्चे अपनी आयु के अनुसार अविकसित या छोटे कद के हैं, जो दर्शाता है कि वे कुछ समय के लिए कुपोषित हो गए हैं। 14% कमजोर हो गये हैं, या अपने कद के अनुसार बहुत पतले हो गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप हाल ही में भोजन के सेवन या हाल ही में बीमारी के कारण वजन का कम हो सकता है, और 4% गंभीर रूप से कमजोर हो गये हैं। 21% कम वजन के हैं, जो पोषण के तहत पुरानी और गंभीर दोनों को ध्यान में रखता है।

तालिका 5.12 शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के पोषण की स्थिति का भी वर्णन करती है। प्रत्येक पोषण सूचकों में, गंभीर रूप से कमजोर होने की स्थिति को छोड़कर, कुल्लू जिला शिमला और मंडी जिलों से बेहतर है, बल्कि राज्य औसत से भी बेहतर है।

क्षेत्र	अविकसित	कमजोर	गंभीर रूप से कमजोर	कम वजन के
हिमाचल प्रदेश	26.3	13.7	3.9	21.2
शिमला जिला	27.3	13.0	1.5	24.1
कुल्लू जिला	19.6	9.9	3.7	9.1
मंडी जिला	27.5	12.2	4.4	17.1

स्रोत: एनएचएस- 4 (2015-16)

#### 5.2.6.5 एनीमिया

एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जो रक्त में हीमोग्लोबिन के निम्न स्तर को चिह्नित करती है। एनीमिया से मातृ मृत्यु दर, कमजोरी, शारीरिक और मानसिक क्षमता को कम करने, संक्रामक रोगों से अस्वस्थता को बढ़ाने, प्रसवकालीन मृत्यु दर, समय से पहले प्रसव, जन्म के समय कम वजन का होने और (बच्चों में) दुर्बल संज्ञानात्मक प्रदर्शन, प्रेरक पेशी का विकास और शैक्षिक उपलब्धि के फलस्वरूप हो सकता है। एनीमिया हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ 3 परियोजना जिलों में, खासकर महिलाओं और बच्चों में एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है।

हिमाचल प्रदेश में एनएचएस-4 के अनुसार, 6 से 59 महीने की उम्र के बच्चों में, बहुसंख्यक (54%) एनीमिक है, 15-49 साल की महिलाओं में 54% और 15-49 साल के पुरुष वर्ग में एक-पांचवें एनीमिक हैं। सभी 3 जिलों में, सभी 3 सूचकों में शिमला जिले की स्थिति बहुत खराब है, यहां तक कि राज्य के औसत से भी अधिक खराब है। (टेबल 5.13)

क्षेत्र	बच्चें (6 - 59 महीने)	महिलाएं (15 - 49 साल)	पुरुष (15 - 49 साल)
हिमाचल प्रदेश	53.7	53.5	20.1
शिमला जिला	70.0	68.7	30.6
कुल्लू जिला	54.9	59.5	16.1
मंडी जिला	37.8	39.8	16.3

स्रोत एनएचएफएस 4 (2015-16)

### 5.3 गरीबी का स्तर

गरीबी एक सामाजिक और साथ ही एक बहुआयामी घटना है। योजना आयोग गरीबी के आकलन के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी थी। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी की घटनाओं का अनुमान लगाता है। गरीबी की घटना को गरीबी अनुपात द्वारा मापा जाता है, जो प्रतिशत के रूप में व्यक्ति कुल आबादी में से गरीबों की संख्या का अनुपात है। गरीबी अनुपात को एक महीने में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के संदर्भ में परिमाणित की गई एक बहिर्जात रूप से निर्धारित गरीबी रेखा से और राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय (एनएसएसओ) के उपभोक्ता व्यय डेटा के बड़े नमूना सर्वे से प्राप्त किए गये व्यक्तियों के वर्ग वितरण से मापा जाता है।

स्थान	ग्रामीण	शहरी	कुल
भारत	25.7	13.7	21.9
हिमाचल प्रदेश	8.5	4.3	8.1

स्रोत : योजना आयोग की रिपोर्ट 2011-12

हिमाचल प्रदेश भारत के अधिक समृद्ध राज्यों में से एक है। हिमाचल प्रदेश की मुख्य उपलब्धियों में से एक लोगों को गरीबी उभारना इसकी सफलता थी। गरीबी की कुल गणना राष्ट्रीय औसत का लगभग एक तिहाई है। कुछ ही समय में हिमाचल प्रदेश न केवल छोटे राज्यों के लिए बल्कि देश के बड़े राज्यों के लिए भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बागवानी, समाज कल्याण और सम्पूर्ण वृद्धि के विकास एक मॉडल बन गया है। आज हिमाचल देश में सबसे समृद्ध और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। 3 परियोजना जिलों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का विवरण टेबल 5.14 में दिया गया है।

### 5.4 कमजोर समूह

कमजोर समूह वे समूह हैं जो किसी भी परिस्थिति में कमजोर हो सकते हैं। कमजोर समूह जिसमें भेदभाव का सामना करना शामिल है- महिला, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), बच्चे, वृद्ध, विकलांग, गरीब प्रवासी, एचआईवी/एड्स और यौन अल्पसंख्यकों से पीड़ित लोग। कभी-कभी प्रत्येक समूह अपनी कई पहचानों के कारण कई बाधाओं का सामना करता है। उदाहरण के लिए, एक विकलांग एसटी व्यक्ति एसटी होने और विकलांग होने के दोहरे भेदभाव का सामना करता है।

एसआईए सर्वे के दौरान, विभिन्न प्रकार के कमजोर परिवारों की पहचान करने का प्रयास किया गया था। टेबल 5.15 एलएचईपी स्टेज- II क्षेत्र में सर्वे किए गए परिवारों के बीच कमजोर समूहों पर विवरण को दिखाता है। यह पाया गया कि 217 सर्वे किए गए परिवारों में से 19 एसटी वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं। 217 परिवारों में से 70 परिवारों में एससी परिवारों को दोहरे भेदभाव का सामना किया है।

टेबल 5.15 : कमजोरी के प्रकार		
सं.	विवरण	संख्या
1	महिला प्रधान परिवार	3
2	एसटी परिवारों	19
3	एससी परिवारों	70
4	विकलांग व्यक्ति	2

स्रोत: एसआईए सर्वे, एलएचईपी स्टेज-II, 2019

### 5.5 भूमि का उपयोग और आजीविका

अन्य सभी देशों की तरह, भारत में भूमि को विभिन्न उपयोगों के लिए रखा गया है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी और जलवायु के साथ-साथ मानव कारकों पर निर्भर करता है जैसे जनसंख्या का घनत्व, क्षेत्र के व्यवसाय की अवधि, भूमि का कार्यकाल और लोगों के तकनीकी स्तर।

भूमि का उपयोग कृषि के लिए, वनों को उगाने के लिए, पशुओं को चराने के लिए, खनन के लिए, उद्योगों को स्थापित करने और घरों, सड़कों, रेलवे, आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। किसी भी देश के सतत विकास और समृद्धि के लिए, भूमि के उचित और सही उपयोग की आवश्यकता होती है। भूमि का उपयोग भूमि का प्रकार, उसकी गहराई, उर्वरता, जल रोकपाने की क्षमता, उपलब्ध खनिज सामग्री और परिवहन के साधनों आदि पर निर्भर करता है। कृषि के लिए भूमि का उपयोग मिट्टी के प्रकार, सिंचाई की सुविधाओं और जलवायु पर निर्भर करती है।

भारत के सर्वे करने वाले जनरल के अनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 5567 हजार हेक्टेयर है, जिसमें से 4543 हजार हेक्टेयर का कैडस्ट्रल (भू-कर संबंधी) सर्वे किया गया है और यह भूमि रिकॉर्ड में जगह पाती है। इस प्रकार, 18.39 प्रतिशत कैडस्ट्रल (भू-कर संबंधी) के 1024 हजार हेक्टेयर के शेष क्षेत्र का सर्वे किया गया और जिसकी राजस्व रिकॉर्ड (टेबल 5.17) में प्रविष्टि नहीं मिलती हैं। यह भिन्नता दूर-दराज के आंतरिक क्षेत्रों के दुर्गम होने के कारण है, जिसका सर्वे नहीं हो पाया; हालाँकि, यह संकुचित होने के लिए बाध्य है क्योंकि अधिकतर क्षेत्र राजस्व रिकॉर्ड 5.16 में स्थान पा रहे हैं।

टेबल 5.16: हिमाचल प्रदेश में नौ श्रेणियों के तहत वर्गीकरण के साथ कुल कैडस्ट्रल(भूकर संबंधी) सर्वे किया गया क्षेत्र		
सं.	एचपी में भूमि का नौ बार वर्गीकरण	कुल क्षेत्र % में
1	वनों	24.2
2	बंजर और अनुपजाऊ भूमि	17.7
3	गैर-कृषि उपयोग के लिए भूमि रखी	7.0

टेबल 5.16: हिमाचल प्रदेश में नौ श्रेणियों के तहत वर्गीकरण के साथ कुल कैडस्ट्राल(भूकर संबंधी) सर्वे किया गया क्षेत्र		
सं.	एचपी में भूमि का नौ बार वर्गीकरण	कुल क्षेत्र % में
4	सांस्कृतिक बंजर भूमि	2.7
5	स्थायी चरागाह और अन्य चराई भूमि	33.4
6	विविध के तहत भूमि, क्षेत्र में बोए गए पेड़ की फसलें शामिल नहीं	1.3
7	वर्तमान में बोने के लिए तैयार भूमि के अलावा बोने के लिए तैयार भूमि	0.4
8	वर्तमान में बोने के लिए तैयार भूमि	1.3
10	बोया हुआ कुल क्षेत्र	12.0
<b>Total कुल</b>		<b>100</b>
स्रोत: राजस्व विभाग, स्रोत: एसआईए सर्वे, एलएचईपी स्टेज- II, 2019		

## 5.6 कृषि और गैर-कृषि उपयोग

3 परियोजना जिलों के साथ-साथ परियोजना स्थलों में पहाड़ों और घाटियों की एक बड़ी श्रृंखला है जो समुद्र तल से 1500 मीटर से 2600 मीटर की ऊंचाई तक है। एलएचईपी स्टेज- II साइट समुद्र तल से लगभग 2300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जलवायु उप-उष्णकटिबंधीय से लेकर उप-आर्कटिक ठंड तक 350 मिलीमीटर की वार्षिक वर्षा के साथ 3800 मिलीमीटर तक होती है। जलवायु में, गर्मियों में दर्ज अधिकतम तापमान 39 °C (102 °F) और सर्दियों में न्यूनतम तापमान (1 °C (30° F)) है। इस क्षेत्र में लगभग सभी भागों में बहने वाली बारहमासी नदियाँ और नदियाँ हैं। स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, वर्षा और तापमान कृषि और बागवानी के लिए व्यापक अवसर और क्षमता प्रदान करते हैं।

लेकिन इस क्षेत्र में कृषि कुछ सीमाओं से ग्रस्त है। परियोजना से प्रभावित गांवों में कृषि योग्य भूमि के लिए कोई सुनिश्चित सिंचाई नहीं होने के कारण अधिकांश खेती वर्षा आधारित है। परिचालन भूमि - जोत छोटी और बिखरी हुई होती है।

इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलों में शामिल हैं: (i) अनाज - गेहूं और मक्का (ii) दलहन- तिलहन; कुट्टू; और मामूली बाजरा; (iii) नकदी फसलें - आलू, अदरक, मटर, और विभिन्न प्रकार की (iv) सब्जियाँ जिनमें मौसम और विदेशी सब्जियाँ शामिल हैं; और (v) फल, विशेष रूप से सेब, अनार, और सूखे मेवे जैसे अखरोट, पकान नट, पिस्ता, आदि इसके अलावा कुछ औषधीय और सुगंधित पौधे इस क्षेत्र में उगाए जाते हैं।

### 5.6.2 बागवानी

विभिन्न प्रकार के फलों की खेती में हिमाचल प्रदेश को जलवायु और स्थलाकृति का लाभ मिलता है। उप-उष्णकटिबंधीय फल जैसे कि आम, लीची, अमरूद, साइट्रस इत्यादि, लगभग एक महीने के बाद मैदानी इलाकों की तुलना में परिपक्व हो जाते हैं, जिससे बेहतर दाम मिलते हैं। फल राज्य के कुल खेती वाले क्षेत्र का लगभग 64

प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं, जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक सेब की खेती होती है। पिछले दो दशकों में फलों का क्षेत्र दोगुना हो गया है।

### 5.6.3 पशुधन

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोगों के लिए कृषि आजीविका का प्रमुख स्रोत है। कृषि में सुधार लाना एक कठिन कार्य है क्योंकि इसकी प्रकृति-निर्भरता और विभिन्न तकनीकी बाधाओं का अस्तित्व है। ये अवरोध पहाड़ी और पहाड़ी क्षेत्रों में कठिन इलाकों और दुर्गमता के कारण अधिक कठोर दिखाई देते हैं। फसलों, पशुपालन और बागवानी सहित कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियों के लिए इनपुट सेवाओं की डिलीवरी के लिए पहाड़ी और पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी इलाकों की तुलना में कड़े प्रयासों की आवश्यकता है। पशुधन पालन इन कृषि प्रणालियों का एक अभिन्न अंग है।

यह पता चला था कि एलएचईपी स्टेज- II के इस परियोजना क्षेत्र में पशुधन को रखना बहुत आम है। सर्वे किए गए 217 घरों में से, 345 परिवारों में पशुधन कम से कम की एक प्रजाति है, जो गाय, भैंस और बैल हैं। यह तालिका 5.17 में दी गई है।

**टेबल 5.17: प्रभावित परिवारों के स्वामित्व वाले पशुधन की सूची**

क्षेत्र		गाय		भैंस(मादा)		भैंस (नर)		बैल		बकरी	
जिला	मोहाल	जिनकेपास है	पशुधन की संख्या	जिनकेपास है	पशुधन की संख्या	जिनकेपास है	पशुधन की संख्या	जिनकेपास है	पशुधन की संख्या	जिनकेपास है	पशुधन की संख्या
शिमला	महावली	43	73	0	0	0	0	19	32	1	20
	बरगल	4	6	0	0	0	0	0	0	2	12
	तलाह	7	11	0	0	0	0	4	8	2	15
	चमोद	6	7	0	0	0	0	2	4	0	0
कुल्लू	डिगिंधर	23	35	0	0	0	0	12	24	1	8
मंडी	कोट	8	13	0	0	0	0	2	4	0	0
	फिरनू	31	46	4	10	1	1	13	24	0	0
	नंज	31	52	4	13	1	5	18	31	4	290
<b>योग</b>		<b>153</b>	<b>243</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>70</b>	<b>127</b>	<b>10</b>	<b>345</b>

स्रोत: एसआईएस सर्वे, एलएचईपी स्टेज- II, 2019

एलएचईपी स्टेज- II क्षेत्र में महिला समूह के साथ सामुदायिक परामर्श और एफजीडी से, यह दो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मिलता है: (1) इस क्षेत्र में पशुधन की उत्पादकता बहुत कम है और इसके बढ़ने की एक बड़ी गुंजाइश है, और (2) पशुधन इस पर्वतीय क्षेत्र के लिए क्षेत्र एक बड़ा वादा करता है, जहाँ भूमि-भण्डार छोटे होते हैं, जनसंख्या का बहुत अधिक अनुपात विविधीकरण को देखते हुए कृषि पर निर्भर है। चूंकि लोगों की एक बड़ी संख्या पशुधन से सीधे जुड़ी हुई है, इसलिए पशुधन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और मौजूदा सरकारी योजनाओं से उचित समर्थन प्रदान करके इसे बढ़ावा दिया जा सकता है जो कि इस परियोजना के विकास के दौरान एसजेवीएन

द्वारा जोड़ा जा सकता है।

## 5.7 रोजगार और आमदनी

### 5.7.1 औपचारिक और अनौपचारिक काम और रोजगार

औपचारिक-अनौपचारिक रोजगार दो क्षेत्रों में फैला हुआ है; संगठित (औपचारिक) और असंगठित (अनौपचारिक)। यह परिभाषित किया गया है कि औपचारिक क्षेत्र ऐसी गतिविधियों हैं जिनसे सरकार के द्वारा कर लिया जाता है और निगरानी जाती है और उन गतिविधियों को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में शामिल किया जाता है। औपचारिक क्षेत्र के विपरीत अनौपचारिक अर्थव्यवस्था वह है जिस पर न तो कर लगाया जाता है और न ही उसे जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) को शामिल किया जाता है। औपचारिक क्षेत्र विशिष्ट काम के घंटों और नियमित मजदूरी के साथ सभी नौकरियों को दर्शाता है और वर्कर्स की नौकरी सुनिश्चित होती है। इसमें सरकारी, राज्य के या निजी क्षेत्र के उद्यम, बड़े पैमाने पर संचालन जैसे बैंक और अन्य निगम शामिल हैं। इसके विपरीत, अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र ऐसे हैं जहां कर्मचारियों या श्रमिकों के नियमित काम के घंटे और मजदूरी नहीं होती है और उन्हें करों से छूट दी जाती है। यह मुख्य रूप से छोटे पैमाने पर रोजगार और आय पैदा करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ वस्तुओं और सेवाओं के प्राथमिक उत्पादन से संबंधित है। एक स्ट्रीट वेंडर अपने दैनिक रोटी कमाने के लिए अपने कृषि उत्पादों को सड़क पर बेच रहा है, जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र दोनों भारतीय आर्थिक क्षेत्र बनाते हैं।

एलएचईपी स्टेज- II क्षेत्र में एसआईए सर्वे के डेटा विश्लेषण से पता चला है कि परियोजना से प्रभावित 15 साल से अधिक उम्र के 918 व्यक्तियों में से 477 रोजगार में हैं (52%) और लगभग(441) काम नहीं कर रहे हैं (48%)। यह टेबल 5.18 में दिया गया है।

पीएपी जो काम कर रहे हैं	गांव का नाम	पीएपी की संख्या	पीएपी जो काम कर रहे हैं		PAPs Not Working पीएपी जो काम नहीं कर रहे हैं	
			संख्या	%	संख्या	%
शिमला	महावली	228	130	57.0	98	43.0
	बरगल	38	21	55.3	17	44.7
	तलाह	28	13	46.4	15	53.6
	चमोद	24	11	45.8	13	54.2
कुल्जू	डिगिंधर	203	96	47.3	107	52.7
मंडी	कोट	61	33	54.1	28	45.9
	फिरनू	184	104	56.5	80	43.5
	नंज	152	69	45.4	83	54.6
<b>योग</b>		<b>918</b>	<b>477</b>	<b>52.0</b>	<b>441</b>	<b>48.0</b>

स्रोत: एसआईए सर्वे, एलएचईपी स्टेज- II, 2019

आगे के विश्लेषण से यह पता चला कि 477 व्यक्तियों में से जो काम कर रहे हैं केवल 9 राज्य के बाहर काम कर रहे हैं, जहाँ अन्य अपने मूल स्थानों में और आस-पास के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उन व्यक्तियों में से जो काम कर रहे हैं 128 व्यक्ति (27%) औपचारिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे सरकारी और निजी नौकरियों, जबकि 349 अनौपचारिक क्षेत्रों (73%) में हैं। सभी 349 जो अनौपचारिक क्षेत्र में हैं वे कृषि और कृषि संबद्ध गतिविधियों से जुड़े हैं और छोटे व्यवसाय और व्यापार कर रहे हैं।

### 5.7.2 घरेलू श्रम और महिलाओं के काम का विभाजन

श्रम के घरेलू विभाजन पर महिलाओं की संबंधित स्थिति का प्रभाव, विशेष रूप से घरेलू कार्यों में पुरुष साझेदारों का हिस्सा, महत्वपूर्ण लेकिन किसी न किसी तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। सर्वेक्षण के दौरान इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया था कि दोनों साथी घरेलू कामों में श्रम के लिंग विभाजन पर संभावित प्रभाव को देखने के लिए भाग लेते हैं, विशेष रूप से घरेलू काम का पुरुष हिस्सा।

श्रम के घरेलू विभाजन पर महिलाओं के सापेक्ष पदों का प्रभाव, खासतौर पर घरेलू काम में पुरुषों का भाग,

यह पाया गया कि परियोजना क्षेत्र में हालांकि घरेलू श्रम में महिला की एक बेहतर संबंधित स्थिति है, लेकिन घरेलू काम के भाग में पुरुष भागीदारों की भूमिका भी बढ़ी है। हालाँकि, घरेलू कामों में महिलाओं की भारी भागीदारी के बावजूद, घरेलू कामों में पुरुषों और महिलाओं के बीच समय का बँटवारा लिंग के आधार पर अभी भी बहुत भिन्न है। टेबल 5.19 दर्शाती है कि विशेष रूप से परियोजना क्षेत्र में, अधिकतर महिलाएं घरेलू काम में शामिल हैं जैसे खाना बनाना जबकि विभिन्न घरेलू काम जैसे पानी लाना, पशु का प्रबंधन, बुर्जुगों/बच्चों की देखभाल और बाजार से सामान खरीदने के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों एकसाथ काम करते हैं।

क्रम	घरेलू गतिधियां	केवल पुरुष	केवल महिलाएं	दोनों	योग
1	खाना बनाना	8	207	1	216
2	पीने/खाना पकाने के लिए पानी लाना	5	208	2	215
3	पशुओं का प्रबंधन	2	22	137	161
4	कृषि क्षेत्र में कार्य करना	27	26	147	200
5	साथ ही बाहर काम कर रहे हैं	12	0	4	16
6	बच्चों को पढ़ाना	1	5	79	58
7	बुर्जुगों/ बच्चों की देखभाल करना	0	7	65	72
8	बाजार से खरीदने का प्रावधान	3	40	166	209

स्रोत: एसआईए सर्वे, एलएचईपी स्टेज- II, 2019

### 5.7.3 पलायन

कृषि क्षेत्रों में मौसमों पर आधारित मानव प्रवास आम है। कई मामलों में, मनुष्य अपने मवेशियों या भेड़ों के साथ मौसम के आधार पर कम/अधिक ऊँचाइयों पर चले जाते हैं। इस पलायन का एक प्रमुख उदाहरण गद्दी चरवाहे है, जो अधिकतर परियोजना क्षेत्र में देखे जाते हैं। गद्दी चरवाहे हिमाचल प्रदेश में एक देहाती समूह हैं। उनकी आर्थिक गतिविधि भेड़ पालन और कृषि के आसपास घूमती है।

सार्वजनिक परामर्श और समुदाय के साथ बैठक के दौरान यह बताया गया कि परियोजना क्षेत्र में कई परिवार मौसम, यानी, गर्मियों और सर्दियों में बदलाव के अनुसार चलते हैं। सर्दियों के मौसम (अक्टूबर से मार्च) के दौरान, वे निचले इलाकों में रहते हैं यानी उनके संबंधित गांवों में। अप्रैल तक, जब गर्मियां शुरू होती हैं, तो वे हिमालय में ऊपर चले जाते हैं जब बर्फ पिघलती है और पहाड़ हरे भरे होते हैं। ग्रामीणों के अनुसार पहाड़ों की उच्च श्रेणी तक पहुंचने में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है और उन्हें लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।

ग्रामीणों ने यह भी बताया कि वन विभाग पहाड़ और वन क्षेत्र में पलायन के दौरान उनसे प्रति जानवरों के लिए कर एकत्र करता है। यह एक बार का कर है और यह राशि प्रत्येक बड़े जानवर के लिए रु .16/- है और प्रत्येक छोटे जानवर के लिए रु 6/- है। पलायन के दौरान वे ज्यादातर व्यापारियों को भेड़, ऊन और बकरियों को बेचने पर निर्भर होते हैं, अक्सर वे उन गांवों में भोजन अनाज के लिए मांस का आदान-प्रदान करते हैं जहां से वे प्रवास के दौरान गुजरते हैं। चूंकि दूध को संरक्षित करने की कोई सुविधा नहीं होती है, वे दूध से पनीर और खोआ तैयार करना पसंद करते हैं और इसे उन व्यापारियों को बेचते हैं जो वन क्षेत्र में उनके रहने के स्थानों से एकत्र करते हैं।

एसआईए सर्वे और समुदाय के साथ बैठक से यह पता चला कि काम की तलाश में स्थानीय लोगों का दूसरे क्षेत्रों में प्रवास लगभग नगण्य है।

### 5.7.4 घरेलू आय का स्तर

घरेलू आय एक विशेष घर या निवास स्थान साझा करने वाले सभी लोगों की संयुक्त आय की एक माप है।

एसआईए सर्वेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों की औसत वार्षिक घरेलू आय के साथ-साथ औसत वार्षिक घरेलू व्यय प्रदान करता है। घरेलू आय में सभी स्रोतों से एक ही परिवार में रहने वाले 15 वर्ष से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय शामिल है। यह पता चला था कि औसत वार्षिक घरेलू आय रुपये 4,11,329/- है। 217 पीएएफ के लिए इसकी गणना की गई है। जैसा कि पता चला है कि घरेलू खर्च आय से कम है, यह संपर्क किये गये सभी पीएएफ के बीच देखा गया है। उन्होंने संकेत दिया है कि उनके पास उनकी आय से बचत है और अपनी भूमि गिरवी रखकर कृषि उद्देश्य के लिए ऋण भी लेते हैं। यह इस क्षेत्र के लोगों के बीच एक सामान्य व्यवहार है।

### 5.7.5 खाद्य सुरक्षा

मुख्य अधिनियम(आरएफसीटीएलएआरआरए 2013) के अध्याय-III में प्रदान किया गया खाद्य सुरक्षा की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है। सेक्शन 10 (1) में कहा गया है, "इस अधिनियम के तहत किसी भी सिंचित बहु-फसली भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि अनिवार्य स्थिति में ना हो (3) 'जब भी बहु-फसल सिंचित भूमि को उप-धारा (2) के तहत अधिग्रहित की जाती है, कृषि योग्य बंजर भूमि के समतुल्य क्षेत्र को कृषि उद्देश्यों के लिए विकसित किया जाएगा या अधिग्रहित भूमि के मूल्य के बराबर राशि को खाद्य-सुरक्षा बढ़ाने के लिए कृषि में निवेश के लिए उपयुक्त सरकार के पास जमा की जाएगी"।

अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित निजी भूमि के भूमि रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद यह पाया गया कि कोई भी भूखंड सिंचित बहु-फसली भूमि'की श्रेणी में नहीं आ रहा है। इन भूमि अभिलेखों को संबंधित पटवारियों और कानूनगो के परामर्श से पुनः सत्यापित किया गया। इसलिए, एलएचईपी स्टेज-II के लिए अधिग्रहण की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि के लिए उप-धारा (3) लागू नहीं होती है।

खाद्य सुरक्षा लोगों को पर्याप्त रूप से खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर देती है, विशेष रूप से उन लोगों को जो सामान्य पोषण से वंचित हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चिंता रही है।

भारत उन कुछ देशों में से एक है, जिन्होंने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए व्यापक कार्यक्रमों के साथ प्रयोग किया है। अनाज में आत्मनिर्भरता और अनाज की खरीद और सार्वजनिक वितरण, रोजगार कार्यक्रमों इत्यादि के माध्यम से पहले से ही अस्थायी खाद्य असुरक्षा पर काबू पाने के संदर्भ में इसने पर्याप्त प्रगति की है।

सरकार का बड़ी खाद्य सुरक्षा और गरीबी-विरोधी कार्यक्रम हैं। ये अनुबंध 9 में दिए गए हैं

### 5.8 स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ

स्थानीय क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि की आर्थिक प्रणाली और रेंज जो एक स्थानीय आबादी को सेवा प्रदान करती है और इस अर्थव्यवस्था का विकास, विस्तार और अधिक रोजगार का सृजन किया जा रहा है, जो कि स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकता है। परियोजना क्षेत्र में प्राथमिक सर्वे से पहचानी गई स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियां शामिल हैं। सार्वजनिक परामर्श से प्राप्त निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि कृषि और बागवानी संबंधी गतिविधियों को छोड़कर परियोजना क्षेत्र में इस प्रकार कोई स्थानीय आर्थिक गतिविधियां नहीं हैं। सेब फल की कटाई के समय लोगों को कुछ मजदूरी का कार्य मिलते हैं लेकिन यह केवल कुछ दिनों के लिए होता है जैसे अधिकतम 30 से 45 दिन।

प्रभावित परिवारों के बीच स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ टेबल 5.20 में दी गई हैं। यह इंगित करता है कि लगभग 61% लोग अधिकतर कृषि में लगे हुए हैं जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी (14%) और निजी सेवा (13%) में भी काम करने वाले लोग हैं।

**टेबल 5.20: परियोजना क्षेत्र में स्थानीय आर्थिक गतिविधियाँ**

संख्या	आर्थिक गतिविधियां	महिला	पुरुष	योग	काम करने वाली कुल जनसंख्या का %
1	कृषि	92	200	292	61.22%
2	कृषि मजदूरी	3	7	10	2.09%
3	गैर-कृषि मजदूरी	2	4	6	1.26%
4	बिजनेस	2	39	41	8.6%
5	सरकारी नौकरी	18	48	66	13.84%
6	प्राइवेट नौकरी	11	51	62	12.99%
<b>योग</b>		<b>128</b>	<b>349</b>	<b>477</b>	<b>100%</b>

स्रोत: एसआईए सर्वे, एलएचईपी स्टेज- II, 2019

### 5.8.1 ऋण तक पहुंच

यह जांचने का प्रयास किया गया था कि परियोजना क्षेत्रों के परिवारों को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संस्थानों में किस हद तक क्रेडिट संस्थानों तक पहुंच प्राप्त हुई है। यह परियोजना क्षेत्र के 8 गांवों में परिवारों की ऋण प्रोफाइल की जांच करके किया गया है। विशेष रूप से, एसआईए सर्वे के दौरान एकत्र किए गए विस्तृत घरेलू डेटा का उपयोग करके और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों से ऋण और लोन की हिस्सेदारी की जांच करके इसका पता लगाया गया है

इन सर्वे ने सभी बकाया ऋणों के साथ-साथ सर्वे से पहले फसल वर्ष में उधार लिए गए सभी ऋणों (बकाया या चुकाए गए) पर विस्तृत डेटा एकत्र किया। जानकारी प्रत्येक ऋण, मूल उधारी, ब्याज की दर, ऋण का स्रोत, उधार लेने का उद्देश्य और ऋण प्राप्त करने का गिरवी रखी गयी संपत्ति के संबंध में एकत्र की गयी थी।

ऋण के स्रोत या उधारदाताओं को औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं में वर्गीकृत किया गया था। कामर्शियल बैंक्स (निजी क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्रों दोनों में), सहकारी समितियों और ग्रामीण बैंक में औपचारिक क्षेत्र शामिल हैं, और अन्य सभी (व्यापारियों, निजी धन साहूकारों, स्वयं सहायता समूहों और रिश्तेदारों/दोस्तों सहित) में अनौपचारिक क्षेत्र शामिल हैं।

एसआईए सर्वे टीम ने परियोजना प्रभावित परिवारों द्वारा लिए गए ऋण के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। यह पाया गया कि 217 परिवारों में से 45 परिवारों ने पिछले वर्ष के दौरान ऋण लिया है। सभी 45 परिवारों ने औपचारिक क्षेत्रों से ऋण लिया है और किसी ने भी अनौपचारिक क्षेत्र से नहीं लिया है। परिवारों ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए लोन लिया है, जिसमें कृषि गतिविधियों और घर का निर्माण शामिल है। ऋण लेने के लिए अधिकांश परिवारों ने जमीन के अलग-अलग संपत्ति गिरवी रखी है जैसे जमीन के पेपर।

### 5.8.2 मजदूरी की दरें

भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में कुछ रोजगार में मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करने का प्रावधान है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भारतीय श्रम कानून से संबंधित संसद का एक अधिनियम है जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है जिसका कुशल और अकुशल मजदूरों को भुगतान किया जाना चाहिए।

पूरे देश के लिए कोई एक राष्ट्रीय स्तर की न्यूनतम मजदूरी नहीं है, लेकिन राज्यों और भौगोलिक क्षेत्रों में भिन्न होती है। यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी राज्य सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से कम न्यूनतम वेतन तय न करे। भारत एक विशाल देश है जहाँ राज्यों के बीच अलग-अलग जीवन यापन की लागत है। यदि राज्यों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पहले से ही 'राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी' से अधिक है, तो राज्यों को उनके मजदूरी के स्तर को कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मजदूरी विधेयक पर संहिता चार श्रम कानूनों को जोड़ती है यानि कि मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बोनस का भुगतान अधिनियम, 1965 और समान मजदूरी अधिनियम, 1976.

विधेयक में कहा गया है कि राज्य सरकारें उनके न्यूनतम वेतन को अन्य कारकों के बीच "आवश्यक कौशल, श्रमिक को सौंपे गए कार्य की योग्यता, श्रमिक के रहन-सहन की लागत, काम के स्थान की भौगोलिक स्थिति," अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए तय करेगी. वर्तमान में, विभिन्न राज्य स्थानीय परिस्थितियों, रहन-सहन की लागत और अन्य कारकों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के अपने स्तर को तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

इसके अलावा, विधेयक यह प्रस्तावित करता है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को कवर करने वाले सभी रोजगार पर लागू होगी। वर्तमान कानून, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, 45 अनुसूचित रोजगार में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों को तय करने और संशोधित करने के मामले में राज्य सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के तहत एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधान के तरह मौजूदा सभी 45 अनुसूचित रोजगार में करने करने वाले लोगों के लिए 01.04.2019 से अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी रुपये 225 रुपये से बढ़ाकर रु.250 प्रति दिन या रु.6,750 से बढ़ाकर रु.7500 प्रति माह कर दी है।

अप्रैल 1, 2019 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की न्यूनतम मजदूरी दर को अनुबंध 10 के रूप में संलग्न किया गया है

समुदाय के लोगों के परामर्श से यह पता चला कि इस क्षेत्र में मजदूरी की उपलब्धता बहुत कम है। ज्यादातर लोगों को कृषि क्षेत्र और निर्माण कार्यों में मजदूरी मिलती है। यह बताया गया कि पुरुष और महिला दोनों को दैनिक वेतन के रूप में एक ही राशि मिलती है जो कि रु200/- से ऊपर है।

### 5.8.3 महिलाओं की विशिष्ट आजीविका गतिविधियाँ

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी महिलाओं, परिवार और समुदाय को सशक्त बनाती है। कार्यबल में महिलाओं की आवश्यकता के बारे में स्वीकार्यता के बावजूद, भारत में महिलाओं के लिए काम के अवसर बहुत अच्छे नहीं हैं।

एसआईए सर्वे में श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी का आकलन करने की कोशिश की गई थी। सारणी 5.21 इंगित करता है कि सर्वेक्षण किए गए परिवारों में महिलाओं की भागीदारी कुल कार्यबल के साथ बहुत कम है, महिलाओं की भागीदारी दर पुरुष भागीदारी की तुलना में आधे से भी कम है।

टेबल 5.21: लिंग द्वारा 15-64 वर्षों के भीतर लोगों की रोजगार स्थिति			
लिंग द्वारा व्यक्ति	15 – 64 साल की उम्र	रोजगार में कुछ	रोजगार में प्रतिशत
पुरुष	320	413	77.48%
महिला	109	404	26.98%
स्रोत: एसआईए सर्वेक्षण, एलएचईपी स्टेज- II, 2019			

15-64 वर्ष की आयु के भीतर काम करने वाली महिलाओं के रोजगार के प्रकारों के बारे में आगे के आकलन से यह पता चला कि अधिकांश महिलाएँ कृषि और संबद्ध सेवाओं से जुड़ी हैं।

### 5.8 ऐसे कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं

#### 5.9

रिपोर्ट के इस भाग में, यह उन विभिन्न कारकों का विश्लेषण करने का प्रयास करेगा जो एलएचईपी स्टेज-II परियोजना स्थल में स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं। इस संबंध में एसआईए हाउसहोल्ड सर्वे के अलावा विभिन्न हितधारकों के साथ और संस्थागत स्तर पर परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित की गई। इसके अलावा, एफजीडी से पुरुषों और महिलाओं दोनों से, साइट पर जाकर और व्यक्तिगत निरीक्षण से जानकारी एकत्र की गई थी।

#### 5.9.1 सड़कें और परिवहन

ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका में सुधार के लिए सड़कें स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण सक्षम स्थिति हैं। ग्रामीण सड़कों के सुधार को मोटे तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक मौलिक पूर्व शर्त के रूप में पहचाना जाता है। पृथक्ता और गतिशीलता की कमी को व्यापक रूप से गरीबों द्वारा उनकी कमजोरी को प्रभावित करने और उनकी गरीबी को बनाए रखने वाले कारकों के रूप में पहचाना जाता है। सड़क सुविधाएं गरीबों के लिए आर्थिक अवसर, ग्रामीण परिवहन सेवाओं के प्रावधान, बाजारों में अवसर प्रदान करने और काम के लिए मौसमी प्रवास के अवसर प्रदान कर सकती हैं।

यह सामाजिक उद्देश्यों के लिए घरेलू यात्रा के अवसरों में सुधार करता है, जैसे कि परिवार के पास जाना या स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बनाना। एक ग्रामीण सड़क गरीबों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर इन सेवाओं तक पहुंचने का अवसर प्रदान करती है और यह सरकार को गरीबों तक पहुंचने का अवसर भी देती है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लिए बुनियादी परिवहन की जरूरतें होती अलग हैं। गरीबों के पास समय और ऊर्जा की कमी होती है जबकि बेहतर समूहों के पास समय, ऊर्जा और पूंजी होती है। इसलिए बेहतर समूहों परिवारों के पास अपनी आजीविका गतिविधियों का विस्तार करने के लिए बेहतर अवसर हो सकते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य एलएचईपी स्टेज-II परियोजना क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आजीविका पर मौजूदा सड़कों और परिवहन के प्रभाव को समझना है।

यह परियोजना स्थल हरियाणा के कालका में नवीनतम रेल हेड से लगभग 178 किमी दूर स्थित है और शिमला, नल्हेड़ा और चाबा होते हुए एनएच-5 और उसके बाद एसएच-13 और एमडीआर-22 होते हुए पहुंचा जा सकता है।

निकटतम एयरपोर्ट जुबेर हट्टी (शिमला) है जो परियोजना स्थल से लगभग 93 किमी दूर है। निकटतम इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना स्थल से 205 किमी की दूरी पर चंडीगढ़ में स्थित है।

एसएआई हाउसहोल्ड सर्वे से यह बताया गया था कि परियोजना क्षेत्र में प्रमुख परिवहन सुविधा बस सेवाएं हैं। परियोजना से प्रभावित अधिकांश गांव मोटर योग्य सड़क से बहुत दूर हैं। गांव के सर्वे के दौरान स्टडी टीम ने मोटर योग्य सड़क से परियोजना प्रभावित गांवों की दूरी का आकलन करने का प्रयास किया। (टेबल 5.22)।

जिला	गांव का नाम	मोटर योग्य सड़क से दूरी
शिमला	महावली	0 km
	बरगल	0.5 km
	तलाह	0.5 km
	चमोद	0 km
कुल्जू	डिगिंधर	0.2 km
मंडी	कोट	0.5 km
	फिरनू	2 km
	नंज	0 km

स्रोत: एसआईए सर्वेक्षण, एलएचईपी स्टेज- II, 2019

जब गाँव के बाहर परिवहन के सबसे पसंदीदा तरीके को जानने की कोशिश की गई तो अधिकांश परिवारों द्वारा यह बताया गया कि बस उनके आस-पास के बाजारों, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों जैसे बीडीओ कार्यालय, तहसील कार्यालय, आदि की यात्रा के लिए एकमात्र उपलब्ध परिवहन है जहां बस से पहुँचा जा सकता था। परियोजना क्षेत्र की महिलाओं के साथ एफजीडी के दौरान यह बताया गया कि समुदाय के अंदर महिलाओं को अपने बच्चों के साथ आसपास के उप केंद्रों में स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए अधिक बार जाना पड़ता है। वे घरेलू वस्तुओं के लिए भी यात्रा करते हैं, फसल प्रसंस्करण के लिए, मवेशियों के लिए चारे इकट्ठा करने, जलाने वाली लकड़ी एकत्र करने के लिए यात्रा करती हैं और गांव और आसपास के गांवों में सामाजिक यात्रा भी करती हैं। महिलाओं ने बताया कि इन सभी कार्यों के लिए उन्हें पहाड़ी इलाकों में पैदल यात्रा करनी पड़ती है। पुरुष भी इन कामों के लिए पैदल जाते हैं, लेकिन कुछ पुरुषों के पास निजी साधन जैसे मोटरसाइकिल है।

### 5.9.2 सिंचाई की सुविधा

स्टडी टीम में इन तीन जिलों में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सिंचाई योजनाओं और कवर किये गये कुल क्षेत्रफल के बारे में जानने के लिए सिंचाई और सावर्जनिक स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया है।

टेबल 5.23 जिलों में बोया गया कुल क्षेत्रफल और सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल को दर्शाती है।

जिला	बोया गया कुछ क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर में)
शिमला जिला	69620	18636.31

टेबल 5.23: जिलों में 3/2018 तक सिंचाई के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र		
जिला	बोया गया कुछ क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर में)
कुल्लू जिला	38575	8692.78
मंडी जिला	91521	37625.18
स्रोत: सिंचाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार		

परियोजना से प्रभावित गांवों में एसआईए के सर्वे के अनुसार, भूमि खोने वाले परिवारों के पास सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। सभी भूमि वर्षा-सिंचित आधारित हैं और कृषि के लिए मानसून पर निर्भर हैं।

### 5.9.3 बाजारों तक पहुंच

एक कुशल विपणन प्रणाली उत्पादकों को बेहतर मूल्य प्रदान कर सकती है और उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्धता में सुधार कर सकती है। एसआईए स्टडी टीम ने समुदाय के लोगों के साथ कई बैठकें कीं और परियोजना क्षेत्र के लोगों की बाजारों तक पहुंच और लोगों द्वारा सामना की जाने वाली विपणन समस्याओं को समझने के लिए पास के बाजार क्षेत्र में गये, जो परियोजना क्षेत्र के पास मौजूदा बाजार है।

एलएचआईपी स्टेज- II परियोजना क्षेत्र के आसपास के गांवों के लोग मुख्य रूप से अपने दिन-प्रतिदिन के उपभोग के लिए दो पास के स्थानीय बाजारों पर निर्भर हैं। लुहरी में बाजार परियोजना स्थल से लगभग 22 किलोमीटर दूर है जबकि रामपुर परियोजना स्थल से 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर एक और स्थानीय बाजार है। बड़ी खरीद के लिए लोग शिमला जाते हैं जो 120 किलोमीटर की दूरी पर है।

चर्चा के दौरान समुदाय के लोगों ने कहा है कि वे बाजारों तक अपनी पहुंच के संबंध में कई समस्याओं का सामना करते हैं। परियोजना क्षेत्र के अधिकांश गांव दुर्गम हैं और कई दिनों से मानसून से भारी बारिश में गिर रहे हैं। बारिश के मौसम में भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं अक्सर होती हैं। कई गांव मोटर योग्य सड़कों से नहीं जुड़े हैं। मानसून के मौसम के दौरान सड़क की सतह खराब हो गयी है और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

### 5.9.4 पर्यटक स्थल

पर्यटन हिमाचल प्रदेश में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक रहा है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र का राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 6.6 प्रतिशत योगदान है। राज्य में घरेलू पर्यटकों की आमद 2017 में 19.13 मिलियन तक पहुंच गई जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 470,992 पर पहुंच गई। टेबल 5.24 2017 के दौरान 3 जिलों में आये पर्यटकों की संख्या को प्रदर्शित करती है

टेबल 5.24: 3 जिलों में आने वाले पर्यटक			
जिला	घरेलू पर्यटक (हजार में)	विदेशी पर्यटक (हजार में)	कुल (हजार में)
शिमला जिला	3318	162	3480
कुल्लू जिला	3732	133	3865
मंडी जिला	1231	10	1242
स्रोत: पर्यटन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार			

1991 में राज्य सरकार की पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। बिजनेस और गतिविधि-उन्मुख पर्यटन ने अधिक पारंपरिक छुट्टियों के पर्यटन में प्रवेश किया है।

### 5.10 ऐसे कारक जो स्थानीय आजीविका में योगदान करते हैं

स्थानीय आजीविका मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि पर निर्भर करती है। इसके दो मायने हैं, एक बारिश से होने वाली कृषि है जो भूमि के मालिक अपनी जमीन पर ही करते हैं। फलों के मौसम के दौरान सेब सहित मौसमी स्थानीय फल होते हैं जो इस राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर योगदान करता हैं। सेब की फसल के मौसम के दौरान अवसर होते हैं, जब स्थानीय किसानों या सेब उत्पादकों को वर्ष की दूसरी छमाही में पीक सीजन के दौरान श्रम शक्ति की कमी महसूस होती है। दूसरी बात यह है कि कुछ छोटे व्यवसाय हैं जो मांग के कारण और पर्यटन उद्योग के कारण पनप रहे हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है।

### 5.11 रिश्तेदारी पैटर्न और सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन

संयुक्त परिवार हिमाचल प्रदेश में परिवार का सबसे सामान्य रूप है, लेकिन एक महत्वपूर्ण संस्थान होने के बावजूद, यह सामाजिक रूप से अज्ञात हिथरो बना हुआ है। अन्य क्षेत्रों की तरह, हिमाचल प्रदेश में भी सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, शहरीकरण, शैक्षिक उन्नति, तर्कसंगत सोच, महिलाओं की आजादी, राजनीतिक परिवर्तन और इसी तरह आगे जैसे बहुआयामी बलों के बढ़ते प्रभाव की स्थिति में, न केवल नए मानदंड और मूल्य उभर रहे हैं, बल्कि पारंपरिक मानदंड और मूल्य को चुनौती दी जा रही है। लोग, विशेष रूप से आज के युवा, परंपराओं का पालन करना पसंद नहीं करते हैं। परिवर्तन के दबाव में, परिवार के सदस्यों के बीच रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है। परिवार के भीतर रिश्तों के पुनर्मूल्यांकन के संदर्भ में, यह समझना जरूरी है कि कल के भावी माता-पिता, संयुक्त परिवार की बरसों-पुरानी संस्था को कैसे देखते हैं।

हिमाचल प्रदेश में, भूमि अधिकार आम तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वितरित किए जाते हैं। राज्य के नियमों के अनुसार, प्रवासी "देवभूमि" में जमीन नहीं खरीद सकते। इसलिए, यहां की भूमि पैतृक संपत्ति है और यह केवल बच्चों/पत्नी को समान रूप से वितरित की जाती है जब तक कि उनकी वसीयत कुछ और नहीं कहती है।

कई मामलों में, यह देखा गया है कि वर्तमान भूमि मालिकों के नाम मूल भूस्वामी के निधन के बाद भी राजस्व विभाग के साथ अपडेट नहीं किए गए हैं। किसी भी भूस्वामी की मृत्यु के मामले में, भूमि का स्वामित्व स्वतः उनके बच्चों/पत्नी को हस्तांतरित हो जाता है।

स्थानीय लोगों और प्रभावित परिवारों के साथ सामाजिक सर्वे चर्चा के दौरान पता चला है कि अपनी बहन की शादी के बाद, भाई जमीन के व्यावहारिक मालिक हैं क्योंकि वे भूमि की रक्षा कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और कृषि उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं। प्रभावित परिवार के सदस्यों में से कुछ ने संकेत दिया है कि परिवार में विभाजन के कारण संपत्ति का विखंडन भूमि क्षेत्र को कृषि गतिविधियों के लिए काफी हद तक आर्थिक रूप से अस्थिर बना रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि बहनें अपने वैवाहिक परिवार या ससुराल के स्वामित्व वाली भूमि की खेती में लगी थीं।

### 5.12 परियोजना क्षेत्र में संगठन

हिमाचल प्रदेश राज्य को 12 जिलों में विभाजित किया गया है, जिन्हें तीन प्रभागों शिमला, कांगड़ा और मंडी में बांटा गया है। जिलों को 69 उप-विभाजनों, 78 ब्लॉकों और 145 तहसीलों में विभाजित किया गया है।

परियोजना क्षेत्र में निम्नलिखित संगठन के पदचिह्न पाये गये जो नीचे टेबल 5.25 में दी गई हैं।

टेबल 5.25: परियोजना क्षेत्र में संगठन		
क्रम	संस्थान	विवरण
1.	प्रशासनिक संगठन	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ पंचायत</li> <li>▪ पटवारी कार्यालय</li> <li>▪ सिंचाई और जन स्वास्थ्य कार्यालय</li> <li>▪ बिजली विभाग</li> <li>▪ कृषि विभाग</li> <li>▪ लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी)</li> </ul>
2.	राजनीतिक संगठन	<ul style="list-style-type: none"> <li>कांग्रेस</li> <li>भाजपा</li> </ul>
3.	समुदाय आधारित और नागरिक समाज संगठन	<ul style="list-style-type: none"> <li>मंदिर समिति</li> <li>▪ महिला मंडल</li> </ul>
स्रोत: एसआईए सर्वेक्षण, एलएचईपी स्टेज- II, 2019		

### 5.15 क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं

परियोजना क्षेत्र की क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाओं को शिमला, कुल्लू और मंडी तीन जिलों के इतिहास से समझा जा सकता है, जिसमें परियोजना स्थित होना प्रस्तावित है।

#### शिमला

शिमला उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य का एक जिला है। इसका मुख्यालय राज्य की राजधानी शिमला है। पड़ोसी जिले उत्तर में मंडी और कुल्लू, पूर्व में किन्नौर, दक्षिण-पूर्व में उत्तराखंड, दक्षिण पश्चिम में सोलन और दक्षिण में सिरमौर हैं। जिले की ऊंचाई 987 मीटर (3,238 फीट) से 4,500 मीटर (14,764 फीट) तक है।

2011 के अनुसार यह कांगड़ा मंडी के बाद हिमाचल प्रदेश का तीसरा (12 में से) सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। यह हिमाचल प्रदेश का सबसे शहरी जिला है।

जिले में सबसे अधिक प्रचलित धर्म हिंदू धर्म है। हिंदी और पहाड़ी बोली जाने वाली भाषाएँ हैं। पर्यटन और कृषि/बागवानी आय के प्रमुख स्रोत हैं।

## कुल्लू

कुल्लू भारत के हिमाचल प्रदेश में एक जिला है। यह जिला मध्य हिमाचल में स्थित है और अपने पर्यटन केंद्रों और हिमालयी ट्रैक के लिए प्रसिद्ध है जो लाहौल और स्पीति के निकटवर्ती जिलों, किन्नौर, मंडी और कांगड़ा जिलों के बीच के सुदूर क्षेत्रों को जोड़ता है जो क्रमशः कुल्लू के उत्तर-उत्तर पूर्व, पूर्व, पश्चिम में है। जिला कुछ प्राचीन बस्तियों, पारंपरिक हथकरघा और सेब की खेती का भी एक स्थान है। यह दक्षिण में रामपुर शहर से लेकर उत्तर में रोहतांग दर्रे तक फैला हुआ है। मुख्य कुल्लू घाटी जो पीर पंजाल हिमालय और धौलाधार या भंगाल क्षेत्र के उत्तरी छोर के बीच में स्थित है, इसकी ऊंचाई 833 मी से 3330 मीटर तक है, जो कि ऑट टनल नॉर्थ पोर्टल (मंडी जिला प्रशासनिक सीमा में कुछ क्षेत्रों से कम है) से लेकर एनएच3 और एनएच 505 पर रोहतांग टनल साउथ पोर्टल तक फैला है।

जिले की सबसे बड़ी घाटी को कुल्लू घाटी कहा जाता है, जिसे देवताओं की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार कुल्लू जिले में 4 उप-मंडल, 4 तहसील और 2 उप-तहसील शामिल हैं। चार तहसीलें कुल्लू मनाली, बंजार और निरमंड और दो उप-तहसीलें हैं, जो अननी, और सेंज है।

## मंडी

मंडी (मंडी), जिसे पहले मांडव नगर के नाम से भी जाना जाता था, साहोर (तिब्बती: जहूर) के नाम से भी जाना जाता है, जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले का एक प्रमुख शहर और एक नगरपालिका परिषद है।

मंडी अपने 81 प्राचीन पुराने पत्थरों वाले शैव मंदिरों और उनकी विशाल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इस वजह से, इसे अक्सर "वाराणसी ऑफ हिल्स" भी कहा जाता है।

15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के गठन के समय मंडी और सुकेत की तत्कालीन रियासतों के सम्मेलन से मंडी जिला का गठन हुआ था। तब से यह मंडी जिले के जिला मुख्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। मंडी जिले में 7 तहसीलें शामिल हैं, जैसे जोगिंदर नगर, सरकाघाट, सुंदर नगर, सदर मंडी, चच्योट, थुनाग, करसोग और 9 उप-तहसील, यानी, लडभडोल, पाढेर, संधोल, धर्मपुर, बलदवारा, निहरी, कोटली, ऑटो, बाली चौकी।

विकास गतिविधियों के उद्देश्य से जिले को 10 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। जिले में 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 9,00,987 व्यक्ति और 3,950 वर्ग किमी का क्षेत्रफल है। और राज्य के 7.10% क्षेत्र को कवर करता है। जिले में पंडोह सहित छह शहर जनगणना शहर हैं। इनके नाम हैं मंडी, सुंदर नगर, जोगिंदर नगर, रेवाल्सर, सरकाघाट और पंडोह। हाल ही में मंडी मध्य क्षेत्र का जोनल मुख्यालय बन गया है, जो खुद बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू और मंडी जिलों को कवर करता है और जिसने प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसे बहुत अधिक महत्व दिया है।

नगर परिषद मंडी का गठन 1950 के दौरान किया गया था। इसमें 13 वार्ड हैं जिनमें 10 राजस्व हस्बैंड शामिल हैं।

मंडी हिमाचल प्रदेश के सबसे तेज़ विकसित होने वाले शहरों में से एक है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-20, 21 और 70 के क्रॉस जंक्शन पर स्थित है। यह कुल्लू, लाहौल, लेह लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। जिला मुख्यालय होने के नाते, पूरा जिला व्यापार और वाणिज्य, सेवाओं और नागरिक प्रशासन के लिए शहर पर निर्भर करता है। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है क्योंकि कुल आबादी का लगभग 79% अपनी आजीविका कमाने के लिए कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है।

बल्ह घाटी को गुणवत्ता वाले गेहूँ, धान और सब्जी की फसल के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जहाँ जल निकासी प्रणाली और सिंचाई की छिड़काव प्रणाली को अपनाया गया है। मकई मक्का, गेहूँ, चावल और सब्जियों की फसलें जिले के अन्य हिस्सों में उगाई जाती हैं, जो बड़ी आबादी की मांग को पूरा करती हैं। एच.पी. राज्य को-ऑपरेशन-मिल्क-फेडरेशन द्वारा संचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र मंडी से 8 किलोमीटर दूर चक्कर में है।

मंडी के लोग कृषि अर्थव्यवस्था का पालन करते हैं और चावल, दाल, बाजरा, चाय, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी तेल और हर्बल उत्पादों की खेती करते हैं। हिमाचल प्रदेश टाउन एंड प्लानिंग विभाग मंडी योजना क्षेत्र (एमपीए) के लिए काम करता है। मंडी जिला की निचली पहाड़ियों में रेशम उत्पादन के लिए कोकून की खेती में 9,000 से अधिक किसान सीधे तौर पर शामिल हैं। मंडी जिला को चीन से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो बाजार में बहुत कम दरों पर कच्चे रेशम का विपणन कर रहा है।

मंडी में कई हेक्टेयर भूमि पर सेब का उत्पादन किया जाता है। सेब आम तौर पर हर साल दिसंबर के दौरान लगाए जाते हैं। मंडी में फल के अंतर्गत क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में फलों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 15 प्रतिशत है। मंडी कच्ची रेशम ने व्यापक ख्याति प्राप्त कर ली है, लेकिन द्रंग और गुमा में नमक की खदानें अर्थव्यवस्था की विशेष विशेषताएं हैं। नमक और माइलस्टोन के प्रचुर डिपॉजिट के साथ, मैग्नेसाइट कोयला और क्ले चाइना के होने की संभावनाओं की जांच की जा रही है। मंडी में मछली के बाजार भी हैं जहां ब्राउन ट्राउट सबसे अधिक मांग वाली मछली प्रजातियों में से एक है। मंडी में किसान को ब्राउन ट्राउट के लिए लगभग 200रूपये/ किग्रा मिलता है।

## 5.16 रहने वाले पर्यावरण की गुणवत्ता

एक गुणात्मक जीवन के लिए ग्रामीणों को एक टिकाऊ जीवन वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जो उनकी आवश्यकताओं को सामर्थ्य, जीवन-शैली और पर्यावरण के अनुकूल होने के संदर्भ में संतुष्ट करता है। इस रिपोर्ट में इस सेक्शन का उद्देश्य स्थायी सुविधाओं और प्रथाओं की पहचान करना है जो एलएचईपी स्टेज-2 के तहत आने वाले परियोजना से प्रभावित गांवों ने अपनाया है। स्टडी के लिए मात्रात्मक ऐतिहासिक डेटा की कमी के कारण, ग्रामीणों के साथ इंटरव्यू, सामुदायिक नेताओं और ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ बैठक और परामर्श, प्रत्यक्ष निरीक्षण और दस्तावेजीकरण के आधार पर सूचना और डेटा एकत्र किए गए थे। जानकारी को ग्राम सूचना पत्र का उपयोग करके एकत्र किया गया था और एकत्रित डेटा का विश्लेषण कंटेंट एनालिसिस का उपयोग करके किया गया था। रिपोर्ट का यह सेक्शन विभिन्न विशेषताओं जैसे कि आवास पाटर, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों, पानी की आपूर्ति जैसी भौतिक अवसंरचना, सीवेज प्रणाली आदि, सार्वजनिक सेवा के बुनियादी ढांचे और गांवों में महिलाओं के लिए सामाजिक एकत्रीकरण बिंदुओं पर पहली नज़र डालता है।

### 5.9.1 आवास

चूँकि इस क्षेत्र में बर्फबारी एक प्राकृतिक घटना है, इसलिए एक कुलमिलाकर शंक्वाकार या वी आकार प्रदान करने के लिए पतले टिन और पत्थर की प्लेटों का उपयोग किया गया है जो किसी भी संचित वर्षा जल या पिघलती हुई नालियों में बदल जाता है। ऊपरी हिमाचल के इन ग्रामीण क्षेत्रों में, एक झुकी हुई छत के निर्माण के लिए विशेष रूप से चौकोर पत्थरों का उपयोग करने के लिए एक व्यापक वास्तुशिल्प प्रवृत्ति है। इस तरह के निर्माण के पीछे का उद्देश्य अर्थशास्त्र के साथ-साथ इन दूरदराज के क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में चट्टानों के टुकड़ों का उपयोग करना है।

घरों के साथ जुड़ा हुआ एक पशु आश्रय (आमतौर पर भैंस, गाय, बकरी या भेड़ के लिए) के लिए आम बात है। जैसा कि एसआईएस स्टडी टीम ने देखा है कि परियोजना के गाँवों के लगभग सभी घर अर्ध-पक्के हैं जिनमें पत्थर की प्लेटों के साथ छत है। जिला वार आवास का विवरण टेबल 5.26 में दिया गया है।

टेबल 5.26: परियोजना से प्रभावित परिवारों की आवास की संरचना					
जिला	गांव का नाम	योग	कच्चा	पक्का	सेमी-पक्का
शिमला	महावली	61	0	24	37
	बरगल	10	0	5	5
	तलाह	10	0	4	6
	चमोद	6	0	5	1
कुल्लू	डिगिधर	44	1	27	16
मंडी	कोट	9	0	5	4
	फिरनू	39	2	22	15
	नंज	38	1	28	9
<b>योग</b>		<b>217</b>	<b>4</b>	<b>120</b>	<b>93</b>
स्रोत: एसआईएस सर्वे, एलएचईपी स्टेज- II, 2019					

### 5.9.2 धार्मिक और सांस्कृतिक अभिप्राय का स्थान

एसआईएस टीम ने सभी परियोजना प्रभावित गांवों का दौरा किया और गांवों में मौजूद धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का आकलन करने का प्रयास किया। चूंकि परियोजना प्रभावित गांवों में ज्यादातर लोग हिंदू समुदाय के हैं, इसलिए सभी गांवों में मंदिर पाए गये हैं। इसके अलावा फिरनु और नानजिंग गाँव में मस्जिद पाई गयी हैं।

### 5.9.3 भौतिक अवसंरचना

एसआईएस टीम ने परियोजना प्रभावित गांवों में पानी की आपूर्ति, सीवेज सिस्टम और इलेक्ट्रिक सिस्टम जैसी विभिन्न बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता का पता लगाने की कोशिश की। इन प्रणालियों में उच्च लागत वाले निवेश होते हैं और ये गांव के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।

एसआईएस की टीम ने सभी परियोजना प्रभावित गांवों का दौरा किया और गांवों में पानी की आपूर्ति प्रणाली का निरीक्षण करने का प्रयास किया। आम तौर पर, इस पहाड़ी क्षेत्र में सभी मौसमों के लिए प्राकृतिक धाराएँ बहती हैं। लोग एक खुले गड्ढे में धारा के पानी को जमा करते हैं और गड्ढे से धारा के पानी को प्लास्टिक पाइप के माध्यम से अपने घरों में जमा करते हैं। स्थानीय भाषा में भंडारण गड्ढे को चस्मा कहा जाता है। यह देखा गया कि लोग पीने और खाना पकाने के उद्देश्यों के लिए इस धारा के पानी का उपयोग करते हैं। इसलिए लोग असुरक्षित और असुरक्षित स्रोतों से पानी का उपयोग कर रहे हैं (टेबल 5.27)।

टेबल 5.27: परियोजना प्रभावित गांवों में भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता					
जिला	गांव का नाम	सुरक्षित स्रोत का इस्तेमाल करने वाले घरों का %	विद्युतीकृत घरों का %	शौचालय का इस्तेमाल करने वाले घरों का %	गाँव में सीवेज सिस्टम की उपलब्धता
शिमला	महावली	0%	100%	100%	100%
	बरगल	0%	100%	100%	100%
	तलाह	0%	100%	100%	100%
	चमोद	0%	100%	100%	100%
कुल्लू	डिगिंधर	0%	100%	100%	100%
मंडी	कोट	0%	100%	100%	100%
	फिरनू	0%	100%	100%	100%
	नंज	0%	100%	100%	100%

स्रोत: एसआईए सर्वे, एलएचईपी स्टेज- II, 2019

#### 5.9.4 सार्वजनिक सेवा के बुनियादी ढांचे

मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक, काफी हद तक, बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के लिए इन सेवाओं के लिए बाजार की अनुपस्थिति के कारण या गरीबी के कारण राज्य पर निर्भर हैं यानि कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल देखभाल और विकास, खाद्य वितरण और बुनियादी ढांचे। उद्देश्य गरीबों और कमजोरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और मुफ्त या रियायती सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से गरीबी को कम करना है।

एसआईए सर्वे में परियोजना से प्रभावित गांवों में विभिन्न सार्वजनिक सेवा अवसंरचना की उपलब्धता को जानने का प्रयास किया गया। विवरण टेबल 5.28 में प्रस्तुत किए गए हैं

टेबल 5.28: परियोजना से प्रभावित गांवों में सार्वजनिक सेवा की बुनियादी संरचना की उपलब्धता						
जिले का नाम	गांव का नाम	गाँव में उपलब्धता (हाँ), यदि नहीं तो निकटतम दूरी				
		प्राइमरी स्कूल	सेकेंडरी स्कूल	उप केंद्र	आंगनवाड़ी	पीडीएस शॉप
शिमला	महावली	0 किमी.	3 किमी.	1 किमी.	0 किमी.	0 किमी.
	बरगल	2 किमी.	5 किमी.	1 किमी.	2 किमी.	2 किमी.
	तलाह	2 किमी.	5 किमी.	1 किमी.	2 किमी.	2 किमी.
	चमोद	0 किमी.	0 किमी.	1 किमी.	0 किमी.	0 किमी.
कुल्लू	डिगिंधर	0 किमी.	5 किमी.	1 किमी.	0 किमी.	0 किमी.
मंडी	कोट	2 किमी.	5 किमी.	1 किमी.	2 किमी.	1 किमी.
	फिरनू	2 किमी.	2 किमी.	1 किमी.	0 किमी.	0 किमी.
	नंज	1 किमी.	1 किमी.	0 किमी.	1 किमी.	0 किमी.

स्रोत: एसआईए सर्वे, एलएचईपी स्टेज- II, 2019

#### 5.9.5 महिलाओं के लिए सामाजिक धार्मिक सभा स्थान

पूरे हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले मेलों और त्योहारों के अलावा, यहां अन्य स्थानीय मेलों और त्योहारों की संख्या भी है जो परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। ये त्योहार स्थानीय महिलाओं के लिए रंगीन पोशाक और सामान को सजाने और उनके बीच घुलने मिलने का समय है। इस क्षेत्र के कुछ मेले और त्योहार देवता (शिवजी, दुर्गा), दशहरा, दिवाली, ईद के लिए मेले हैं

महिलाओं के साथ FGD के दौरान यह बताया गया कि गाँवों की महिलाएँ अपने गाँव में अलग-अलग समारोह मनाती हैं जैसे विवाह समारोह, मेहंदी समारोह आदि।

## अध्याय 6

## सामाजिक प्रभाव

### 6.1 परिचय

इंटरनेशनल एसोशिएसन फॉर इंपैक्ट असेसमेंट (आईएआईए) के अनुसार, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन में विश्लेषण की प्रक्रियाएं, आपेक्षित और अनपेक्षित सामाजिक परिणाम की निगरानी और प्रबंधन, नियोजित हस्तक्षेपों (नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं) में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों और इन हस्तक्षेपों के द्वारा उत्पन्न किसी सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया शामिल हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य अधिक टिकाऊ और न्यायसंगत जैव-भौतिकी और मानव पर्यावरण को लाना है।

एसआईए में उन सभी मुद्दों पर विचार किया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को प्रभावित करते हैं और सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए उचित हैं। संक्षेप में, सामाजिक प्रभाव बहु-क्षेत्रीय मुद्दों से संबंधित है, जैसे स्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकन, सांस्कृतिक प्रभाव मूल्यांकन, विरासत प्रभाव मूल्यांकन, सौंदर्य प्रभाव मूल्यांकन, या लिंग प्रभाव मूल्यांकन।

हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट प्रोटोकॉल (एचएसएपी) एक ऐसा टूल है जो अधिक दीर्घकालिक जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देता है और उनका मार्गदर्शन करता है। यह एक ऐसी कार्य पद्धति है जिसका उपयोग बीस से अधिक पर्यावरणीय, सामाजिक, तकनीकी और आर्थिक विषयों में जलविद्युत परियोजना के प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। सामाजिक पहलुओं के अंतर्गत कई विषयों को कवर किया जाता है, जिन्हें एक जल विद्युत परियोजना की कुलमिलाकर स्थिरता का आकलन करने के लिए समझने की आवश्यकता होती है। सामाजिक पहलुओं के अंतर्गत ये विषय संचार और परामर्श, परियोजना के लाभ, परियोजना समुदाय प्रभावित समुदाय और आजीविका, पुनर्वास, मूल निवासी, श्रम और काम करने की स्थिति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विरासत हैं।

जलविद्युत परियोजनाओं का सकारात्मक और नकारात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि एक डैम, पावर प्लांट और जलाशय के निर्माण से उस क्षेत्र में कुछ सामाजिक और भौतिक परिवर्तन होते हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। प्रोटोकॉल सरकारों, नागरिक समाज, वित्तीय संस्थानों और जलविद्युत क्षेत्र को उसके बारे में बात करने और स्थिरता के मुद्दों का मूल्यांकन करने की अनुमति देने के लिए एक आम भाषा प्रदान करता है।

### 6.2 प्रभावों की पहचान करने के लिए रूपरेखा और दृष्टिकोण

सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए दृष्टिकोण और कार्यपद्धति के बारे में इस रिपोर्ट के पिछले भाग में विस्तार से बताया गया है। हालांकि, संक्षेप में, सामाजिक प्रभावों की पहचान करने के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण यहां बताये गये हैं। एलएचईपी चरण II परियोजना के सामाजिक प्रभावों की पहचान करने के लिए उपयोग किए गये वाले टूल और तरीके हैं: a. एनालिटिकल टूल, b. परामर्श की विधियां और c. निरीक्षण और इंटरव्यू टूल्स। इन टूल्स और विधियों के तहत विभिन्न रिसर्च गतिविधियां आयोजित की गयी थी जो नीचे दी गयी हैं।

### 6.2.1 एनालिटिकल टूल

**हितधारक(स्टेकहोल्डर) विश्लेषण:** यह एसआईए और भागीदारी कार्य के लिए एक प्रवेश बिंदु है। यह रणनीतिक प्रश्नों को संबोधित करता है, उदाहरण प्रमुख हितधारक कौन हैं? परियोजना या नीति में उनके हित क्या हैं? उनके बीच पावर डिफरेंशियल्स(भिन्नताएं) क्या हैं? उनके ऑपरेशन पर क्या संबंधित रूप से प्रभाव डालते हैं? इस जानकारी ने उन संस्थानों और संबंधों की पहचान करने में मदद की, जिन्हें अगर नजरअंदाज किया जाता है, तो प्रस्तावों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है या, अगर विचार किया जाए, तो उन्हें मजबूत करने के लिए बनाया जा सकता है।

**लैंगिक विश्लेषण:** यह किसी दिए गए संदर्भ में लैंगिक भूमिकाओं, गतिविधियों, जरूरतों और अवसरों में अंतर को समझने और दस्तावेजीकरण करने पर केंद्रित है। यह पुरुषों और महिलाओं की विभिन्न भूमिकाओं और व्यवहार पर प्रकाश डालता है। ये विशेषताएँ संस्कृतियों, वर्ग, जातीयता, आमदनी, शिक्षा और समय के आधार पर भिन्न होती हैं; और इसलिए लैंगिक विश्लेषण महिलाओं को एक एक समान समूह के रूप में नहीं मानता है। लैंगिक विश्लेषण परियोजना स्थल के लिए लिंग विशेषज्ञ द्वारा किया गया था।

**सेकेंडरी डेटा (द्वितीयक आंकड़ों) की समीक्षा:** उस जानकारी का अध्ययन और समीक्षा जो पिछली बार तरह के काम के लिए किया गया है जो विशेषज्ञों और संस्थानों को पहचानने के लिए, सामाजिक आकलन के केंद्र को संकीर्ण करने का आसान तरीका है जो विकास के संदर्भ, और उपयुक्त रूपरेखा बनाने के बारे में परिचित हैं। परियोजना के लिए आवश्यक सरकारी और निजी भूमि पर भूमि रिकॉर्ड की जानकारी एचआईपीए और राजस्व विभाग से एकत्र की गई थी। इन दस्तावेजों की उचित समीक्षा की गई थी।

### 6.2.2 परामर्श की विधियां

**लाभार्थी का मूल्यांकन:** यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों और अन्य हितधारकों के सैंपल की धारणाओं की एक व्यवस्थित जांच है कि उनकी चिंताओं को सुना गया है और परियोजना और नीति निर्माण में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य व्यवस्थित लिस्टिंग करना और लाभार्थी की भागीदारी के लिए बाधाओं को उजागर करना, और हस्तक्षेप पर उनकी प्रतिक्रिया लेना है।

### 6.2.3 निरीक्षण और इंटरव्यू टूल

**भागीदार का निरीक्षण:** इस फील्ड तकनीक का उपयोग एसआईए टीम के सदस्यों के द्वारा गुणात्मक(क्वालिटेटिव) डेटा एकत्र करने और लोगों की प्रेरणाओं और दृष्टिकोणों की गहराई से समझ विकसित करने के लिए किया गया था। यह देखने, सुनने, सवाल पूछने और विस्तृत फील्ड नोट रखने पर आधारित था। निरीक्षण और विश्लेषण माध्यमिक स्रोतों की डेस्क समीक्षाओं द्वारा पूरा किये गये थे, और स्थानीय वास्तविकता के बारे में अनुमानों को प्रमुख स्थानीय जानकारी देने वालों के साथ जांचा गया है।

परियोजना के लिए अपनी जमीन खो देने वाले परिवारों के साथ अर्ध-संरचित(सेमी-स्ट्रक्चर्ड) इंटरव्यू आयोजित किए गए थे। इस सर्वे में प्रशिक्षित रिसर्च इन्वेस्टीगेटर्स के द्वारा परिवारों से जानकारी एकत्र की गई थी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें सामाजिक प्रभाव के आकलन से संबंधित मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया था, इंटरव्यू को लिखित गाइड द्वारा आंशिक रूप से संरचित(स्ट्रक्चर्ड) किया गया था। सर्वे के दौरान इन्वेस्टीगेटर

प्रतिभागियों को उन पहलुओं से परिचित कराने और उन पहलुओं चर्चा करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त रूप से संवादी बने रहे, जिन्हें वे उपयुक्त मानते हैं।

एलएचईपी स्टेज- II परियोजना क्षेत्र के सभी 8 गाँवों में सामाजिक विशेषज्ञों द्वारा फोकस ग्रुप डिस्कशन आयोजित किये गये थे। ये एफजीडी परियोजना से प्रभावित गाँवों के पुरुषों और महिलाओं के समूहों और सामाजिक और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समूहों के लोगों के साथ अलग-अलग आयोजित किए गए थे। ये एफजीडी विभिन्न प्रकार के हितधारकों से तुलनात्मक डेटा एकत्र करने के लिए तेज तरीके थे। वे आमतौर पर एक से दो घंटे थीं जिन्होंने विशेष चिंता का समाधान करने; परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं के बारे में सामुदायिक सहमति बनाने; बड़ी संख्या में लोगों के साथ जानकारी की जांच करने; या काल्पनिक या इच्छित कार्यों के लिए प्रतिक्रियाएँ प्राप्त का प्रयास किया था।

### 6.3 परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण। प्रत्यक्ष प्रभाव, अप्रत्यक्ष प्रभाव और संचयी प्रभाव

यह सेक्शन सामान्य सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का अवलोकन प्रदान करता है जिन पर एलएचईपी स्टेज- II परियोजना के निर्माण-पूर्व, निर्माण, शुरू करने और संचालन के चरणों के माध्यम से विचार किया जाना चाहिए और उन्हें हल किया जाना चाहिए।

एलएचईपी स्टेज-II परियोजना का परियोजना क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दोनों और संचयी प्रभाव हो सकता है। कुछ प्रभाव लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जबकि उनमें से कुछ का लोगों की सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस अध्ययन में एलएचईपी स्टेज- II परियोजना जिन गतिविधियों के सामाजिक प्रभावों का आकलन किया गया है वह हैं: i) स्वास्थ्य पर प्रभाव, (ii) संस्कृति और सामाजिक एकता पर प्रभाव, (iii) भूमि पर प्रभाव, (iv) आजीविका और आय पर प्रभाव, (v) भौतिक संसाधनों पर प्रभाव, (vi) निजी संपत्ति पर प्रभाव, (vii) सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव और (viii) लिंग-आधारित प्रभाव। प्रभाव के अनुसार व्यापक परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफ में हाइलाइट किए गए हैं।

#### 6.3.1 स्वास्थ्य पर प्रभाव

प्रभावित परिवारों के लोगों की सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है, जिसमें 2 व्यक्तियों हैं जो जन्म से विकलांग हैं, 3 व्यक्ति बाद में विकलांग हो गये और 1 बीमारी से पीड़ित हैं। ये विवरण टेबल 6.1 में दिए गए हैं।

टेबल 6.1- स्वास्थ्य का स्तर										
जिला	मोहाल	योग	जन्म से विकलांग	%	बाद में विकलांग हो गये	%	गंभीर बीमारी	%	कोई बीमारी नहीं	%
शिमला	महोली	228	1	0.4	2	0.9	0	0.0	225	98.7
	बरगल	38	0	0.0	0	0.0	0	0.0	38	100.0
	तलहा	28	0	0.0	0	0.0	0	0.0	28	100.0
	चमोद	24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	24	100.0
कुल्लू	दिंगीधर	203	1	0.5	0	0.0	0	0.0	202	99.5
दिंगीधर	कोट	61	0	0.0	1	1.6	0	0.0	60	98.4
	फिरनू	184	0	0.0	0	0.0	1	0.5	183	99.5

	नंज	152	0	0.0	0	0.0	0	0.0	152	100.0
<b>Total</b>		<b>918</b>	<b>2</b>	<b>0.2</b>	<b>3</b>	<b>0.3</b>	<b>1</b>	<b>0.1</b>	<b>912</b>	<b>99.3</b>
<b>स्रोत: एसआईए सर्वे, एलएचईपी- II, 2019</b>										

### 6.3.2 संस्कृति और सामाजिक एकता पर प्रभाव

इस क्षेत्र में मौजूदा सांस्कृतिक प्रणालियों के लिए कोई परिकल्पित प्रभाव नहीं है क्योंकि परियोजना के विकास के कारण जनसंख्या का कोई विस्थापन नहीं है। यह परियोजना विकास आर्थिक अवसरों के संदर्भ में विकास को लाने में सक्षम होगी जो बदले में सामाजिक एकता को बनाएगा जिसे समाज के सदस्यों को जीवित रहने और समृद्धि के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने की इच्छा के रूप में परिभाषित किया गया है। कृषि भूमि के नुकसान के कारण प्रभावित परिवारों को प्रदान की जा रही मुआवजा राशि को, जो वर्तमान में आय का स्थायी आर्थिक स्रोत प्रदान नहीं कर रही है, उसे कौशल विकास, उद्यम विकास और इन प्रभावित परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बेहतर आर्थिक अवसरों तक पहुँचने के लिए उपयोग किया जाएगा। रोजगार के अवसर भी इस परियोजना के विकास का एक सकारात्मक प्रभाव है जो क्षेत्र में कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल मजदूरों को स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

### 6.3.3 भूमि पर प्रभाव

एलएचईपी स्टेज-II परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि 174.3584 हेक्टेयर है, इसमें से कुल निजी भूमि 24.1449(13.85%) है और कुल सरकारी भूमि 150.2135 हेक्टेयर(86.15%) है। कुल निजी भूमि में 168 प्लॉट हैं। निजी भूमि के अंतर्गत आने वाले ये 168 प्लॉट 324 निजी मालिकों के हैं।

परियोजना के लिए आवश्यक भूमि 8 गांवों में आती है। टेबल 6.2 गांव और उनकी संबंधित तहसीलों और जिलों से भूमि की आवश्यकता का वर्णन करती है।

टेबल 6.2- भूमि अधिग्रहण के कारण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले निजी भूमि मालिकों की संख्या					
जिला	तहसील का नाम	गांव का नाम	जमीन के मालिकों की संख्या	प्लॉट्स की संख्या (किट्टा)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
शिमला	कुमारसैन	महोली	82	17	2.1126
		बरगल	11	09	1.5751
		तलहा	11	07	1.7075
		चमोद	04	08	2.3269
कुल्लू	अन्नी	दिगीधर	66	13	1.2284
मंडी	करगोज	कोट	12	28	0.5974
		नंज	65	48	8.0198
		फिरनू	73	38	6.5772
<b>योग</b>			<b>324</b>	<b>168</b>	<b>24.1449</b>
<b>स्रोत: एसआईए सर्वे, एलएचईपी- II, 2019</b>					

### 6.3.3.1 भूमि के बचे हुए भाग में खेती जारी रखने के लिए आर्थिक रूप से व्यावहारिकता

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि कुल 168 प्लॉट से अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि 324 निजी मालिकों की है। एसआईए के सर्वे के दौरान टीम ने जमीन खोने वाले लोगों से उसकी राय जानने के लिए मुलाकात की है कि क्या उसके प्लॉट से अधिग्रहित की भूमि के हिस्से के बाद भूमि का बचा हुआ हिस्सा खेती करने के लिए आर्थिक रूप से व्यावहारिक होगा। 333 निजी मालिकों में से 217 को संपर्क किया जा सका क्योंकि 116 जमीन के मालिक सर्वे के दौरान उपलब्ध नहीं थे।

सभी परिवारों ने बताया कि उनकी भूमि का बचा हुआ भाग खेती के लिए आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है।

### प्लॉट एक भाग के अधिग्रहण के बीच जमीन का मामूली/मुख्य प्रभाव

प्रभावित भूमि का नुकसान बनाम स्वामित्व वाली कुछ जमीन का 10% या ज्यादा होने के मामले में उत्पादकता की गतिविधियों के लिए उपलब्ध बची हुई जमीन को जीविका के लिए आर्थिक रूप से अलाभकारी माना जाता है। तो प्रभाव को गंभीर प्रभाव माना जाएगा। और यदि प्रभावित भूमि का नुकसान बनाम स्वामित्व वाली कुछ जमीन का 10% या कम होने के मामले में उत्पादकता की गतिविधियों के लिए उपलब्ध बची हुई जमीन को जीविका के लिए आर्थिक रूप से व्यवहारिक माना जाता है। तो प्रभाव को मामूली प्रभाव मानना जाएगा। यह एशियन डेवलपमेंट बैंक सेफगार्ड पॉलिसी स्टेटमेंट 2009 गाइडलाइन के अनुसार है जिसे नुकसान की सीमा का अनुमान लगाने के लिए अपनाया गया है।

भूमि के बचे हुए हिस्से पर प्रभाव का आकलन करने के लिए एसआईए टीम ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और प्रत्येक प्लॉट के नुकसान के प्रतिशत की गणना के बाद प्रभाव का आकलन करने का प्रयास किया। एलएचईपी स्टेज-II के लिए जमीन को 168 प्लॉट से अधिग्रहित किया जाना है। ये 168 प्लॉट 8 गांवों के हैं। इन सभी में से 168 प्लॉट गंभीर प्रभाव के तहत हैं। प्रत्येक प्लॉट के प्रभाव का विवरण अनुबंध 11 के रूप में संलग्न है।

### 6.3.4 आजीविका और आय पर प्रभाव

इस खंड में पीएएफ के व्यावसायिक पैटर्न और पीएएफ की घरेलू आय पर विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया गया है

एलएचईपी स्टेज-II क्षेत्र में एसआईए के सर्वे के डेटा विश्लेषण से पता चला है कि परियोजना से प्रभावित होने वाले 918 लोग 15 साल से अधिक उम्र के हैं, 477 रोजगार (52%) करते हैं और लगभग इतने ही (411) (48%) काम नहीं कर रहे हैं।

उन व्यक्तियों में से जो काम कर रहे हैं 128 व्यक्ति (27%) सरकारी और निजी नौकरियों जैसे औपचारिक क्षेत्रों में हैं, जबकि 349 (73%) अनौपचारिक क्षेत्रों में हैं। सभी 349 व्यक्ति जो अनौपचारिक क्षेत्र में हैं वे कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों से जुड़े हैं और छोटा व्यवसाय और व्यापार कर रहे हैं।

सर्वे किये गये 217 परिवारों के 15 साल से ऊपर से परिवार के सदस्यों के व्यवसायिक पैटर्न से पता चलता है कि परियोजना से प्रभावित होने वाले 918 व्यक्तियों में से 477 रोजगार में हैं और 411 काम नहीं करते हैं। 477 व्यक्तियों में से 128 व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वह औपचारिक क्षेत्र जैसे सरकारी या प्राइवेट नौकरी में हैं, जबकि

349 अनौपचारिक क्षेत्रों में हैं। सभी 349 व्यक्ति जो अनौपचारिक क्षेत्र में हैं वे कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियों से जुड़े हैं और छोटा व्यवसाय और व्यापार कर रहे हैं।

एसआईए के सर्वे से यह पाया गया कि परियोजना से प्रभावित परिवारों की औसत वार्षिक आय रु 411329/- है।

### 6.3.5 भौतिक संसाधनों पर प्रभाव

इस रिपोर्ट के पहले के खंडों में परियोजना प्रभावित 8 गांवों में पानी की आपूर्ति, सीवेज सिस्टम और इलेक्ट्रिक सिस्टम जैसे मौजूदा भौतिक बुनियादी ढांचे पर विवरण बताया गया है। एसआईए स्टडी टीम ने एसजेवीएन और राजस्व विभाग के साथ परामर्श किया ताकि यह पता चल सके कि परियोजना के हस्तक्षेप के कारण क्या कोई भौतिक बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है। यह बताया गया था कि एलएचईपी स्टेज-II के लिए आवश्यक सरकारी या निजी भूमि में कोई बुनियादी ढांचा नहीं आ रहा है। साथ ही, परियोजना का डिजाइन परियोजना के निर्माण के दौरान किसी भी भौतिक बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं करेगा।

महिलाओं के साथ सार्वजनिक परामर्श और एफजीडी के दौरान, परियोजना क्षेत्र में भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए कुछ विकास करने के लिए कई सुझाव आए हैं, जिसे रिपोर्ट के सिफारिश अध्याय में चित्रित किया गया है।

### 6.3.6 निजी संपत्तियों पर प्रभाव

एसआईए के सर्वे के अनुसार 324 पीएएफ अपनी निजी संपत्ति के रूप में अपनी जमीन और फल दे रहे पेटों को खो रहे हैं। परियोजना के विकास के कारण कोई संरचना या अन्य संपत्ति प्रभावित नहीं हुई है।

### 6.3.7 सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं पर प्रभाव

इस रिपोर्ट के पिछले खंडों में परियोजना से प्रभावित हुए गाँवों में और उसके आसपास सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता के बारे में विवरण दिया गया है। सार्वजनिक सेवाओं जैसे यानि कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चे की देखभाल और विकास और खाद्य वितरण के लिए जानकारी एकत्र की गई थी।

एसआईए के सर्वे के दौरान स्टडी टीम के सदस्यों ने समुदाय के साथ विभिन्न बैठकें कीं और यह जानने के लिए इन सार्वजनिक सेवाओं के बुनियादी ढांचे का भौतिक रूप से निरीक्षण किया कि क्या प्रस्तावित परियोजना हस्तक्षेपों के कारण इन सेवाओं में से कोई भी प्रभावित हुई है। टीम ने एसजेवीएन के साथ भी परामर्श किया और बताया गया कि एलएचईपी स्टेज- II के लिए आवश्यक किसी भी सरकारी या निजी भूमि पर कोई सार्वजनिक सेवाओं के बुनियादी ढांचे नहीं आ रहे हैं।

पीएएफ के साथ सार्वजनिक परामर्श और बैठक के दौरान परियोजना क्षेत्र में सार्वजनिक सेवाओं की उपयोगिताओं को विकसित करने और बढ़ाने के लिए कई सुझाव आए हैं, जिन्हें रिपोर्ट के सिफारिश अध्याय में वर्णित किया गया है।

### 6.3.8 लिंग आधारित प्रभाव

एसआईए टीम ने विभिन्न परियोजना चक्र के दौरान एलएचईपी स्टेज-II परियोजना के लिंग आधारित प्रभाव पर उनकी राय जानने के लिए परियोजना क्षेत्र में महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों और संस्थागत हितकारकों जैसे आईसीडीएस विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ कई परामर्श आयोजित किये।

रोड और कनेक्टिविटी- क्षेत्र की महिलाएं घरेलू काम, जलाने वाली लकड़ी का संग्रह, मवेशियों के लिए चारे के संग्रह, खेती और अन्य कृषि गतिविधियों में शामिल हैं। वे अपने गाँव की सड़क का उपयोग अपनी नियमित घरेलू गतिविधियों और आर्थिक गतिविधियों जैसे कि कृषि और विपणन(मार्केटिंग/बिक्री) आदि के लिए करती हैं। मौजूदा सड़कों का सभी मौसम में इस्तेमाल वाली सड़कों में विकास और बेहतर परिवहन सेवाओं के साथ परियोजना के तहत नई सड़कों के निर्माण से क्षेत्र की महिलाओं को लाभ होगा।

**संस्थागत प्रसव-** प्रसूति और प्रसवकालीन स्वास्थ्य दोनों के लिए उपयुक्त प्रसव देखभाल महत्वपूर्ण है। जन्म के समय कुशल सहायक सुरक्षित मातृत्व और बाल के जीवित रहने की संभावना का बढ़ाता है। यह महत्वपूर्ण है कि माताएं अपने बच्चों को एक उपयुक्त सेटिंग में जन्म देती हैं, जहां जीवन रक्षक उपकरण और स्वच्छ स्थिति भी उन जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है जिसके कारण मां और बच्चे की मृत्यु या बीमारी हो सकती है।

जैसा कि रिपोर्ट के पिछले खंडों में बताया गया है कि इन 3 जिलों में और परियोजना क्षेत्र में भी संस्थागत प्रसव का प्रतिशत बहुत खराब है। एनएफएचएस-4 के अनुसार संस्थागत प्रसव का प्रतिशत शिमला (77%), कुल्लू (71%) और मंडी (64%) है। यह देखा गया है कि चंबा के बाद जहां संस्थागत प्रसव का सबसे कम प्रतिशत है दूसरे और तीसरे सबसे कम संस्थागत प्रसव वाले जिलों में मंडी और कुल्लू हैं।

रिसर्च टीम ने इन 3 जिलों के साथ-साथ परियोजना से प्रभावित हुए गांवों में घर में होने वाले प्रसव के उच्च प्रतिशत में योगदान देने वाले कारकों को पता करने का भी प्रयास करती है। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि संस्थागत प्रसव को प्रभावित करने वाले कारक सुविधा से दूरी, परिवहन की कमी और मुश्किल इलाके हैं। परियोजना क्षेत्र की महिलाओं के अनुसार लंबी दूरी और पहाड़ी इलाके स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंचने में बाधक हैं। यहां तक कि गर्भवती महिलाओं को हास्पिटल ले जाने के दौरान प्रसव और यहां तक कि कुछ मामलों में मातृ महिला की मृत्यु की घटनाएं भी हुई हैं।

**महिलाओं की साक्षरता दर:** स्टडी में हिमाचल प्रदेश राज्य और 3 जिलों और परियोजना क्षेत्र में साक्षरता दर को लिंग और साक्षरता में लिंग अंतर का विश्लेषण करने की कोशिश की गई।

हिमाचल प्रदेश साक्षरता के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में है और यह 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 11वें स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर 82.80% है और पुरुष साक्षरता 89.53% और महिला साक्षरता 75.93% है।

जब हम जिलेवार साक्षरता दर के बारे में बताते हैं, तो जिला कुल्लू में साक्षरता का स्तर लगभग 79% है जहां 3 जिलों में सबसे कम साक्षरता प्रतिशत है। जब महिला साक्षरता की बात करते हैं तो 16.48 प्रतिशत के साथ कुल्लू जिले में लिंग अंतर राज्य के औसत के साथ-साथ शिमला और मंडी जिलों से भी खराब है। साक्षरता दर का विवरण लिंगवार टेबल 6.3 में दिया गया है।

टेबल 6.3- हिमाचल प्रदेश राज्य, 3 जिलो और परियोजना क्षेत्र में लिंग के अनुसार साक्षरता दर				
स्थान	योग	पुरुष	महिला	लैंगिक अंतर
हिमाचल प्रदेश	82.80	89.53	75.93	13.60
शिमला जिला	83.64	89.59	77.132	12.46
कुल्लू जिला	79.40	87.39	70.91	16.48
मंडी जिला	81.53	89.56	73.66	15.90

स्रोत: जनगणना 2011 और एसआईए सर्वे

एसआईए सर्वे ने खुलासा किया है कि सर्वे किए गए परिवार के सदस्यों की कुल साक्षरता दर 81.51% है। महिला साक्षरता की बात करें तो परियोजना प्रभावित क्षेत्र में लिंग अंतर 16.48 प्रतिशत है।

**श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी:** रिपोर्ट के पिछले अध्यायों में श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार से वर्णन किया गया है। एसआईए सर्वे में श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी का आकलन करने की कोशिश की गई थी। यह पाया गया कि सर्वे किए गए परिवारों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। 15-64 वर्ष की आयु में नियोजित महिलाओं के रोजगार के प्रकारों के आगे के आकलन से यह पता चला कि अधिकांश महिलाएँ कृषि और संबंधित सेवाओं से जुड़ी हुई हैं।

## अध्याय 7 अधिग्रहण पर लागत और लाभ और गणों का विश्लेषण

### 7.1 परिचय

सामाजिक प्रभाव आकलन एचपी आरटीएफसीटीएलएआरआर (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम 2015 के नियम 3 के अनुसार एलएचईपी स्टेज -2 के अंतर्गत निजी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए तैयार किया गया है।

इस अध्याय में, विभिन्न जनसभाओं जैसे सार्वजनिक परामर्श, पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन और घरेलू सर्वेक्षण में अभिव्यक्त किए गए भूमि खोने वाले लोगों के विचारों सहित विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन दल ने विभिन्न संस्थागत स्तरों के साथ परामर्शों की श्रृंखला भी की है यानी आईसीडीसी विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग आदि। यह अध्याय सीधे प्रभावित हुए भूस्वामियों, प्रभावित गाँवों और आस-पास के क्षेत्र के लिए प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना के संभावित लाभों को भी कैप्चर करता है। प्रस्तावित एलएचईपी स्टेज- II के कथित प्रभावों के आधार पर, एसआईए टीम ने, आरएफसीटीएलएआरआर 2013, एचपी आरएफसीटीएलएआरआर (एसआईए एंड कं) नियम 2015 और हिमाचल प्रदेश के स्थानीय नियम और नीतियां पर विचार के अनुसार सुझाव प्रदान किया है।

### 7.2 अंतिम निष्कर्ष

#### 7.2.1 सार्वजनिक उद्देश्य का आकलन

हिमाचल प्रदेश अपनी पांच बड़ी नदियों और उनकी सहायक नदियों में विशाल जल-विद्युत क्षमता के साथ समृद्ध है जिसकी खड़ी ढाल जल-विद्युत क्षमता के अनुकूल उपयोग के लिए योजना बनाने वालों और इंजीनियरों को निरंतर चुनौती देती रहती है। राज्य, केंद्रीय, राज्य, ज्वाइंट और निजी क्षेत्र के डिवलपर्स द्वारा कई पनबिजली परियोजनाएं चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में पनबिजली ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के लिए केवल एक ही रणनीति है, कि जितना संभव हो उतनी ऊर्जा का उत्पादन करना, न्यूनतम लागत के साथ और न्यूनतम पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभावों के साथ जितना तेज संभव हो उत्पादन करना है।

सभी नए प्रतिष्ठानों पर 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 1% स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) राज्य के संसाधनों को एक महत्वपूर्ण सीमा तक बढ़ायेगा। परियोजना की आवश्यकता अधिकतम बिजली की मांग में लगातार वृद्धि और उत्तरी क्षेत्र में बढ़ते ऊर्जा घाटे को पूरा करने की आवश्यकता से उत्पन्न होती है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्माण और संचालन के लिए एसजेवीएन को एलएचईपी स्टेज- II (172 मेगावाट) आवंटित किया है। आवश्यक निकाय एचपी की पीएसयू सरकार है। पीएसयू आवश्यक निकाय होते हुए, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 2 के अंतर्गत आता है।

वर्तमान में एलएचईपी स्टेज- II को इस कार्यक्रम के अंतर्गत माना जाता है जिसे नदी पर चलने वाली योजनाओं के रूप में डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण नंज गाँव के पास सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश के शिमला,

कुल्लू और मंडी जिलों में विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना से 90% विश्वसनीय वर्ष में 632 MU बिजली उत्पन्न होना अनुमानित है। एलएचईपी स्टेज- II (172 मेगावाट) सतलुज नदी की जल क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रस्तावित एक नदी पर चलने जैसा विकास है।

निर्माण के पूर्व चरण के दौरान, निर्माण के दौरान और परियोजना शुरू होने के बाद, कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए रोजगार पैदा होगा। एचपी सरकार के नियम के अनुसार, औद्योगिक रोजगार का 70% हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए आरक्षित होना चाहिए। इस मामले में, परियोजना प्रभावित गांवों के पीएफ को परियोजना स्तर पर पैदा हुए रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

### 7.2.2 भूमि के कम स्थानंतरण और न्यूनतम आवश्यकता के लिए वैकल्पिक

विभिन्न भू-तकनीकी पहलुओं, स्थान, क्षमता और प्रकृति के साथ वैकल्पिक प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद, 172 मेगावाट की क्षमता के साथ वर्तमान प्रस्ताव और 90% विश्वसनीय वर्ष में 632 MU बिजली उत्पन्न करने का अनुमान, एलएचईपी स्टेज- II में नानजिंग गाँव के पास सतलुज नदी के सबसे गहरे नींव स्तर और बाँये तट पर भूमिगत बिजली घर के ऊपर + 71 मीटर ऊँचे कंक्रीट के बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। *वर्तमान परियोजना के डिजाइन को भूमि अधिग्रहण की न्यूनतम आवश्यकता और सबसे साध्य इंजीनियरिंग डिजाइन के महत्वपूर्ण विचार के बाद चुना गया था।* एलएचईपी स्टेज- II के लिए कुल आवश्यक भूमि 174.3584 हेक्टेयर होने का अनुमान है, जिसमें निजी भूमि मालिकों से केवल 24.1449 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यह कुल भूमि की आवश्यकता का केवल 13.85% है। भूमि खोने वालों की संख्या 324 होगी जो 8 गांवों, 3 तहसीलों और 3 जिलों से हैं। इसलिए निजी भूमि के अधिग्रहण को कम करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं और परियोजना गतिविधियों के कारण कोई स्थानंतरण नहीं होगा।

### 7.2.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता

एसआईए के सर्वेक्षण से पता चलता है कि भूमि के नुकसान के साथ-साथ कुछ पेड़ों का नुकसान भी होगा। किसी भी आवासीय या व्यवसायिक संरचनाओं का कोई नुकसान नहीं होगा। भूमि खोने के कारण संबंधित पीएफ प्रभावित होगा जिसके परिणामस्वरूप फसल उत्पादन में कमी होगी। चूंकि कोई स्थानंतरण नहीं है, इसलिए परियोजना प्रभावित गांवों में सामाजिक-सांस्कृतिक पर कम से कम प्रभाव पड़ेगा।

भूस्वामियों को कुछ नकारात्मक प्रभावों की उम्मीद थी जिनमें भूमि का खोना शामिल है। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि परियोजना निर्माण अवधि के दौरान बाहरी आबादी की आगम हो सकती है और रक्षा-सुरक्षा के मुद्दों और सामाजिक संघर्ष आदि में वृद्धि परिणाम हो सकता है। वे यह भी उम्मीद करते हैं कि राज्यों के बाहर से मजदूरों के आने के कारण, परियोजना के आस-पास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।

किसी भी सामान्य संपत्ति संसाधनों की कोई हानि नहीं होगी जैसे कि चराई की भूमि, पुलों, दाह संस्कार के स्थान, खेल के मैदान, स्कूल, पूजा स्थल आदि। इसलिए बदले में प्रभावित गांवों के निवासियों के सामान्य जीवन को प्रभावित नहीं करेगा।

यह परियोजना राज्य के बाहर से एक बड़ी प्रवासी आबादी लाएगी, जो मौजूदा बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक उपयोगिताओं पर दबाव डालेगा। सामाजिक संघर्ष और स्थानीय आबादी की रक्षा और सुरक्षा के लिए खतरे बढ़ सकते हैं। समुदाय के लोगों ने आशंका जताई है कि बाहर से मजदूरों के आने के कारण परियोजना वाले गांवों में और उसके आसपास एचआईवी के मामले फैल सकते हैं।

नकद मुआवजे के प्रवाह से अचानक प्रभावित परिवारों के व्यय पैटर्न और वित्तीय निर्णयों में बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर ध्यान न दिया गया, तो युवा पीढ़ी शराब/मादक वस्तुओं, आलीशान वस्तुओं पर गैर-जिम्मेदार खर्च के प्रभाव में आ सकते हैं और गैर-जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन हो सकता है। हालांकि, सार्वजनिक परामर्श के दौरान ज्यादातर पीएफ ने यह व्यक्त किया कि वे अपने पैतृक गांव के पास के स्थानों में कृषि भूमि खरीदकर मुआवजे की राशि का उपयोग करेंगे।

#### 7.2.4 गंभीरता को कम करने वाले सुझाव

अधिनियम 2013, के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन अधिनियम और हिमाचल प्रदेश नियम, 2015 के नियम 3 के उप नियम (4) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के धारा 4 (6) के प्रावधानों के अनुसार, गंभीरता को कम करने वाली परियोजना के प्रभाव को संबोधित करने के लिए किए जाने वाले आवश्यक सुधारात्मक उपायों को सूचीबद्ध करती है। विस्तृत अध्ययन के बाद, हिस्सेदारों द्वारा परामर्श और चिंताओं को आगे रखा गया, रिपोर्ट में गंभीरता को कम करने वाले निम्नलिखित का सुझाव दिया गया है।

##### 7.2.4.1 सामुदायिक विकास कार्य

एलएचईपी स्टेज- II परियोजना प्रभावित गांवों के लिए निम्नलिखित सामुदायिक विकास कार्यों की सिफारिश की जाती है अनुसूची 3 अनुबंध 12 में संलग्न है। इन सबके बीच आंतरिक और संपर्क मार्ग, सुरक्षित पीने के पानी का स्रोत प्रदान करना, जल निकासी और स्वच्छता सुविधाएं और पशुओं के लिए चराई की भूमि आदि शामिल होंगे।

##### 7.2.4.2 कमजोर और सामाजिक रूप से पिछड़े परिवार

महिला प्रधान परिवारों के लिए, शारीरिक / मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध लोगों की समय-समय पर निगरानी करनी चाहिए और उन्हें आर्थिक उत्थान और जीवन की खुशहाली के लिए उचित योजनाओं से जोड़ना चाहिए।

19 एसटी प्रभावित परिवार और 90 एससी परिवार हैं, अधिनियम 2013 में विशेष प्रावधान जो इन परिवारों के लिए बजट अनुमान का हिस्सा माना जाता है।

##### 7.2.4.3 पीएफ के लिए मुफ्त बिजली

उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकार के अनुसार, 10 वर्षों तक प्रभावित परिवारों के लिए परियोजना शुरू करने के बाद नीति 100 यूनिट मुफ्त बिजली परियोजना द्वारा प्रदान की जानी है।

#### 7.2.4.4. स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ)

जलविद्युत परियोजनाओं के विकास दौरान, पर्यावरण, मौजूदा बुनियादी ढांचे, व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधनों, आदि पर प्रभाव पड़ता है। इन प्रतिकूल परिणामों की गंभीरता कम करने का प्रावधान को योजनाओं जैसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी), कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान (कैट प्लान), क्षतिपूर्क वनीकरण के माध्यम से पर्यावरण के नुकसान भरपाई, कुल मौजूदा कीमत का भुगतान, पुनर्वास और पुनःस्थापन योजनाएं और प्रदूषण के कारण फसलों को नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति, आदि के लिए प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, स्थानीय विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए राज्य जल विद्युत नीति के तहत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) का एक विशेष प्रावधान किया गया है, ताकि परियोजना की लागत के हिस्से के रूप में परियोजना क्षेत्र में स्थानीय समुदायों के लिए दिखने वाला अतिरिक्त लाभ के रूप में सुनिश्चित किया जा सके।

एमपीपी एंड पावर विभाग, एचपी सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित एलएडीएफ दिशानिर्देशों के अनुसार (प्रतिलिपि अनुबंध 13 के रूप में संलग्न है ...) 5MW से ऊपर की परियोजना की अंतिम लागत का 1.5% एलएडीएफ को योगदान दिया जाएगा। यहां यह ध्यान दिया जाता है कि एलएचईपी स्टेज- II की क्षमता 271 मेगावाट है।

जलविद्युत परियोजनाओं के चालू होने के बाद अतिरिक्त 1% (एक प्रतिशत) निः शुल्क बिजली एलएडीएफ के लिए आय उत्पत्ति और जनकल्याण योजनाओं, अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं आदि के निर्माण के लिए जीवन भर परियोजना के आधार पर लगातार और निरंतर राजस्व का एक नियमित स्रोत प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा।

परियोजना के डिजाइन और लागत में उचित और पर्याप्त प्रावधान करके इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

फसल के नुकसान का मुआवजा: आवश्यक बाँडी न केवल प्रभावित भूस्वामियों की भरपाई के लिए प्रतिबंधित होगी, बल्कि निर्माण चरण के दौरान, अगर निर्माण गतिविधियों के कारण फसलों के किसी भी नुकसान का पता लगेगा, तो प्रभावित किसानों को एचपी सरकार की फसल नीति के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

### 7.3 मूल्यांकन मानदंड और काल-चक्र

एसएमपी के एक उद्देश्य कार्यान्वित का संचालन करने के लिए और प्रतिकूल मुद्दों को आवधिक मूल्यांकन को न्यूनतम करने (शुरु में तिमाही होगा, और उसके बाद सत्र के बीच में और अंतिम अवधि के मूल्यांकन) बाहरी एम एंड ई एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस मूल्यांकन में एसएमपी के कार्यान्वित होने के बीच के अंतराल की पहचान करना शामिल होगा और और एसएमपी में गंभीरता को कम करने वाले उपाय प्रस्तावित होंगे। इस प्रकार पहचाने गए किसी भी अंतराल पर चर्चा की जाएगी और सुधारात्मक कार्यों को समय पर कार्यान्वयन के लिए डिजाइन किया जाएगा। मूल्यांकन मानदंड में निम्नलिखित मुद्दों की जांच शामिल होगी:

#### 7.3.1 आउटपुट

प्रभावित परिवारों की संख्या और संख्या के खिलाफ वास्तव में क्षतिपूर्ति या सहायता प्राप्त लोगों की संख्या। यदि कोई भी कृषि भूमि आंशिक रूप से प्रभावित होती है (इसके मौजूदा भू-भाग का 10%) तो उपलब्ध बची हुई भूमि परिवार के लिए खुद का पालन पोषण करने के लिए आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगी। कार्यान्वयन के दौरान उचित प्रक्रिया को अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए कैसे समाधान किया गया था इसका परीक्षण करना जरूरी है। नुकसान के बदले में वैकल्पिक जमीन की पहचान के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गयी थी, या क्या परिवार को कृषि गतिविधियों के लिए एक दूसरे प्लॉट खरीदने में सक्षम बनाने के लिए उचित मुआवजा प्रदान किया गया था, स्थानांतरण के दौरान कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की गयी थी, स्थानांतरण में सहयोग के लिए भुगतान,

पारगमन सहयोग आदि। यदि निर्धारित किये गये के अनुसार गतिविधियों को करने में कोई चूक हुई है, तो मामले दर मामले के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई प्रदान की जाएगी। इससे समुदाय की समस्याओं और मुद्दों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में कार्यान्वयन एजेंसी के प्रति समुदाय का विश्वास भी बढ़ेगा।

परिवार की किसी अन्य श्रेणियों या व्यक्ति के साथ इस तरह का परीक्षण किया जाएगा और उसके अनुसार गंभीरता को करने करने के उपाय लागू किये गये थे।

### 7.3.2 परिणाम

मूल्यांकन में उन व्यक्तियों या परिवारों के आय स्तर के संबंध में जीवन की गुणवत्ता की जांच की जाएगी जो जमीन या अन्य संपत्ति के नुकसान के कारण आजीविका या आर्थिक अवसरों तक पहुंच खो रहे हैं। परियोजना शुरू होने की अवधि और परियोजना के कार्यान्वयन के बाद के स्तर पर आमदनी के स्तर का सीधा मुआवजा होगा। यदि कोई ऐसे परिवार हैं जो परियोजना के विकास के कारण गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, आजीविका खो चुके हैं, आदि तो सके समाधान के लिए उपाय का सुझाव दिया जाएगा।

एसएमपी के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के मुद्दों की समय पर जांच और मूल्यांकन किया जाएगा।

उपरोक्त सभी गतिविधियों के अलावा, एसजेवीएन को योजना बनाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि जमीन पर सिविल कार्यों के कार्यान्वयन या पहल पर किसी भी मुद्दे को आगे बढ़ाने से पहले भूमि अधिग्रहण को पूरा करने के लिए सभी आवश्यकता अधिसूचनाओं को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्यान्वयन के लिए कॉन्ट्रैक्टर को निर्धारित करने के बाद किसी भी देरी या निर्णय से परियोजना की लागत और कुलमिलाकर बजटीय आवंटन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में श्रेयलिंग पर उचित रूप से काम करना होगा और अनुमान लगाना होगा।

गंभीरता को कम करने वाली योजना को लागू करने के लिए बजट अनुमान

एसआईएमपी के कार्यान्वयन के लिए बजट में भूमि अधिग्रहण, भूमि से जुड़ी संपत्ति, और पुनर्वास और पुनर्स्थापन लागत आरटीएफसीटीएलएआरआरए, 2013 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के अनुसार लागत शामिल है। इस बजट में एसजेवीएन के द्वारा एसआईएमपी के कार्यान्वयन की आंतरिक निगरानी की लागत भी शामिल है। इसके अलावा यह एनजीओ के लिए बजट भी प्रदान करता है जो वास्तविक कार्यान्वयन के समय सामाजिक प्रभाव और भूमि अधिग्रहण डेटा को अपडेट करने के लिए जिम्मेदार होगा।

हमने परियोजना के तहत निगरानी और मूल्यांकन के तीसरे पक्ष के बाहरी एजेंसी के मूल्यांकन पहलू की लागत पर भी विचार किया है।

एनजीओ और निगरानी और मूल्यांकन एजेंसी के लिए लागत आईएफसी मानकों की जरूरतों के अनुसार है। यह लागत बिल ऑफ कोटेशन (बीओक्यू) के हिस्से के रूप में शामिल किए जाने वाली कुलमिलाकर परियोजना कार्यान्वयन की लागत का हिस्सा है, जिस पर परियोजना के ब्याज की दर की गणना करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

बजट रुपये 31,42,08,239/-, यानी इकतीस करोड़ बयालीस लाख आठ हजार दो सौ और उनतीस रुपये है। सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) के कार्यान्वयन के लिए बजट का विवरण रिपोर्ट के एसआईएमपी खंड में प्रदान किया गया है।

## 7.4 अंतिम सिफारिशें

कुलमिलाकर प्रभावित परिवारों, पंचायतों और समुदाय की उपरोक्त राय और मांगों के आधार पर, परियोजना के विभिन्न पहलुओं और राज्य सरकार की भागीदारी पर विचार करते हुए, परियोजना के सकारात्मक और साथ ही नकारात्मक पक्ष भी हैं। समुदाय में भय और आशंका दिखाई देती है जबकि एलएचईपी स्टेज-II के कारण क्षेत्र के विकास की भी उम्मीद है।

जमीन के मालिकों को नकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है जिसमें भूमि की हानि, बाहरी आबादी की आमद और रक्षा-सुरक्षा के मुद्दों में कमी, सामाजिक संघर्ष में वृद्धि आदि शामिल हैं। वे यह भी उम्मीद करते हैं कि राज्यों के बाहर से मजदूरों के आने के कारण परियोजना के करीबी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। समुदाय के लोग यह भी आशंका जताते हैं कि बाहरी मजदूरों की वजह से परियोजना के गाँवों में और आसपास एचआईवी के मामले फैल सकते हैं। एलएचईपी स्टेज-II के लिए परियोजना गतिविधियों के कारण किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जा रहा है।

स्टडी के दौरान संपर्क किये गये जमीन के मालिकों के अनुसार, प्रभावित क्षेत्र में लोग रोजगार के अवसरों, जमीन की कीमत, और छोटे और मध्यम व्यापार उद्यम की संभावना के लिए के लिए गुंजाइश के बारे में आशान्वित हैं। वे बेहतर रोड नेटवर्क, उच्च आवृत्ति और बेहतर गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाओं की भी उम्मीद कर रहे हैं। ढांचागत सुविधाओं में सुधार किया जाएगा जो रोजगार सृजन के लिहाज से फायदेमंद होगा।

एसआईए और सार्वजनिक परामर्श और संस्थागत परामर्श के दौरान एकत्र की गई जानकारी के विश्लेषण से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परियोजना के फायदों को परियोजना से प्रभावित हुए गाँवों, ब्लॉक, जिला और राज्य के स्तर पर विस्तारित किया जाएगा। गंभीरता को कम करने वाली योजना सामाजिक प्रभावों को हल करेगी और परियोजना प्राधिकरणों और राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली विकास गतिविधियों से प्रतिकूल सामाजिक लागतों को ढांका जाएगा।

उपरोक्त को देखते हुए, यह खंड भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर सिफारिशों पर चर्चा करता है।

- I. भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास से बचा गया है क्योंकि प्रस्तावित विकल्पों में से चुनी गयी परियोजना के डिजाइन का परियोजना क्षेत्र में पीएएफ और समुदायों पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- II. जहां हाउसहोल्ड्स(परिवार) (समुदाय सहित) संपत्ति, जीविका या संसाधन खो रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से मुआवजा और सहायता दी जाएगी ताकि वे अपनी पहले की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार कर सकें, या कम से कम उसे बहाल कर सकें।
- III. मुआवजा और पुनर्वास सहायता पीएएफ को प्रदान की जाएगी, मतलब कोई व्यक्ति या हाउसहोल्ड या बिजनेस जो प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयन के कारण उसका/उसकी/ उसके पास होगा
  - a) बुरी तरह प्रभावित जीवन स्तर
  - b) किसी घर का अधिकार, टाइटल या हित, उसका हित, या इस्तेमाल करने का अधिकार, कोई कृषि भूमि जिसमें परिसर, कृषि और चराई की भूमि, व्यवसायिक संपत्ति, किरायेदारी, या वार्षिक या बारहमासी फसलों और पेड़ों में अधिकार या कोई निश्चित या गतिशील संपत्ति, अधिग्रहित या या सम्मिलित भूमि शामिल है।

- c) आय अर्जित करने के अवसर, **बिजनेस**, व्यवसाय, कार्य या निवास स्थान या आवास पर अस्थायी या स्थायी रूप से प्रतिकूल प्रभाव; या,
- d) सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों और प्रभावित हुए रिश्ते या कोई अन्य नुकसान जिन्हें पुनर्वास योजना की प्रक्रिया के दौरान पहचाना जा सकता है।

## सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

### 1.1 गंभीरता को कम करने के लिए दृष्टिकोण

2013 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अनुभाग 4 (6) के प्रावधान और हिमाचल प्रदेश नियम, 2015 के नियम 3 के उप नियम (4) गंभीरता को कम करने के उपाय के सुझाव प्रदान करता है जो परियोजना के विकास के कारण परिकल्पित प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों समाधान करने के लिए अपनाया जा सकता है। हालांकि उपर बताएं गई नीतियों में विस्तार से बताया गया है, इन गंभीरता कम करने वाले उपायों को लागू करने के लिए अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण रिपोर्ट के इस भाग में विस्तार से है।

प्रभावित परिवारों ने परामर्शों की श्रृंखला के दौरान और सामाजिक प्रभाव आकलन स्टेज के दौरान हो रही चर्चा के दौरान सूचित किया है कि परियोजना के कार्यावित के हिस्से के रूप में सामुदायिक स्तर के लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि इन प्रावधानों, जो प्रदान किये गये थे, वो कुछ गांवों के लिए विशिष्ट थे परन्तु इसे परियोजना प्रभाव क्षेत्र में अन्य जगहों के लिए भी माना जा सकता है।

दृष्टिकोण प्रभावित परिवारों द्वारा उपलब्ध कराए गए विकल्पों को प्राथमिकता देने के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ एक ग्राम सभा आयोजित करना होगा। प्राथमिकता बनाने के बाद इन गतिविधियों को कार्यान्वयन एजेंसी (इस मामले में एसजेवीएन) के साथ अंतिम रूप दिया जा सकता है और तदनुसार कार्यान्वित की जा सकती है। इन कार्यों के लिए आवश्यक भूमि की पहचान इस ग्राम सभा सत्रों के दौरान भी की जाएगी। कुछ जानकारी जन सुनवाई के दौरान एकत्र की जा सकती है जिसमें परियोजनाओं को प्राथमिकता के लिए और पुख्ता किया जा सकता है।

ऊपर बताई गई परियोजनाओं के अनुसार नीचे चर्चा की गई है।

#### 1.1.1 सामुदायिक विकास कार्य

एलएचईपी स्टेज- II परियोजना प्रभावित गांवों के लिए सामुदायिक विकास कार्यों की सिफारिश की जाती है अनुसूची 3 अनुबंध 12 में संलग्न है। इन सबके बीच आंतरिक और संपर्क मार्ग, संरक्षित पीने के पानी का स्रोत प्रदान करना, जल निकासी और स्वच्छता सुविधाएं और पशुओं के लिए चराई की भूमि आदि शामिल होंगे।

#### 1.1.2 पीने के पानी के लिए सुरक्षित स्रोत के प्रावधान

परामर्श के दौरान, अधिकतर गांवों एक प्रमुख मसला उठाया गया था कि पीने और खाना पकाने के लिए पानी के उपयोग के लिए संरक्षित स्रोत की आवश्यकता है। चूंकि कोई संरक्षित स्रोत नहीं है, लोग अपने पीने के पानी और घरेलू उपयोग के लिए खुली नदी और नाले जैसे असुरक्षित स्रोतों से पानी का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं। एसआईए सर्वे के दौरान, अध्ययन टीम ने पाया है कि परियोजना प्रभावित गांवों में 100% परिवार असुरक्षित स्रोतों से असुरक्षित पानी का उपयोग करते हैं। गर्मियों के दौरान पानी की कमी होती है, जिससे लोगों को घरेलू उपयोग, खाना पकाने और पीने के उद्देश्यों दोनों के लिए निकट के शहर से पानी खरीदना पड़ता है। लोगों ने परियोजना प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि पानी के पंप के प्रावधान और सामान्य नल की स्थापना के साथ ओवरहेड टैंक का निर्माण किया जाए, तब ग्रामीणों के लिए वहां से सुरक्षित पानी लाना फायदेमंद होगा। चूंकि सतलुज नदी का पानी साफ नहीं है, इसलिए पीने के लिए सहायक नदियों/नालों के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है।

### 1.1.3 गांवों में स्ट्रीट लाइट का प्रावधान

कई गांवों में यह एक आम मांग थी कि उन्हें अपने गांवों के अंदर स्ट्रीट लाइट पोस्ट की जरूरत है। गाँव के अंदर की संकरी सड़कों पर रात के समय चलना भी बहुत मुश्किल और खतरनाक है। लोगों ने परियोजना प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि महौली (शिमला जिला) और बेहना, डिंगिधर मोहाल (कुल्लू जिला) के परियोजना गांवों में कम से कम 3 से 4 स्ट्रीट लाइट पोस्ट प्रदान करना चाहिए।

### 1.1.4 मंदिर धर्मशाला का पुनर्निर्माण (विश्राम गृह)

कुल्लू जिले के बेहना डिंगिधर मोहाल में, एक प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ भगवान बेहना महादेव की पूजा की जाती है। न केवल परियोजना स्थल के आस-पास के गाँव के लोग बल्कि 25 किलोमीटर से अधिक दूर के लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। गाँव के लोगों के अनुसार यह मंदिर 100 साल से अधिक पुराना है। हर साल यहां एक बड़ा मेला (स्थानीय त्योहार) आयोजित किया जाता है, जिसमें सैकड़ों से अधिक श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के परिसर के अंदर एक धर्मशाला थी। शादी और अन्य समारोहों के दौरान लोग इस धर्मशाला का उपयोग करते हैं। ज्यादातर महिला श्रद्धालु दूर-दराज से आती हैं और यहीं विश्राम करती हैं। अब धर्मशाला जर-जर स्थिति में है और यह वर्तमान में उपयोग में नहीं है। गाँव के लोगों ने परियोजना प्राधिकरण से इस धर्मशाला के पुनर्निर्माण का अनुरोध किया।

### 1.1.5 युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौशल प्रशिक्षण

सार्वजनिक परामर्श के दौरान पाया गया कि बहुत से युवा जो कि शिक्षित हैं, यहां तक कि स्नातक पूरा करके बेरोजगार बैठे हैं। कौशल की कमी शायद एक सबसे बड़ी समस्या है जो युवाओं का सामना कर रहे हैं जो बेरोजगार कई स्नातकों की ओर जाता है, जिसका युवा सामना कर रहे हैं जिसके कारण कई स्नातक युवा बेरोजगार हो गये हैं। ग्रामीणों के अनुसार डिग्री के साथ कॉलेजों से पास करने वाले कई स्नातकों को उचित कौशल की कमी के कारण बेरोजगार कहा गया। लोगों की मांग है कि परियोजना प्राधिकरण को उनके गांवों के शिक्षित छात्रों के लिए वित्त और आईटीआई या अन्य कौशल आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।

### 1.1.6 कमजोर और सामाजिक रूप से पिछड़े परिवार

महिला प्रधान परिवारों के लिए, शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध लोगों की समय-समय पर निगरानी करनी चाहिए और उन्हें आर्थिक उत्थान और जीवन की खुशहाली के लिए उचित योजनाओं से जोड़ना चाहिए।

यहां कोई एसटी परियोजना प्रभावित परिवार नहीं है। लेकिन एससी परिवारों के लिए, अधिनियम 2013 में दिए गए विशेष प्रावधान को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

### 1.1.7 पीएएफ के लिए मुफ्त बिजली

उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकार के अनुसार, 10 वर्षों तक प्रभावित परिवारों के लिए परियोजना शुरू करने के बाद नीति 100 यूनिट मुफ्त बिजली परियोजना द्वारा प्रदान की जानी है।

### 1.1.8 स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ)

जलविद्युत परियोजनाओं के विकास दौरान, पर्यावरण, मौजूदा बुनियादी ढांचे, व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधनों, आदि पर प्रभाव पड़ता है। इन प्रतिकूल परिणामों की गंभीरता कम करने का प्रावधान को योजनाओं जैसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी), कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान (कैट प्लान), क्षतिपूर्क वनीकरण के माध्यम से पर्यावरण के नुकसान भरपाई, कुल मौजूदा कीमत का भुगतान, पुनर्वास और पुनःस्थापन योजनाएं और प्रदूषण के कारण फसलों को नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति, आदि के लिए प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, स्थानीय विकास

गतिविधियों को पूरा करने के लिए राज्य जल विद्युत नीति के तहत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) का एक विशेष प्रावधान किया गया है, ताकि परियोजना की लागत के हिस्से के रूप में परियोजना क्षेत्र में स्थानीय समुदायों के लिए दिखने वाला अतिरिक्त लाभ के रूप में सुनिश्चित किया जा सके।

एमपीपी एंड पावर विभाग, एचपी सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित एलएडीएफ दिशानिर्देशों के अनुसार (प्रतिलिपि अनुबंध के रूप में संलग्न है 13) 5MW से ऊपर की परियोजना की अंतिम लागत का 1.5% एलएडीएफ को योगदान दिया जाएगा। यहां यह ध्यान दिया जाता है कि एलएचईपी स्टेज- II की क्षमता 172 मेगावाट है। जल विद्युत परियोजना के शुरू होने के बाद परियोजना के जीवन भर सतत और निरंतर आधार पर आमदनी उत्पन्न करने और कल्याणकारी योजना, अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और समान्य सुविधा के लिए आमदनी का एक नियमित साधन प्रदान करने के लिए एलएडीएफ के लिए अतिरिक्त 1% (एक प्रतिशत मुफ्त बिजली निर्धारित की जाएगी)।

परियोजना के डिजाइन और लागत में उचित और पर्याप्त प्रावधान करके इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए फसल के नुकसान के लिए मुआवजा: आवश्यक निकाय न केवल प्रभावित भूस्वामियों को मुआवजा देने के लिए प्रतिबंधित होंगे, बल्कि निर्माण चरण के दौरान, अगर निर्माण गतिविधियों के कारण फसलों को किसी भी नुकसान का पता चलेगा, तो प्रभावित किसानों को हिमाचल सरकार की फसल नीति के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

## 2.0 प्रभाव से बचने, उसे कम करने और क्षतिपूर्ति करने के लिए उपाय

परियोजना ने प्रभावों से बचने और न्यूनतम निजी भूमि अधिग्रहण के भूमि अधिग्रहण तक सीमित करने के सभी विकल्पों पर विचार किया है। एलएचईपी II के लिए परियोजना के विकास के लिए आवश्यक कुल भूमि क्षेत्र इस निजी भूमि का 174.3584 हेक्टेयर है जो 24.1449 हेक्टेयर है जो कुल भूमि अधिग्रहण का लगभग 13.85% है। इसलिए जरूरी जमीन का बड़ा हिस्सा सरकार का है।

जिन निजी भूमि से जिसका अधिग्रहण किया जा रहा है, वहां से कोई भी संरचना प्रभावित नहीं हो रही है, अधिग्रहित की जाने वाली पूरी भूमि कृषि भूमि है, जो ज्यादातर वर्षा आधारित भूमि है। इस प्रकार, निजी भूमि का अधिग्रहण सीमित हो गया है और परियोजना विकास के लिए किसी भी बहु-फसली भूमि ड्र को प्रभावित नहीं करने के लिए भी माना गया है।

सभी प्रभाव जिसकी पहचान की गई है, जो कृषि भूमि है, जिसकी हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व विभाग के अनुसार सर्कल दरों के आधार पर भरपाई की जा रही है। कौशल विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के संदर्भ में आय पुनर्स्थापना कार्यक्रम को एसआईए रिपोर्ट और इस एसआईएमपी के भाग के रूप में सुझाया गया है।

## 3.0 उपाय जो अधिनियम में बताए गये पुनर्वास और मुआवजे की शर्तों में शामिल हैं

एलएचईपी फेज II के अंतर्गत आय पुनर्स्थापना कार्यक्रम, जो प्रकार के रूप में सहयोग है, उसे पीएपी की आजीविका गतिविधियों और आय स्रोत को बहाल करने और स्थिर करने के लिए प्रदान किया गया है।

आईआरपी पीएपी के लिए कम अवधि में अर्जित आय उत्पन्न करने के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है जो परियोजना के विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण के बाद पीएपी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। यह आमदनी वाली गतिविधि के लिए आवश्यक तकनीकों में पीएपी के क्षमता विकास के लिए सहयोग करता है और स्थिर आमदनी या आय के स्रोतों को प्राप्त करने के लिए पीएपी को सशक्त बनाता है।

एसआईएमपी के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए एनजीओ को काम पर रखा जाएगा और वह प्रभावित गाँवों के लोगों की आवश्यकताओं का आकलन करेगा और फिर उनकी योग्यता के आधार पर परिवार के सदस्यों के कौशल की पहचान करेगा जिसे सामाजिक प्रभाव आकलन सर्वे के दौरान पहले से ही कैप्चर किया गया है। एक

उपयुक्त स्थानीय आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए, एनजीओ निम्नलिखित अभ्यास करेगा, इसमें निम्न शामिल हैं:

व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं के संदर्भ में उपलब्ध सभी राज्य या केंद्र सरकार की योजनाओं को सूचीबद्ध करना, हालांकि कुछ को एसआईए रिपोर्ट के अनुबंध 9 के रूप में प्रदान किया गया है;

वित्तीय संस्थानों के संदर्भ में उपलब्ध वित्तीय संसाधन जो क्षेत्र के भीतर छोटे उद्यमों को शुरू करने के लिए टर्म क्रेडिट प्रदान करते हैं। ये वित्तीय स्रोत बैंकिंग या गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान हो सकते हैं।

माध्यमिक स्रोतों से जिले के आधार पर आकलन करना, जो कृषि-व्यवसाय या अन्य गतिविधियाँ जैसे ऑटोमोबाइल यांत्रिकी, टेलरिंग, मशीन यांत्रिकी, बढईगीरी, आशुलिपि, नर्स, कोल्ड स्टोरेज रखरखाव कौशल, परिवहन, बुक कीपिंग और अकाउंट्स, कोई अन्य कौशल या अर्ध-कौशल नौकरी के अवसर आदि के संदर्भ में विभिन्न आर्थिक अवसरों की क्षमता के लिए संभावित हैं

प्रत्येक परिवार में अवसरों का लाभ लेने के लिए उपलब्ध इच्छुक पुरुष या महिला दोनों की सूची बनाना;

पहचाने गये प्रभावित परिवार के सदस्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को सूचीबद्ध करना;

इस फंड को सीधे प्रभावित परिवार को देने के बजाय पुनर्वास और पुनर्स्थापन सहायता के भाग के रूप में प्रशिक्षण शुल्क के भुगतान के लिए परियोजना अधिकारियों के माध्यम से फंड की व्यवस्था करना;

स्थानीय लघु उद्यमों की स्थापना में रुचि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा ऋण लेने या चुकाने की क्षमता;

छोटे उद्यमों की स्थापना के लिए क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों द्वारा क्रेडिट लिंकेज और वापसी की शर्तों पर सहमति; और

कोई अन्य गतिविधियाँ जिसमें परियोजना के तहत आर्थिक अवसरों तक पहुँचने के लिए प्रभावित परिवारों को जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है।

इसी क्रम में जिले में उपलब्ध विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया जाएगा और उसके अनुसार उपयुक्त उपलब्ध कार्यक्रम में प्रभावित परिवार के परिवार के एक सदस्य को समायोजित करने के लिए डिजाइन जाएगा जिन्हें आवश्यक आकलन सर्वे के दौरान पहचाना गया था।

#### **4.0 अतिरिक्त उपाय जो आवश्यक निकाय ने कहा है यह सामाजिक प्रभाव आकलन प्रक्रिया और सार्वजनिक सुनवाई के निष्कर्षों के जवाब में कार्य करेगा**

सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किए गए परामर्श से पता चला है कि लोगों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए अनुरोध किया, जिसमें ऑटो मैकेनिक, कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि शामिल थे। यह व्यक्तियों के कौशल पर आधारित हो सकता है और आर्थिक स्रोतों तक पहुंच प्रदान कर सकता है ताकि इन विशेषताओं से प्रशिक्षण पूरा होने के बाद लंबे समय तक कमाई की जा सके। इसका मतलब यह भी है कि क्षेत्र में मांग के आधार पर स्थानीय निर्भरता पर सिलाई करने या ऑटो मैकेनिक की दुकानों के ऐसे उद्यमों को शुरू करने धन के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ जुड़ने का साधन प्रदान करना।

एसआईए परामर्श के दौरान लोगों ने यह भी संकेत दिया है कि हम कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अनपढ़ हैं या हाई स्कूल छोड़ दिया था और अगर ऐसे बच्चों के लिए कुछ अकुशल या अर्ध-कुशल मजदूरी के काम को जोड़ा जा सकता है तो यह परिवारों के लिए उपयोगी होगा जिससे वे अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए कुछ आर्थिक स्रोत प्राप्त सकते हैं।

इसके अलावा जनसुनवाई से प्राप्त जानकारी को भी गतिविधि पूरी होने के बाद शामिल किया जाएगा और ऐसे सुझावों और तदनुसार एसआईएमपी को इन गतिविधियों के लिए आवश्यक बजट को शामिल करने के लिए तदनुसार रिपोर्ट अपडेट की गई।

#### 5.0 प्रत्येक गंभीरता को कम करने के उपायों और प्रत्येक गतिविधि के लिए समय सीमा और लागत के लिए जिम्मेदार संस्थागत संरचनाओं और प्रमुख व्यक्तियों का विवरण

गंभीरता को कम करने के हिस्से के रूप में प्रदान की जाने वाली मुख्य गतिविधियां हैं:

भूमि अधिग्रहण

पेड़ों पर प्रभाव

सामुदायिक विभाग की गतिविधियां

प्रभावित परिवारों के लोगों के लिए आय का पुनःस्थापन

टेबल S.1: प्रभाव बनाम गंभीरता को कम करना और कार्यान्वित के लिए जिम्मेदारी						
क्र.सं.	प्रभाव	गतिविधि	प्राथमिक जिम्मेदारी	माध्यमिक जिम्मेदारी और भूमिका	समय सीमा	रूपये में लागत
1.	प्राइवेट भूमि अधिग्रहण	स्वामित्व विवरणों को अंतिम रूप देना (अपडेट करना, आदि)	एसजेवीएन	ग्राम राजस्व विभाग और जिला कलेक्टर के साथ एनजीओ	3-4 साल 3-4	25,82,52,789.00
2a.	प्रभावित पेड़ - प्राइवेट	श्रेणी के अनुसार प्रभावित पेड़ों की संख्या का अंतिम रूप देना- फल देने वाले	एसजेवीएन	एनजीओ और एसजेवीएन के माध्यम से मूल्यांकन और भुगतान के लिए उद्यान-विज्ञान विभाग	पेड़ काटने के लिए माना जाने वाला वर्ष का फल देने की अवधि से 06-12 महीने ध्यान में रखते हुए	58,70,000.00
3.	सामुदायिक संसाधन प्रभावित	आरटीएफसीटीएलएआरआरए 2013 तीसरी अनुसूची के अनुसार सामुदायिक विभाग कार्य करता है	एसजेवीएन	एनजीओ के साथ एसजेवीएन	2 साल	38,00,000.00
4.	आजीविका या आय स्रोतों का क्षति	आय की पुनःस्थापन गतिविधियों और वित्तीय संयोजन प्रदान करना	एसजेवीएन	एसजेवीएन के साथ एनजीओ	18 महीने	10,00,000.00